Wednesday, July 30, 1975
Sravana 8, 1897 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

(FIFTH SERIES)

Vol. LIII

[*July, 21 to Aug. 03, 1975/Asadha 30 to Sravana 10 Saka*]

Fourteenth Session, 1975/1897 (Saka)

(Vol. LIII contains Nos. 1 - 10)

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

CONTENTS

No. 8—*Wednesday, July* 30, 1975/*Sravana* 8, 1897 (*Saka*)

	COLUMNS
Papers laid on the Table	1—3
Messages from Rajya Sabha	3
Statement *re.* Sittings of the House Shri K. Raghu Ramaiah	4
Banking Service Commission Bill Motion to Consider	
Shri Darbara Singh	4—12
Shri Md. Jamilurrahman	12—32
Shri Aravind Bala Pajanor	33—37
Shri C. M. Stephen	37—42
Shri Ramavatar Shastri	42—48
Shri Raja Kulkarni	48—52
Shri Shyam Sunder Mohapatra	52—57
Shri S. M. Banerjee	57—61
Shri P. K. Ghosh	61—64
Shri Kartik Oraon	64—70
Shri D. Basumatari	70—73
Prof. Narain Chand Parashar	73—82
Shri Ram Hedaoo	82—85
Shrimati Sushila Rohatgi	85—93
Clauses 2 to 33 and 1	93—100
Motion to pass, as amended	100
Employees' State Insurance (Amendment) Bill Motion to consider, as passed by Rajya Sabha	101—53
Shri Raghunatha Reddy	101—104, 147—153
Dr. Ranen Sen	104—10
Shri Ram Singh Bhai	110—20
Shri B. R. Shukla	120—23
Shri C. M. Stephen	123—28
Shri Ramavatar Shastri	129—32
Shri Raja Kulkarni	132—35
Shri N. K. Sanghi	135—39
Dr. Kailas	139—43
Shri Amarnath Vidyalankar	143—47

COLUMNS

Clauses 2 to 9 and 1 153

Motion to pass 153

Telegraph Wires (Unlawful Possession) Amendment Bill

Motion to consider, as passed by Rajya Sabha . . . .

Dr. Shanker Dayal Sharma . . . . . 154—56, 185—95
Shri B.S. Bhaura . . . . . 156—60
Shri Vayalar Ravi . . . . . 160—65
Shri K. Mayathevar . . . . . 165—68
Shri Shivnath Singh . . . . . 168—71
Shri Ram Hedaoo . . . . . 171—73
Shri D. N. Tiwary . . . . . 173—76
Shri K. M. 'Madhukar' . . . . . 176—78
Shri Giridhar Gomango . . . . . 179—80
Shri Dhamankar . . . . . 180—81
Shri Nageshwar Dwivedi . . . . . 181—83
Shri Panna Lal Barupal . . . . . 183—85

Clauses 2 to 6 and 1 . . . . . 195—201

Motion to pass, as amended 202

LOK SABHA

Wednesday, July 30, 1975/Sravana 8, 1897 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

PAPERS LAID ON THE TABLE

"CURRENT ECONOMIC SITUATION: A REVIEW"

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI C. SUBRAMANIAM): I beg to lay on the Table a document entitled "Current Economic Situation. A Review"—(Hindi and English versions) [*Placed in Library. See* No. LT-9896/75.]

RICHARDSON AND CRUDDAS LTD. (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKING) RULES, 1974

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI PRABHUDAS PATEL): On behalf of Shri A. C. George, I beg to lay on the Table a statement (Hindi and English versions) giving reasons for delay in laying the Richardson and Cruddas Limited (Acquisition and Transfer of Undertaking) Rules, 1974 published in Notification No. S.O. 147(E), in Gazette of India dated the 20th March, 1975. [*Placed in Library. See* No. LT-9897/75.]

REPORT ON THE WORKING OF DEPOSIT INSURANCE CORPORATION, BOMBAY, NOTIFICATION *re.* SPECIAL DEPOSIT SCHEME AND FOREIGN EXCHANGE REGULATION (AMENDMENT) RULES

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI): I beg to lay on the Table:—

(1) A copy of the Report (Hindi and English versions) on the working of the Deposit Insurance Corporation, Bombay, for the year ended the 31st December, 1974 along with the Audited Accounts, under sub-section (2) of section 32 of the Deposit Insurance Corporation Act, 1961. [*Placed in Library. See* No. LT-9898/75.]

(2) A copy of Notification No. F.16(1)-20/75, (Hindi and English versions) published in Gazette of India, dated the 30th June, 1975 regarding introduction of a Special Deposit Scheme for the benefit of non-Government provident, superannuation and gratuity funds. [*Placed in Library. See* No. LT-9899/75.]

(3) A copy of the Foreign Exchange Regulation (Amendment) Rules, 1974 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 663, in Gazette of India, dated the 31st May, 1975, under sub-section (1) of section 79 of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973. [*Placed in Library. See* No. LT-9900/75.]

ANNUAL REPORT AND AUDITED ACCOUNTS OF HIMACHAL PRADESH AGRO-INDUSTRIES CORPORATION, LTD., SIMLA

SHRI PRABHUDAS PATEL: I beg to lay on the Table a copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Himachal Pradesh Agro-Industries Corporation Limited, Simla, for the year 1973-74 along with the Audited Accounts, under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956. [*Placed in Library. See* No. LT-9901/75.]

11.12 hrs.

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report the following messages received from the Secretary-General of Rajya Sabha:

(i) "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Finance (Amendment) Bill, 1975, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 25th July, 1975, and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

(ii) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha, at its sitting held on the 29th July, 1975, agreed without any amendment to the Maintenance of Internal Security (Amendment) Bill, 1975, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 25th July 1975."

11.14 hrs.

STATEMENT *RE.* SITTINGS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI K. RAGHU RAMAIAH): With your permission, I would like to announce that the sittings of the House will stand extended till Monday. As it is, it is scheduled to conclude on the 31st July, 1975. Thus, there will be a sitting on Friday, the 1st August and also on Monday, the 4th August.

11.15 hrs.

BANKING SERVICE COMMISSION BILL—*contd.*

MR. SPEAKER: We now take up further consideration of the Banking Service Commission Bill. Shri Darbara Singh was on his legs. He may continue his speech.

श्री दरबारा सिंह (होशियारपुर) : स्पीकर साहब, मैं कल अर्ज कर रहा था कि 22 बैंकों में अब तक जो स्टाफ है उस की स्कूटिनी होनी चाहिये । क्योंकि बैंकिंग कमीशन ने रिपोर्ट की है कि नान-मैट्रिकुलेट्स और ऐसे लोग जो क्वालिफाइड नहीं थे उन को भर्त्ती कर लिया गया । किसी का कोई रिश्तेदार है, कोई किसी का भाई है, किसी न किसी ढंग से उन को रख लिया गया । जाहिर है कि ऐसे लोगों की ऐफिशियेंसी अच्छी नहीं हो सकती । पिछली जो रिपोर्टस ले की गई हैं उन में बताया गया है कि इन बैंकों में 88 लाख रु० का लैस प्रौफिट हुआ है । इस की बजह यह है कि एफीशियेंसी नहीं रही है और ऐसे लोग भर्त्ती किये गये जो क्वालिफाइड नहीं थे । फैसला किया गया है कि नये ग्रैजुएट्स, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स इंजीनियर्स और टेक्नीकल आदमी लिये, जायेंगे । बड़ी अच्छी बात है । लाखों की भर्त्ती होती है इन बैंकों में । कई बैंक वक्त पर पता नहीं देते । अब आप ने कहा है कि 25

परसेंट हो तो बता दें, रेगुलर बताते रहें। लेकिन भर्ती अब उन के जिम्मे नहीं रही है, बल्कि कमीशन करेगा। लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं कि दूसरे जो बैंक हैं क्या उन के बारे में आपने कभी सोचा कि उन की भर्ती कैसे हो रही है। अपनी मर्जी के आदमी रखते हैं, जो क्वालिफिकेशन्स आप ने रखी है उन से कम क्वालिफिकेशन के लोग भर्ती कर रहे हैं। कल को अगर उन को नेशनेलाइज करना होगा तो ऐसा इन-एफिशियेंट स्टाफ मिलेगा कि जिस का कोई हिसाब नही है। इसलिये आप क्यों नहीं उस को अपने परव्यू में लेते ताकि सभी बैंकों की भर्ती बैंकिंग कमीशन के जरिये हो जिस से उन की निस्वती बराबर हो।

आप ने कहा है कि 15 परसेंट शेड्यूल्ड कास्ट्स और साढे 7 परसेंट शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों का जगह दी जायेगी। मुझे पता नहीं यह कहा तक पूरा होगा, क्योंकि क्राइटेरिया जो आप ने रखा है, जो कमीशन की रिपोर्ट है उस मे कहा गया है कि कोशिश करनी चाहिये कि मैनेजर ऐसा हो जो लोकली अच्छा हो और सब को जानता हो ताकि लोगों से पैसा अट्रेक्ट कर सके। जो आप शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के लोगों को रखना चाहते हैं उन को आप अकोमोडेट करेंगे कि नही, क्योंकि अभी यह होता है कि उन की खाली जगहें खाली नही रखी जाती हैं, बल्कि उन को भर लिया जाता है यह कह कर कि सूटेबिल आदमी नहीं मिले। अब ऐसी कोई बात न हो और यह बहाना कायम न रहे इस पर आप को ध्यान देना चाहिये।

एक रिकमन्डेशन यह भी है कि ऐग्रीकल्चर रीफाइनेंस कमीशन और ऐग्रीकल्चर फंड्स कमीशन को मिला कर एक करना चाहिये ताकि कोई कनफ्यूजन न रहे। जो रिपोर्ट लोक सभा में दी गई उस मे कहा गया कि 51.2 परसेंट नई शाखाये खोली हैं 1969 से ले कर अब तक दुगनी ब्रांचेज खोली गई हैं। बड़ी अच्छी बात है और इस का ऐक्सटेंशन 55.2 परसेंट देहात में हुआ है। लेकिन एक सिफारिश की तरफ आप की तवज्जह दिलाना चाहता हूं और वह यह कि प्राइमरी क्रैडिट सोसाइटीज के जिम्मे बहुत काम डाला है और साथ यह भी कहा है कि ऐग्रीकल्चर कोआपरेटिव सोसाइटीज को और तरजीह देनी चाहिये जिस से वह कर्जा दे पाये और उन का ताल्लुक कर्माशियल बैंक्स से हो। आज का जो कोआपरेटिव सिस्टम है उस में रिवोल्यूशनाइज तरीके से काम करने की जरूरत हैं क्यो कि आज की जो सोसाइटीज हैं उन की खराबियां आप के सामने हैं। आप रिपोर्ट को अगर देखें तो ऐसा मालूम होगा कि इस का जो ढांचा है, वह पहले से गिरा हुआ है और जो डिफाल्टर्स है और जो वाइंड अप सोसाइटीज हैं, जिन का कर्जा रह गया है, उस को आप को राइट आफ करना पड़ता है। इसलिए मेरा कहना यह है कि आप कोआपरेटिव्ज को नये ढंग से ढाले और जो प्राइमरी सोसाइटीज है जिन के जिम्मे अपने कर्जा देना लगाया है, उनको मजबूत करे। यह भी उन्होंने कहा है कि जो कर्माशियल बैंक्स है वे कर्जा दे ताकि वे आगे कर्जा दे पाए। आप ऐसे बैंक्स बनाए जो उन को कर्जा दें। इस के लिए मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि जो आफिसर्स कमीशन ने भर्ती करने है, उन को अच्छे ढंग से चुने। मैं यह कहूंगा कि स्टेट्स मे रीजन्स मुकर्रर करने चाहिये और वहां पर आप को अच्छे बढ़िया आदमी रखने चाहिए जिस से वे देहातों से डिपोजिट्स को कलक्ट कर सकें। इस ढंग से आप नही करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है और आप के डिपोजिट्स शार्टेन होते जाएगे नीचे होते जाएगे। इस के बारे में जो एडवाइस देने वाले है कमीशन को, उस में इस का भी इन्द्राज करें।

एक चीज मैं यह भी अर्ज करना चाहता हू कि फारेन करंसी के बारे मे कुछ पहले से ज्यादा इन्क्रीमेंट हुआ है। जो लोग बाहर दूसरे मुल्कों में हैं और अपना रुपया पैसा यहां

[श्री दरबारा सिंह]

भेजते हैं, उन को सहूलियतें मिलनी चाहिए। वे छोटी इंडस्ट्री और दूसरी चीजों के लिए रुपया भेजते हैं।

मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि देहातों के लिए यह कहा गया है कि वहां पर लोगों को क्रेडिट मिलना चाहिए लेकिन वह ज्यादा इन्ट्रेस्ट पर देना चाहिए। क्यों, इसलिए कि वहां पर खर्च का मार्जिन ज्यादा आता है। उन का कहना है कि शहरों में कम इन्ट्रेस्ट पर और देहातो मे ज्यादा इन्ट्रेस्ट पर कर्जा देना चाहिए। मैं इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। यह जो रिपोर्ट में कहा गया है कि देहातवालों से इन्ट्रेस्ट ओवर एंड एबाव ज्यादा चार्ज करना चाहिए, जोकि आज किया जाता है उस से ज्यादा चार्ज किया जाए, यह बात मैं समझता हूं ठीक नहीं है। वे दबे हुए हैं और आप उन की इनडेटेडनेस को रिमूव करना चाहते हैं और आप कहते हैं कि उस को माफ कर दिया जाए और दूसरी तरफ आप नये इन्ट्रेस्ट की मारफत उन लोगों पर बोझ डालना चाहते हैं।

इस के बाद मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो सेल बना हुआ हैं, इस सेल ने दो तीन बातें की हैं कि जो यहां मोटर साइकिल लेने वाले हैं या जो ऐसी छोटी-मोटी चीजों के लिए कर्ज लेने वाले हैं उन को प्रायरटी दी जाए। मैं चाहूंगा कि छोटी इंडस्ट्रीज देहातों में लगाने के लिए और छोटे छोटे यूनिट्स वहां पर स्थापित करने के लिए भी उस को एडवाइस मिलनी चाहिए। रिकमेंडेशन में यह है कि मैनेजमेंट सोसाइटी ऐसी बनाए जो एडवाइस देने वाली हों। वे भी आप को बनानी होंगी। अध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि पंजाब के लोग दुनिया भर में अपनी मेहनत और मजदूरी कर के पैसा कमाते हैं और उस में से बहुत सा रुपया इसलिए उन के पास रुका पड़ा हुआ है क्योंकि उस को इस्तेमाल करने के लिए ठीक ढंग से कोई एडवाइस नहीं मिल रही है। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपया वहां से आ सकता है। जैसे नजदीक के चार, पांच देहातों में चार चार बैंक खुले हुए हैं जोकि नेशनेलाइज्ड बैंक हैं। इस के अलावा और भी बैंक हैं और उन बैंकों में करोड़ों रुपये का सरमाया है, लेकिन वह जाता कहां है। वह सरमाया बम्बई और कलकत्ता जाता है और जो मीडियम और स्माल फार्मर्स हैं, जो मीडियम कर्जा या छोटा मोटा कर्जा लेने वाले स्माल फार्मर्स हैं, उन को उन बैंकों से कर्जा कम दिया जाता है। वह सरमाया इंडस्ट्री और कमर्शियल तौर पर लगता हैं और प्रोफिटएबिल इंस्टीट्यूशन्स में ज्यादा लगाया जाता है ताकि ज्यादा प्रोफिट मिल सके। इस का मतलब यह नहीं है कि आप उन छोटे लोगों के लिए इन्तजाम न करें। आज जो स्माल फार्मर्स हैं, जो कि प्रोडक्शन करते है, उन के लिए पैसे की कोई भी सहूलियत न मिले, ऐसी बात नहीं होनी चाहिये। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो प्रोडक्शन करने वाले लोग हैं उन को पैसा मिलना चाहिए। आज जो प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज हैं या एग्रीकल्चरल सोसाइटीज हैं, जो कि किसानों को कर्जा देती हैं, उन को पैसा दिया जाए। आज जो स्माल फार्मर्स हैं उन को शार्ट टर्म लोन की अजहद जरूरत है और उन को कर्जा मिलना चाहिए।

एक यह भी रिकमेंडेशन की गई है कि जहां दो फसलें खराब हो जाएं और वहां पर किसान डिफाल्टर हो, तो उस की रिकवरी फ्लेक्सिबिल होनी चाहिए। अगर बारिश लगातार नहीं होती है और दूसरी फसल बर्बाद हो जाती है, तो वहां पर कर्जा रिजिडली नहीं वसूल करना चाहिए बल्कि वह पेनेसिविल होना चाहिए।

एक बात यह अर्ज कहना चाहता हूं कि यह ओवरटाइम की बीमारी बैंकों में बहुत है। ऐसा कौनसा काम है, जिस को उन्हें दफ्तर के टाइम के बाद करना है। आप अन्दाजा लगाइए कि कितना ओवरटाइम सारे दफ्तरों में दिया जाता है। जब बजट तैयार किया जाता

है जो जो नीचे के सुपरिन्टेंडेंट होते हैं दफ्तरों में वे उस वक्त उस को तैयार करना शुरु करते हैं जब बिल्कुल नजदीक बजट का समय आजाता है और पांच, पांच और सात सात घंटे ओवरटाइम के लगा लेते हैं । इस तरह से हर जगह यह बीमारी है और यह बडी क्रोनिक हो गई है । हर महकमे में यह चली गई है । इस इंस्टीट्यूशन में जहां आप लाखो लोग भर्ती करते हैं वहां पर अगर कोई 10 बजे से 5 बजे तक आफिस टाइम में अपना काम पूरा न करे, तो उस की एकाउन्टेबिलिटी होनी चाहिए । यह देखना चाहिए कि वह काम करता है या नही और अगर नही करता है तो उस को सजा मिलनी चाहिए । होता क्या है कि पाच बजे तक तो काम होता नही है और उस के बाद काम कर के चार, चार पांच पाच घंटे ओवरटाइम के बना लिये जाते है । यह सब बद होना चाहिए । फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा था कि आज एक चपरासी की तनखाह जो है वह बडे बडे अफसरों से ज्यादा हो गई है क्योंकि वह ओवरटाइम कमाता है । यह ओवरटाइम की बीमारी आप बिल्कुल हटा दीजिए क्योंकि ब्योरोक्रेसी के टैंटेकल्स इतने फैल गये हैं, इतने बडे भारी बोझल हो गये हैं और स्टाफ इतना ज्यादा हो गया है कि इस मे कमी करने की जरूरत है । बजाए कम करने के आप उन को ओवर-टाइम देते है । मेरा कहना यह है कि आप इस ओवरटाइम को यक-कलम खत्म कर दीजिए ताकि लोगों को सहूलियते हम दे सकें और उन को राहत मिल सके ।

जैसा कि मैं पहले कह चुका हू, छोटे लोगों को जैसे कि कारपेन्टर्स है, आर्टीशन्स हैं, उन को कर्जे की सहूलियतें मिलनी चाहिए और आपने भी कहा है कि वे सहूलियतें उन को मिलेंगी और एक बैंक ने—सेंट्रल बैंक आफ इंडिया—यह बात शुरू की है और उन्होंने कहा है कि हम इस सहूलियत को और बढ़ाने के लिए तैयार हैं ।

स्लम्स क्लियरेंस स्कीम्स में लोग, बहुत अच्छी बात है । स्लम क्लियरेंस टी०बी पर भी दिखलाया जाता है लेकिन मैं यह देखता हूं कि स्लम क्लियरेंस एक तरफ खत्म होता है तो दूसरी तरफ वह शुरु हो जाता है । दिल्ली मे ऐसा वातावरण बना है कि एक जगह से स्लम्स खत्म किये जाते हैं तो दूसरी तरफ नये स्लम्स कायम हो जाते हैं । जिन को एलाटमेंट होता है तो वह एलाटमेंट दूसरे लोगों को बेच देते है और बड़े आदमी उन को ले लेते हैं । इसलिए मेरा कहना यह है कि इस पर बंदिश होनी चाहिए कि जिस आदमी के नाम पर एलाटमेंट होता है, वह दूसरे को नहीं बेच सकता । इस प्राब्लम को भी आप को देखना चाहिए ।

अब मै बैंकों में कर्मचारियों की ट्रेनिंग के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । वहां पर लोग नान-मैट्रिक है और उन के ही रिश्तेदार वहां बैंकों में लग जाते हैं । इस तरह से वहां पर काम करने वाले लोगों के आदमियों को ही रख लिया जाता है और कोई इम्तिहान नहीं होता है । इसलिए उन में एफीशियेन्सी नहीं है और यही कारण है कि 88 लाख रुपये का घाटा दिखलाया है । उन लोगों के लिए कोई ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए और उस के बाद ही उन को रखना चाहिए । उन को यह पता नहीं है कि सर्विस कैसे की जाती है । बस बैंक मे आ कर बैठ गये । उन को चैक का पता नहीं है और सिलिप का पता नहीं है । उन को डिपोजिटस का पता नहीं है । इसलिए आप को इस को ठीक करना होगा ।

उन बेचारों को कुछ पता नहीं होता है । वे किसी दूसरे आदमी से लिखवाते है, जो चाहे गलत लिखे या सही लिखे, और चाहे खुद ही रुपया निकलवा कर ले जाये। ऐसे फ्राड भी होते हैं । अभी हाल ही मे लन्दन में इस किस्म का जो फ्राड हुआ था, उस के लिए गवर्नमेंट ने 22 लाख रुपया खर्च किया है । ऐसे फ्राड आगे भी होते रहेंगे क्योंकि वे काम

[श्री दरबारा सिंह]

उन लोगों के सुपुर्द हैं, जो बहुत पढ़े-लिखे हैं थोड़े पढ़े-लिखे और देहात के लोगों के लिए कोई इन्तजाम नहीं किया गया है कि वे रिजनल लैंग्वेज में कागज पेश कर के बैंक में अपना काम करवा लें।

गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि बैंकों के मुख्तलिफ कारोबार को रिजनल लैंग्वेजिज में करने का काम तीन साल में मुकम्मल हो जायेगा । अगर यह काम तीन साल में पूरा हो जाये, तो यह एक बड़ी अच्छी बात होगी ।

यह जरूरी है कि रूरल एरियाज की तरफ ज्यादा तवज्जुह दी जाये, क्योंकि इस मुल्क में 80 फ़ीसदी लोग देहात में बसने वाले हैं । गवर्नमेंट कामर्शल बैंक्स, प्राइमरी क्रेडिट सोसायटीज और को-आपरेटिव सोसायटीज को मजबूत करे, लेकिन ग़रीब लोगों को कर्जा जरूर मिलना चाहिए । जो प्रोड्यूस करता है, जो स्माल-स्केल इंडस्ट्री में काम करता है, उस को कर्जा मिलना चाहिए, न कि बड़े बड़े लोगों को, जिन के पास पहले ही से ब्लैक का करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है । इस के अलावा अगर गवर्नमेंट डामानटाइजेशन का कदम उठाये, तो मुल्क की फ़िनांशल पोजीशन जरूर अच्छी होगी । गवर्नमेंट को आज, कल या परसों ये स्टेप्स लेने ही होंगे ।

प्राइम मिनिस्टर के 20-पायंट प्रोग्राम में गरीबों के लिए एक गुंजाइश पैदा की है । लेकिन उस का इम्प्लीमेंटेशन कौन करने वाले हैं ? हम नहीं करने वाले हैं । वैसे, अगर हम से करवाया जायेगा, तो हम करेंगे, लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने यह काम करना है, और वह अभी तक वैसी की वैसी है । सिवाये इस के कि वे लोग वक्त पर दफ़्तर में आ जायें, उन की दिमांगी कैफ़ियत नहीं बदली है । जो लोग काम नहीं करते हैं, उन को शंट आउट करना होगा । बैंक फ़िनांस मिनिस्ट्री के मातहत हैं । मिनिस्टर साहब कम से कम वहां से ऐसे लोगों को निकाल बाहर करें, जो काम नहीं करते हैं । अभी तक दो बैंकों के हैड्ज़ को निकाला गया है । नये आदमियों को मौका देना चाहिए । एक्सपीरियंस के अलावा इनटेक्रिटी को भी देखना चाहिए कि आया कोई शक्स ग़रीबों का उत्थान करने के बारे में कमिटिड है या नहीं । अभी तक हम ने ऐसी बात नहीं देखी है । बड़ी बड़ी जगहों पर जो लोग बैठे हैं, उन को यह पता नहीं है कि ग़रीब कैसे पिस रहे हैं और कैसे उन की इमदाद करनी चाहिए । नीचे की सतह पर ऐसे लोगों को रखना चाहिए, जो कमिटिड हों, ताकि काम ठीक तरह से चल सके ।

आख़िर में मैं यह कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट को मल्टीपर्पज एजेन्सीज कायम करनी चाहिए, जो इंडस्ट्री, फ़ार्मिन्ग और कर्जों के बारे में सलाह दे सकें । इस बिल के जरिये जो कमीशन बनाया जा रहा है, मैं उस को पूरी तरह सपोर्ट करता हूं ।

श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान (किशनगंज) : मोहतरिम स्पीकर साहब, इस में कोई शुबहा नहीं कि जो बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल जेरे-ग़ौर है, वह एक अच्छा कदम है । मैं उस के हक और मुआफ़िकत में हूं । इस बिल को देर से लाने की वजह से तालेम-याफ्ता और काबिल लड़कों को जो नुकसान हुआ है, इस बिल में उस की तलाफ़ी की गुंजाइश नहीं है । बैंकों को कोमियाने के बाद इन में जो बहालियां हुई हैं, अगर आप उन की लिस्ट को देखें, तो साफ़ जाहिर होगा कि सिर्फ़ बैंकों के बड़े बड़े अफ़सरों और ऊंचे ओहदेदारों के रिश्तेदारों और रिश्तेदार-दर-रिश्तेदारों की ही बहालियात हो पाई हैं । इस तरह बैंकों के नेशनलाइजेशन का मकसद इस दौरान में कटअन फ़ौत हो चुका है । बहरहाल, देर आयद दुरुस्त आयद ।

मौजूदा बिल के कुछ क्लाजिज पर मुझे सख्त एतराज है और मैं चाहूंगा कि सरकार इस सिलसिले में तरमीमात लाये, ताकि जिस मकसद के लिए यह बिल लाया गया है, उस से देश को सही मानो में कुछ फ़ायदा हो सके।

अफ़सरशाही का जो चक्कर अंग्रेजों के वक्त से ले कर आज तक जोर-शोर से चल रहा है, हम उसको कम नही कर पाये हैं, बल्कि उसके चगुल मजबूत से मजबूततर हो रहे है। मेरा सब से पहला एतराज क्लाज 3(4) के बारे में है, जिस में कहा गया है :

"The Commission shall have regional offices in such State or group of States as the Commission may, with the previous approval of the Central Government, determine and no such regional office shall be abolished without the previous approval of the Central Government."

जिस तरह आजादी के 27 साल बाद भी भारत के मुखतलिफ हिस्सों में नदियों के पानी का कजिया अभी तक चल रहा है, उसी तरह इस क्लाज के जरिये रिजनल आफिसिज के एस्टाब्लिशमेंट के बारे में झगड़ा, तनाव और कजिया पैदा होने की खुली छूट दी जा रही है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस के बजाय मुल्क को दस यूनिट्स में बांट दिया जाय, और पिछडे हुए हिस्सों, मीडियम लैवल तक डेवेलप्ड हिस्सों और मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड हिस्सों की तीन कैटेगरीज बना दी जायें।

इस क्लाज को पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यह आगे आने वाले फ़ित्न की जड़ है और आगे चल कर रिजनल आफ़िसिज को एस्टाब्लिश करने के बारे में झगड़ा होगा। इस से बेहतर यही है कि मिनिस्टर साहब अभी इस में तरमीम को मान लें, ताकि आगे चल कर तनाव पैदा न हो, और जिस मकसद के लिए यह बिल लाया गया है, वह पूरा हो सके।

बिहार भी बैकवर्ड स्टेट्स और एरियाज से बाहर नहीं है। आगे चल कर इस क्लाज के जरिये जो नुक्सान होने वाला है, मैं उस को अभी ऐप्रिहैंड कर रहा हूं। आगे आने वाला वक्त बतायेगा कि मेरी शंका और शुबहे में कितनी सदाकत है। अभी मौका है कि मिनिस्टर साहब इस पर गौर कर के इस में तरमीम करें।

इस बिल के क्लाज 4 के प्रोवाइजो पर भी मुझे सख्त एतराज है, जिस मे कहा गया है :

"Provided that as nearly as may be one-half of the members shall be persons who, on the date of their respective appointments, have had experience of not less than ten years in a banking company or in any public sector bank or Reserve Bank or in an institution wholly or substantially owned by the Reserve Bank or a public financial institution."

राजा साहब के मरने के बाद उन का बेटा ही राजा होगा। जम्हूरियत में इस की कतई गुंजाइश नही है। क्या हमारे यहां यूनिवर्सिटीज के प्रोफसर, इकानोमिस्ट और दीगर इकानोमिक एक्सपर्ट नहीं हैं ? जो बैंकों में काम कर चुके हैं, सिर्फ उन्ही को कमीशन के मेम्बर बनाने का प्राविजन रखने की क्या वजह है ? जैसा कि श्री दरबारा सिंह ने कहा है, और क्लाजिज में कमीशन की मेम्बरशिप को सिर्फ एक तबके के लिए मखसस कर दिया गया है। एक्सप्लेनेशन में कहा गया है कि सिर्फ छः कैटेगरीज को फिनांशल इंस्टीट्यूशन माना जायेगा और सिर्फ उन में काम करने वाले लोग ही मम्बरशिप के काबिल समझे गये हैं। मेरा ख़याल है कि इस

[श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान]

क्लाज को एमेंड करना चाहिये । मैं मोहतरमा वजीर साहब से कहूंगा कि आप इस में ऐसा प्रावीजन जरूर रखें कि जिस के जरिये एक्सपर्ट को रखा जाय, इकानामिक एक्सपर्टस को रखा जाय, यूनिवर्सिटी प्रोफ़ेसर्ज को रखा जाय, दूसरे पढ़े-लिखे लोगों को रखा जाय ।

एक बड़े मजे की बात इस में यह है कि आप ने शैडयूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राइब्स के लिये गुंजाइश रखी है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि मेम्बर्स की एप्वाइन्टमेंट में आपने ऐसी गुंजाइश क्यों नहीं रखी ? इस कमीशन के आठ मेम्बर्स होंगे, आप कम्पलसेरिली ऐसा प्रावीजन रखें कि इन आठ मेम्बर्स में से एक मेम्बर शैडयूल्ड कास्ट्स का होगा और दूसरा शैडयूल्ड ट्राइब्स का होगा । मोहतरिम स्पीकर साहब, आप मुझ से एग्री करेंगे—कांस्टीट्यूशन में इन लोगों के लिये गारन्टी की गई है, उन के लिये परसेन्टेज दी हुई है, हम लोग भी यहां हर रोज इस के बारे में बोलते रहते हैं—लेकिन इस का क्या असर पड़ता है । कांस्टीचूशन में ऐसा प्रावीजन होने की बिना पर हम इन के लिये कमिटेड है, लेकिन होता कुछ नही है । इस लिये मैं चाहता हूं कि इस कमीशन में भी एक आदमी शैडयूल्ड कास्ट्स का और एक आदमी शैडयूल्ड ट्राइब्स का रखा जाय और बाई-रोटेशन इस कमीशन का चेयरमैन शैडयूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राइब्स का भी हो । मोहतरिम स्पीकर साहब, आप के जरिये सरकार से मेरी गुजारिश है कि इस प्रावीजो को ला कर आप ने इस के दायरे को बहुत महदूद कर दिया है । इस का मतलब यही है कि जमींदार मरेगा तो उस का बेटा जमींदार होगा, वह मरेगा तो फ़िर उस का बेटा जमींदार होगा । सैकुलर स्टेट में ऐसी गुंजाइश नहीं होनी चाहिये । हम लोग अपने अवाम से, अपने मुल्क से, इस के लिये कमिटेड हैं, इसलिये हमारे अवाम की बहबूदी के लिये ऐसी गुंजाइश होनी चाहिये जिस में अवाम और मुल्क का फ़ायदा हो ।

तीसरी चीज—जिस पर मुझे सख्त ऐतराज है—पेज 3 पर क्लाज 4 का सब क्लाज 3 में कहा गया है—The Chairman or any member shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of sixty-five years. यह क्या मज़ाक है—मैं चाहता हूं कि आप इस को तीन बरस कीजिये । एक तरफ आप कहते है कि लोग 55 साल में रिटायर हों, दूसरी तरफ कोरामीन का इंजेक्शन दे कर उन की जिन्दगी को 65 साल तक पहुंचाना चाहते हैं । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि उन की बहाली सिर्फ़ 3 बरस के लिये होनी चाहिये और उन की ऐज को 65 से घटा कर 55 साल की जाय, ताकि सर्विसिज के दूसरे लोगों को भी आगे आने का मौका मिल सके ।

इस में मेम्बर्ज की क्वालिफ़िकेशन का जो प्रावीजो रखा गया है—आप जरा उस को भी मुलाहिजा फ़रमाइये, इस के बारे मे मुझे एतराज है, सरकार को इस के बारे मे अमेण्डमेंट लाना चाहिये । मैं पूछना चाहता हूं कि पब्लिक का नुमाइन्दा इस का मेम्बर क्यों नही हो सकता ? एक खास किस्म का तबका ही इस का मेम्बर क्यों हो ? पार्लिया-मेंट के मेम्बर, असेम्बली के मेम्बर, यूनि-वर्सिटी प्रोफेसर, पी०एच०डी०, ऐसे लोग भी इस के मेम्बर बनाये जायें । आज वक्त बदल चुका है और जितनी तेजी से बदल रहा है, भारत जितनी तेजी से तरक्की कर रहा है—उस को मद्देनजर रखते हुए वक्त के साथ चलने के लिये कानून में भी तबदीली होनी चाहिये । जब तक कानून अवाम की राय के मुताबिक नहीं होगा, वह अधूरा रह जायगा । उस का सही तौर से इम्पलीमेंटेशन नहीं होगा,

क्योंकि आज जो इम्पलीमेन्टेशन करने वाले हैं, उन को आप भी देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूं, उन का अन्दाजा आप को भी है और मुझे भी है...

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उन का हश्र भी यही होगा ।

श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान : इसीलिये तो याद दिला रहा हू कि वैसा हश्र न हो । आप इस मे ऐसी अमेण्डमेन्ट्स लाइये जिस से यह अवाम के लिये बन सके और अवाम को फ़ायदा हो ।

आप इस के क्लाज 6 को देखिये—इस को पढने से ऐसा मालूम होता है कि इस बिल को ड्राफ्ट करते वक्त इस का कतई ख्याल नही रखा गया है । इस में जो बात रखी गईहै, मैं उसे को आप की इजाजत से पढ़ना चाहता हूं—'6(1) The Central Government may remove from the office the Chairman or any member.....' यह बिलकुल स्टीरिओ-टाइप चीज है । मैं पूछना चाहता हूं कि इस मे ऐसा क्लाज क्यो नही रखा गया कि सब ऐसे लोग जिन का पोलिटीकल एफ़िलिएशन ऐसी जमायतों के साथ हो, जिस की रस्सी दूसरे मुल्क में है, वहां से रस्सी खीचते है तो यहां घन्टी बजने लगती है— ऐसे लोगों को इस में नही रखा जायगा । मैं एक मिसाल देना चाहता हूं—आप के ही वित्त विभाग मे एक साहब हैं, जो एक बोर्ड के चेयरमैन हैं, जिन का ताल्लुक आनन्द मार्ग से है । पिछले साल उन की बेगम ने डेढ लाख रुपया जमा कर के आनन्द मार्ग को दिया है । मेरे पास सुबूत है, मैं कोई जुबानी बात नही कह रहा हूं, आप के वित्त विभाग में ऐसा हुआ है—

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI): Mr. Speaker, Sir, with your permission, I would like to say that instead of taking the names of the officers who are not in a position to defend themselves here, I would request the hon. Member that, if he has any specific allegations, he may send them with all the particulars to me. I shall certainly look into them.

श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान : मैंने नाम नहीं लिया है ।

अध्यक्ष महोदय : मोहतरिम, आप जरा मेरी तरफ भी तवज्जह फरमाइये । यह जो आप का जाब्ता है, इस में लिखा हुआ है कि जब किसी की तरफ कोई ऐसा इल्जाम लगाना हो तो उस का नाम पहले से सदर को दिया जाता है ।

श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान : मैंने नाम नही लिया है । मैंने कहा है कि एक अफ़सर हैं, जो चेयरमैन हैं ।

अध्यक्ष महोदय : फ़िर मोहतरिमा क्या कह रही हैं, मुझे समझ नहीं आया है ।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : मोहतरिमा ने कहा है कि नाम भेजिये, लिख कर भेजिये ।

अध्यक्ष महोदय : फिर तो कोई झगडा नही है—बात साफ है ।

श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान : मैं यही अर्ज कर रहा था कि क्लाज 6 में एक क्लाज ऐसा होना चाहिये कि ऐसे आदमियों की बहाली मेम्बरशिप के लिये या चेयरमैनशिप के लिये नही होगी जिन का एफिलिएशन किसी ऐसी जमायत के साथ होगा, जो एन्टीनेशनल एक्टिविटीज (anti-national activities) में हिस्सा लेती होगी । यह ध्यान में रखने की चीज है—मोहतरिम स्पीकर साहब, आज

[श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान]

कल आप भी शान्ति में हैं और अल्लाह के फज्ल से हम लोग भी शान्ति में चल रहे हैं.....

अध्यक्ष महोदय : मैं तो कभी शान्ति में नहीं रहा हूं, यह तो इत्तिफाक की बात है कि शान्ति मिल रही है ।

श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान : जी हां यह इत्तिफाक की बात है कि हम लोग भी शान्ति से अपनी बात सुना रहे हैं ।

इसी सिलसिले की एक कड़ी में और अर्ज करना चाहता हूं—आप इस को लागू करेंगे तो देश को फायदा होगा, देश तबाह होने से बचेगा । देश में कुछ लोग चाहते हैं कि देश के टुकड़े-टुकड़े हो जाएं, देश की अवाम तबाह हो जाये, देश खत्म हो जाय, लेकिन इस तरह की कार्यवाही से देश को बचाया जा सकेगा, हमारा देश सुरक्षित रह सकेगा । लेकिन ऐसे लोगों को आप को स्क्रूटिनाइज करना होगा, उन को हटाना होगा, जो आप की कुर्सी पर बैठ कर अवाम की गर्दन को उड़ा रहे हैं, देशद्रोहीपन का सुबूत और मजाहरा खुले कर रहे हैं ।

इसी तरह से क्लाज 8 के बारे में मेरा यह आब्जैक्शन है कि इस में ऐसे लोगों को लिया जाय जो बैंकिंग इस्टीचूशन्स की तरक्की के लिये कमिटेड हों, जो अवाम की भलाई कर सकें । बैंकों के नेशनलाइजेशन का मतलब यही था कि हम अवाम को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचा सकें । पहले कुछ पूंजीपति आपस में मिल कर बैंकों से फायदा उठा लेते थे अवाम को बैंकों से कोई फायदा नहीं मिलता था । बैंकों के नेशनलाइजेशन का मकसद यह था कि मुल्क की 60 करोड़ जनता जो गांवों में रहती है, उस को फायदा हो, जैसे स्माल फार्मर्स हैं, स्माल इण्डस्ट्रीज वाले लोग हैं, उन को फायदा हो, वे अपनी इण्डस्ट्रीज गांवों में लगायें ताकि गांवों की जनता को एम्पलायमेन्ट मिल सके ।

आखिर में, मैं यही अर्ज करूंगा कि क्लाज 13 को बिल्कुल डिलीट किया जाना चाहिये ।

मेरी आप के जरिये दरख्वास्त है कि क्लाज 13 को बिल्कुल डिलीट किया जाना चाहिए । मैं बिल्कुल इसके हक में नहीं हूं । मैं आपकी जानकारी के लिए सिर्फ एक लाइन पढ़ना चाहता हूं :

"It shall not be necessary to consult the Commission in regard to the selection of a person—

(a) for appointment to a post in the clerical or allied cadre, on compassionate grounds (in pursuance of the scheme framed by a public sector bank in consultation with the Commission and with the previous sanction of the Central Government), of a dependent of an employee who had died while in the service of the public sector bank;"

इसी तरह से और क्लाजेज हैं । मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि इसके जरिए से आप एम्प्लाइज को खुली रस्सी दे रहे हैं कि जितना ही खींचो उतनी ही मजबत होती जायेगी । भारत में जितने कार्पोरेशन बने हैं, ऐसा मालूम होता है कि वे किसी को भी जवाबदेह नहीं हैं । न तो पार्लियामेंट के लिए वह जवाबदेह हैं और न अवाम के लिए जवाबदेह हैं हालांकि अवाम के लिए ही सारे कार्पोरेशन्स को बनाया गया है । फर्टिलाइजर कार्पोरेशन, इंडियन आयल कार्पोरेशन, सी ड कार्पोरेशन, जूट कार्पोरेशन—इनके बारे में जितना ही कम कहा जाये वही अच्छा है । इसलिए मेरी गुजारिश है कि इन बैंकों का जो सही मकसद है, अवाम के मफाद के लिए हों, यह बात उसूली तौर पर तय है तो इसको

अमल में भी लाना चाहिए । उसको लागू भी करना चाहिए । बैंक कुछ लोगों के लिए ही फायदेमन्द न होकर अवाम के लिए भी फायदेमन्द हों ।

इन सब बातों के साथ मैं आपका शुक्रगुजार हूं, मैं चाहता हूं सरकार मेरे सुझाव पर ध्यान दे, यह बिल अवाम का बिल बने, किसी खास तबके के लिए ही यह बिल बनकर न रह जाये ।

شری محمد جمیل الرحمان

(کشن گنج): محترم اسپیکر صاحب- اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بینکنگ سروسز کمیشن بل زیر غور ہے وہ ایک اچھا قدم ہے- میں اس کے حق اور موافقت میں ہوں- اس بل کو دیر سے لانے کی وجہ سے تعلیم یافتہ اور قابل لڑکوں کو جونقصان ہوا ہے- اس بل میں اس کی تلافی کی گنجائش نہیں ہے- بینکوں کو قومیانے کے بعد انہیں جو بحالیاں ہوئی ہیں- اگر آپ ان کی لسٹ کو دیکھیں تو صاف ظاہر ہوگا کہ صرف بینکوں کے بڑے بڑے افسروں اور ان کے رشتے داروں اور رشتیدار- اور رشتیداروں کی ہی بحالی ہو پائی ہے- اس طرح بنکوں کے نیشنلائزیشن کا مقصد اس دوران میں قطعاً فوت ہو گیا- بحر حال دیر آید درست آید-

موجودہ بل کے کچھ کلاز پر مجھے سخت اعتراض ہے- اور میں چاہونگا

کہ سرکار اس سلسلہ میں ترمیمات لائے - تاکہ جس مقصد کے لئے یہ بل لایا گیا ہے اس سے دیش کو صحیح معنوں میں کچھ فائدہ ہو سکے-

افسر شاہی کا جو چکر انگریزوں کے وقت سے لیکر آج تک زور شور سے چل رہا ہے- ہم اس کو کم نہیں کر پائے ہیں- بلکہ ان کے چنگل مظبوط سے مظبوط تر ہورہے ہیں- میرا سب سے پہلا اعتراض کلاز ۳ (۴) کے بارے میں ہے- جس میں کہا گیا ہے-

"The Commission shall have regional offices in such State or group of States as the Commission may, with the previous approval of the Central Government, determine and no such regional office shall be abolished without the previous approval of the Central Government."

جس طرح آزادی کے ۲۷ سال بعد بھی بھارت کے مختلف حصوں میں ندیوں کے پانی کا قصہ ابھی تک چل رہا ہے- اس طرح اس کلاز کے ذریعہ ریجنل آفیسز کے ایسٹیبلشمینٹ کے بارے میں چھکوا تناؤ اور قضیہ پیدا ہونے کی کھلی چھوٹ دی جا رہی ہے- میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی بجائے ملک کو دس یونٹس میں بانٹ دیا جائے اور بچھڑے ہوئے حصوں- مڈیم لیول تک ڈویلپ حصوں اور موسٹ انڈسٹریل لائزڈ حصوں کی تین کیٹگریز بنادی جائیں -

[شری محمد جمیل الرحمان]

اس کلاز کو پڑھنے کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ وہ آنے والے فتنوں کی جڑ ہے- اور آگے چل کر ریجنل افسر کو اسٹیبلش کرنے کے بارے میں جھگڑا ہوگا- اس سے بہتر یہی ہے کہ منسٹر صاحب ابھی اس میں ترمیم کو مان لیں- تو آگے چل کر اس میں تناو پیدا نہ ہو- اور جس مقصد کے لیے یہ بل لایا گیا ہے وہ پورا ہو سکے-

بہار بھی بیکورڈ سٹیٹ اور ایریا سے باہر نہیں ہے- آگے چل کر اس کلاز کے ذریعہ جو نقصان بہار کو ہونے والا ہے - میں اس کو ایپریشیئیٹ کر رہا ہوں- آگے آنے والا وقت بتلائیگا کہ میری شنکا اور شبہہ میں کتنی صداقت ہے- ابھی موقعہ ہے کہ منسٹر صاحب اس پر غور کرکے اس میں ترمیم کریں- اس بل کے کلاز ۲ کے پروویژن پر بھی مجھے سخت اعتراض ہے- جس میں کہا گیا ہے :

"Provided that as nearly as may be one half of the members shall be persons who, on the date of their respective appointments, have had experience of not less than ten years in a banking company or in any public sector bank or Reserve Bank or in an institution wholly or substantially owned by the Reserve Bank or a public financial institution."

راجہ صاحب کے کرنے کے بعد ان کا بیٹا ہی راجہ ہوگا- جمہوریت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے- کہنا

ہمارے یہاں یونیورسٹی کے پروفیسر اکنومسٹ اور دیگر اکونومک ایکسپرٹ نہیں ہیں- جو صرف بینکوں میں کام کر چکے ہیں صرف انہی کو کمیشن کے ممبر بنانے کا پروویژن رکھنے کی کیا وجہ ہے- جیسا کہ شری دربارہ سنگھ نے کہا ہے - اور کلازز میں کمیشن کی ممبرشپ کو صرف ایک طبقے کے لئے مخصوص کردیا گیا ہے- ایکسپلینیشن میں کہا گیا ہے کہ صرف چھ کیٹیگریز کو فائنانشل انسٹیٹیوشن مانا جائیگا اور صرف ان میں کام کرنے والے لوگ ہی ممبرشپ کے قابل سمجھے جائینگے - میرا خیال ہے کہ اس کلاز کو امینڈ کرنا چاہئے -

میں محترمہ وزیر صاحب سے کہونگا کہ آپ اس میں ایسا پروویژن ضرور رکھیں کہ جس کے ذریعے ایکسپرٹ کو رکھا جائے - اکانومک ایکسپرٹ کو رکھے جائے - یونیورسٹی پروفیسرز کو رکھا جائے - دوسرے پڑھے لکھے لوگوں کو رکھا جائے -

ایک بڑے مزے کی بات اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے شڈولڈ کاسٹ اور شڈولڈ ٹرائبز کے لئے گنجائش رکھی ہے - لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ ممبرز کی اپائنٹمنٹ میں آپ نے ایسی گنجائش کیوں نہیں رکھی - اس کمیشن کے آٹھ ممبرز ہونگے - آپ

تیسری چیز جس پر مجھے سخت اعتراض ہے - پیج ۳ پر کلاز ۴ کا سب کلاز ۳ میں کہا گیا ہے - یہ کیا مذاق ہے - میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو تین برس کیجئے - ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ لوگ ۵۵ سال میں ریٹائر ہوں دوسری طرف کورامین کا انجیکشن دے کر ان کی زندگی کو ۶۵ سال تک پہنچانا چاہتے ہیں - میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی بحالی صرف ۳ برس کے لئے ہونی چاہئے - اور ان کی ایج کو ۶۵ سے گھٹا کو ۵۵ سال کی جائے تاکہ سروسز کے دوسرے لوگوں کو بھی آگے آنے کا موقع مل سکے -

اس میں ممبرز کی کوالیفیکیشن کا جو پروویزن رکھا گیا ہے - آپ ذرا اس کو بھی ملاحظہ فرمائیے - اس کے بارے میں مجھے اعتراض ہے - سرکار کو اس کے بارے میں امینڈمینٹ لانی چاہئے - میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پبلک کا نمائندہ اس کا ممبر کیوں نہیں ہو سکتا - ایک خاص قسم کا طبقہ ہی اس کا ممبر کیوں ہو - پارلیمنٹ کے ممبر - اسمبلی کے ممبر - یونیورسٹی پروفیسرز - پی ایچ ڈی ایسے لوگ بھی اس کے ممبر بنائے جائیں - آج وقت بدل چکا ہے - کمیشن میں ایسا پروویژن رکھیں کہ ان آٹھ ممبرز میں سے ایک ممبر شیڈولڈ کاسٹ کا ہوگا - اور دوسرا شیڈولڈ ٹرائب کا ہوگا - محترم سپیکر صاحب آپ مجھ سے ایگری ہونگے کہ کانسٹیٹیوشن میں ان لوگوں کے لئے گارنٹی دی گئی ہے - ان کے لئے پرسنٹیج دی ہوئی ہے - ہم لوگ بھی یہاں پر ہر روز اس کے بارے میں بولتے رہتے ہیں - لیکن اس کا کیا اثر پڑتا ہے - کانسٹیٹیوشن میں ایسا پروویزن ہونے کی بنا پر ہم اس کے لئے کموٹڈ ہیں - لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے - اس لئے میں چاہتا ہوں - کہ اس کمیشن میں بھی ایک آدمی شیڈولڈ کاسٹ کا اور ایک آدمی شیڈولڈ ٹرائب کا رکھا جائے اور بائی روٹیشن اس کمیشن کا چیئرمین شیڈولڈ کاسٹ اور شیڈولڈ ٹرائب کا بھی ہو - محترم سپیکر صاحب آپ کے ذریعے سرکار سے میری گذارش ہے کہ اس پروویژن کو لیکر آپ نے اسکے دائرے کو بہت محدود کر دیا ہے - اس کا مطلب یہی ہے کہ زمیندار مرے گا تو اس کا بیٹا زمیندار ہوگا - وہ مرے گا تو پھر اس کا بیٹا زمیندار ہوگا - سیکولر سٹیٹ میں ایسی گنجائش نہیں ہونی چاہئے - ہم لوگ اچھے عوام سے - اچھے ملک سے اس کے لئے کموٹڈ ہیں - اس لئے ہمارے عوام کی بہبودی کے لئے ایسی گنجائش ہونی چاہئے جس میں قوم اور ملک کا فائدہ ہو

[شری محمد جمیل الرحمان]

اور جتنی تیزی سے بدل رہا ہے - بھارت جتنی تیزی سے ترقی کر رہا ہے - اس کو مدنظر رکھتے ہوئے وقت کے ساتھ چلنے کے لئے قانون میں بھی تبدیلی لانی چاہئے - جب تک قانون عوام کی رائے کے مطابق نہیں ہوگا - وہ ادھورا رہ جائے گا - اس کا صحیح طور سے ایمپلیمینٹیشن نہیں ہوگا - کیونکہ آج جو ایمپلیمینٹیشن کرنے والے ہیں - ان کو آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور میں بھی دیکھ رہا ہوں - ان کا اندازہ آپ کو بھی ہے اور مجھ کو بھی ہے -

شری رام اوتار شاستری: ان کا حشر بھی یہی ہوگا -

شری محمد جمیل الرحمان : اس لئے تو یاد دلا رہا ہوں کہ ویسا حشر نہ ہو - آپ اس میں ایسی امینڈمینٹ لائیے - جس سے یہ عوام کے لئے بن سکے - اور عوام کو فائدہ ہو -

آپ اس کے کلاز 6 کو دیکھئے - اس کو پڑھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے - کہ اس بل کا ڈرافٹ کرتے وقت اس کا قطعی خیال نہیں رکھا گیا ہے - اس میں جو بات رکھی گئی ہے - میں اس کو آپ کی اجازت سے پڑھنا چاہتا ہوں -

The chairman or any member shall held office for a term of five years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of sixty-five years.

یہ بالکل سٹیریو ٹائپ چیز ہے - میں پوچھنا چاہتا ہوں - کہ اس میں ایسا کلاز کیوں نہیں رکھا گیا کہ سب ایسے لوگ جن کا پالیٹیکل افیلیشن ایسی جماعتوں کے ساتھ ہو - جس کی رسی دوسرے ملک میں ہے - وہاں سے رسی کھینچتے ہیں - تو یہاں گھنٹی بجنے لگتی ہے - ایسے لوگوں کو اس میں نہیں رکھا جائے - میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں - آپ کے ہی ایک بھاگ میں ایک صاحب ہیں - جو ایک بورڈ کے چیرمین ہیں - جن کا تعلق آنند مارگ سے ہے - پچھلے سال ان کی بیگم نے ڈیڑھ لاکھ روپیہ جمع کرکے آنند مارگ کو دیا میرے پاس ثبوت ہے - میں کوئی زبانی بات نہیں کہہ رہا ہوں - آپ کے وت وبھاگ میں ایسا ہوا ہے -

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE SHRIMATI SUSHILA ROHATGI): Mr. Speaker, Sir, with your permission, I would like to say that instead of taking the names of the officers who are not in a position to defend themselves here I would request the hon. Member that, if he has any specific allegations, he may send them with all the particulars to me. I shall certainly look into them.

شری محمد جمیل الرحمان : میں نے نام نہیں لیا ہے -

ادھیکش مہودے : آپ ذرا میری طرف بھی توجہ فرمائیے - یہ جو آپ کا ضابطہ ہے - اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب کسی کی طرف کوئی ایسا الزام لگاتا ہو تو اس کا نام پہلے سے صدر کو دیا جاتا ہے -

شری محمد جمیل الرحمان : میں نے نام نہیں لیا ہے - میں نے کہا ہے کہ ایک افسر ہے - جو چیرمین ہے -

صدر مہودے : پھر محترمہ کیا کہہ رہی ہیں - مجھے سمجھ نہیں آیا ہے -

شری بھگوت جھا آزاد : محترمہ نے کہا ہے کہ نام بھیجئے - لکھ کر بھیجئے -

ادھیکش مہودے : پھر تو بات صاف ہے - کوئی جھگڑا نہیں ہے -

شری محمد جمیل الرحمان : میں یہی عرض کر رہا تھا - کہ کلاز 7 میں ایک کلاز ایسا ہونا چاہئیے کہ ایسے آدمیوں کی بحالی ممبر-شپ کے لئے یا چیرمین شپ کے لئے نہیں ہوگی - جن کا ایفیلیئیشن کسی ایسی جماعت سے تعلق ہوگا جو اینٹی نیشنل ایکٹیویٹیز *(anti-national activities)* میں حصہ ہے - وہ دھیان میں رکھنے کی چیز ہے - محترم سپیکر صاحب - آج کل آپ بھی شانتی میں ہیں - اور اللہ کے فضل سے ہم لوگ بھی شانتی میں چل رہے ہیں -

ادھیکش مہودے : میں تو کبھی شانتی میں نہیں رہا ہوں - یہ تو اتفاق کی بات ہے کہ شانتی مل رہی ہے -

شری محمد جمیل الرحمان : یہ اتفاق کی بات ہے - کہ ہم لوگ بھی شانتی سے اپنی بات سنا رہے ہیں-

اس سلسلے کی کڑی میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں - آپ اس کو لاگو کرینگے تو دیش کا فائیدہ ہوگا - دیش تباہ ہونے سے بچیگا - دیش میں کچھ لوگ چاہتے ہیں - کہ دیش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، دیش کے عوام تباہ ہو جائیں، دیش ختم ہو جائے - لیکن اس طرح کی کارروائی سے دیش کو بچایا جا سکے گا ہمارا دیش سرکشت رہ سکیگا - لیکن ایسے لوگوں کو آپ کو سکیورٹیفائیز کرنا ہوگا - ان کو ہٹانا ہوگا - جو کرسی پر بیٹھ کر عوام کی گردن کو اڑا رہے ہیں - دیش ودھروہی پن کا ثبوت اور مظاہرہ کھلے عام کر رہے ہیں -

اسی طرح سے کلاز 8 کے بارے میں میرا اوبجیکشن ہے - کہ اس میں آپ کو

[شری محمد جمیل الرحمٰن]

ایسے لوگوں کو لیا جائے - جو بینکنگ انڈسٹریز کی ترقی کے لئے کمپیٹنٹ ہوں - جو عوام کی بھلائی کر سکیں - بینکوں کے نیشنلائزیشن کا مطلب یہی تھا کہ ہم عوام کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچا سکیں - پہلے کچھ پونجی پتی ہیں - وہی ملکر بینکوں سے فائدہ اٹھا لیتے تھے - عوام کو بینکوں سے کوئی فائدہ نہیں ملتا تھا - بینکوں کے نیشنلائزیشن کا مطلب یہ تھا کہ ملک کی آٹھ کروڑ جنتا جو گاؤں میں رہتی ہے - اسکو فائدہ ہو - جیسے سمال فارمرز ہیں - سمال انڈسٹریز والے ہیں - ان کو فائدہ ہو - وہ اپنی انڈسٹریز گاؤں میں لگائیں تاکہ گاؤں کے لوگوں کو ایمپلائمنٹ مل سکے -

آخر میں میں یہی عرض کرونگا - کلاز ۱۳ کو بالکل ڈلیٹ کیا جانا چاہئے میری آپ کے ذریعے درخواست ہے - کہ کلاز ۱۳ کو بالکل ڈلیٹ کیا جانا چاہئے - میں بالکل اس کے حق میں ہوں - میں آپکی جانکاری کے لئے صرف ایک لائن پڑھنا چاہتا ہوں -

"It shall not be necessary to consult the Commission in regard to the selection of a person—

(a) For appointment to a post in the clerical or allied cadre, on compassionate grounds (in pursuance of the scheme framed by a public sector bank in consultation with the Commission and with the previous sanction of the Central Government), of a dependent of an employee who had died while in the service of the public sector bank."

اسی طرح سے اور کلاز ہیں - میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں - کہ اس کے ذریعے سے آپ ایمپلائیز کو کھلی رسی دے رہے ہیں کہ جتنی ہی کھینچو اتنی ہی مضبوط ہوتی جائیگی - بھارت میں جتنے کارپوریشن بنے ہیں - ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی کو بھی جواب دہ نہیں ہیں - نہ تو پارلیمنٹ کے لئے وہ جواب دہ ہے حالانکہ عوام کے لئے ہی سارے کارپوریشن کو بنایا گیا ہے - فرٹیلائزر کارپوریشن - انڈین آئل کارپوریشن - سیڈ کارپوریشن - جیوٹ کارپوریشن - ان کے بارے میں جتنا بھی کم کہا جائے - وہی اچھا ہے - اس لئے میری گزارش ہے کہ ان بینکوں کا جو صحیح مقصد ہے عوام کے مفاد کے لئے ہیں - یہ بات اصولی طور پر طے ہے - تو اس کو عمل میں بھی لانا چاہئے - اس کو لاگو بھی کرنا چاہئے - بینک کچھ لوگوں کے لئے ہی فائدے مند نہ ہو کر عوام کے لئے بھی فائدے مند ہوں -

ان سب باتوں کے ساتھ میں آپ کا شکر گزار ہوں - میں چاہتا ہوں کہ سرکار میرے سجھاؤ پر دھیان دے - یہ بل عوام کا بل بنے، کسی خاص طبقے کے لئے ہی یہ بل بن کر نہ رہ جائے -]

SHRI ARAVINDA BALA PAJANOR (Pondicherry): Mr. Speaker, Sir, I support this piece of legislation. It has come in correct time to regulate these financial institutions. In this line it is similar to that of UPSC. It is a welcome thing. The hon. Members referred to the point as to how these banks are functioning in the rural sectors and also expressed their view that people with certain amount of experience in rural life should only be sent there. They referred to the provision of ten years of experience to be a member of the Commission. I am afraid how people from the rural sector can have ten years of banking experience. Our experience also tells us that people who are in the urban areas are reluctant to go to rural areas and even if they are sent in the rural areas they try to impose the conditions that are available in the cities with the results that the benefits intended to be rendered by the banking institutions to the common man are not reaching him in the rural areas Therefore, Sir, when the recruitment rules are framed under this Commission they must also see that the agricultural needs of our country and the service conditions be so moulded so as to meet this requirement.

Now, a word about promotion in the banking institutions Promotions for junior officers are given and there is reservation of 25 per cent from clerical grade. I urge that similar provision must be made for clerical posts from the attendants and the subordinate class IV officers. There are graduates and final school pass persons working as attendants and class IV servants.

Sir, the banking institutions are now functioning in closed chambers. Though we may claim that we are going to the people and a number of new branches are being opened in villages yet the common man is not very much benefited by this. The Service Commission is having supervisory power and the supervisory power alone is not sufficient to extend the services of the banks to the rural areas. Therefore, the banks that are in rural areas must be governed by a separate Commission or by a Committee within the Commission itself. My fear is if the Banking Commission is to follow the same procedures involving voluminous files as are followed in UPSC, the same pitfalls that are available in UPSC will come to this Commission. It is a good thing to bifurcate these services into Commission so that efficient work can be done but if you are going to follow the same procedure as is available in UPSC then only in name we will have the Commission but not in execution. Therefore, Sir, when we introduce these pieces of legislation they must be made on certain specific lines. I find in the entire law the common law language is used and the language is not specific. I wish the Government to fill up the loopholes at least by referring it to certain specialists.

Eighty-five per cent of our population lives in the rural sector. The banking institution is a vital thing that controls—though we say it finances—the very life of our country. Therefore, we must contemplate in such a way that these Commissions function in those areas with efficiency, zeal and real spirit. But in this Bill I find only solutions that are given to the banking institutions to be controlled mostly in urban areas. If there is some piece of legislation by which we can think of the rural sector in banking institutions then we can render real service to the rural people.

When some hon. Members expressed their doubts that these financial institutions are helping big industrialists and the big farmers, I feel, because of the supervisory power that is given to the Commission if it is not properly exercised it will go down

[Shri Aravinda Bala Pajanor]

still further and deteriorate still further. Though it is said that poor people are being helped yet many of us know that only those people who have some influence are alone benefited as there are a number of loopholes. If these loopholes are not plugged, we may repeat the past tragedy. Therefore, I request that after the appointment of the Commission the rules must be framed as early as possible. Then, they must be sent to these institutions. In this connection, it is also said that the other financial institutions may also be brought in, whenever the Central Government feels the necessity for it.

In our country, especially in the southern parts, there is an alarming situation because of the operation of the chit fund companies. They are also financial institutions. They are making lot of profits. I do not know whether this Commission will extend its supervisory power or its advisory power or its controlling power to these institutions. There are a number of chit fund companies in Kerala, Tamil Nadu, Karnataka and also in Pondicherry. These institutions are now controlled by certain legislations of the States. When the question was raised that it was a Central subject, it was said that these are not banking institutions, and therefore, they do not come under the Central Government. In my opinion—it is the opinion of most of the people—they function more like banks. They finance people, collect money from people, they distribute a portin to the people and they themselves devour most of the money. These institutions must be controlled. The State legislations are not sufficient to control these institutions. There are similar institutions in other parts of the country also. For example, there are hire purchase companies and money lending institutions. In these institutions, there are many people who are working without any experience in finance. Sir, if these institutions are allowed to function freely, they will hamper the very structure of our financial status. They inject money into the society, they sometimes take money from the society and they control a viable portion of our economy. This is a fact known to many of us. But, we are not bringing forward any legislation to control these institutions. These institutions form a major sector of the financial transactions of our people. Day in and day out, people are having regular contacts with these types of institutions and these institutions dominate the monetary position of a very large number of our people. Forty per cent of our people go to these chit funds and bid chits and they also make contributions to these companies. They are very much connected with these institutions in so far as their financial transactions are concerned. Then, there are a number of hire purchase companies. They are financial institutions, according to me. Ten per cent of our people purchase articles and other things from these companies. These companies take money from these big institutions and practically wreck the economy of our country. Therefore, Sir, I submit that this Banking Service Commission should not stop only with these financial institutions that are recognised by our laws, but they should also control these institutions which are actually ruining the common people. The services in these institutions must also be controlled. For example, I know two or three companies in our side. They are family concerns. They have a big name and they recruit people who are not even qualified in the third standard. In other institutions, 300—400 people are recruited and in some places, there are thousands of people employed in such institutions. Because the service conditions and the status of the people employed therein are not regulated, a number of malpractices are taking place in such companies.

When we speak about nationalised banks, we say that they are not functioning properly and that the customer service has deteriorated after nationalisation. I do agree with that. I have also the sad experience when I had been to a nationalised bank along with my friend to deposit a certain sum There, we were made to wait for four hours. This is the position in some of the institutions. But, that cannot be regulated simply by a piece of legislation like this Unless you have a goal, unless you have a regulation to control all these institutions, it cannot be done. But the case is still worse in the case of those institutions which are functioning as a by-product of the banking institutions. Therefore, when we have this legislation, we must also look at the other sectors of this business which do not come within the ambit of this legislation. Now that we are in an emergency, this is the time for us to consider these institutions which do not come within the ambit of this Bill and provide for them also. I do not know whether it is by a clever method that they have escaped this kind of legislation. Therefore, I request the authorities here to consider this aspect very seriously and try to bring within the legislation, within the scope of the Banking Service Commission all such institutions and render this service to the people.

SHRI C. M. STEPHEN (Muvattupuzha): I rise to support the Bill. In this Bill, there is nothing new by way of a fresh policy. The setting up of a Banking Service Commission for the purpose of recruitment and appointment of banking personnel is just a logical step in the line of logistics following the nationalisation of banks. With respect to the Railways and other public sector areas, this is the policy we have adopted. Therefore, it is only legitimate and natural that the banking personnel must also be recruited by a Banking Service Commission.

It will, in fact, be appreciated that the most predominant factor in banking is the personal service we get. It is not like other manufacturing industries where so many other factors count; in banking it is the personal service that counts most. The success or failure of the institution depends on the type of people who serve in the banks.

12.00 hrs.

I do not want to go into the different clauses of the Bill because strictly this is not the stage for it. I should, however, try to have a look at the broad principles and certain factors that have come into the public gaze taking into account our experiences during the period since the nationalisation of banks. It is now common knowledge and admitted almost everywhere that whatever be the justification somebody may offer, the banking industry, the nationalised sector of it and the other sector, has not acquired in the course of the last few years what may be called an impression or assessment of reputation. It had the 'distinction' to be singled out by the Prime Minister during her speech when she said that if the persons employed in the nationalised sector do not properly behave, they can bring dis-service to the people and ill-fame to the idea of nationalisation. Now it is known—at least that is the assessment of the people at large—that banking has become a cesspool of nepotism, to some extent corruption, and misbehaviour by persons who are serving in the banks. You have got arrogance there, you find insolence there, absolute irresponsibility in certain quarters and a total lack of appreciation of the motivation that prompted Government to launch on the measure of nationalisation. I wish that on the debate in this House on this subject of banking, no censorship was imposed, because if only the persons serving in the banks knew how this House and the members of this House have appreciated their service, it would have been a dose for them for a certain measure of corrective behaviour in the future. That is all I could say about it. They have got

[Shri C. M. Stephen]

high wages; they are being treated as a privileged class among employees in industry. In the banking industry you find overtime much more than anywhere else. For doing clerical work for which they are engaged, there is abnormal overtime inspite of the high wages they are paid. And that is accepted as a normal thing in the banking industry. Stories are afloat that loans were being given by certain officers knowing that the loans would be irrecoverable, with a definite understanding that the loans might be written off at a particular stage as bad debt. I do not want to make any particular reference to any branch but stories have come in that certain employees collected commission on the basis of loans granted and that that commission was shared among the bank staff. This is what we are experiencing and the customer does not get a proper service. Even those customers who have deposited their money in the banks and who have got to deal with the banks get a service which is not of a high order. I repeat that there is distinction between the manufacturing industry and the banking industry the difference is that in the banking industry from beginning to end the overall thing is the service that you get. If the service is vitiated then the experiement fails. Bank nationalisation had two purposes: to take away the money power from certain quarters and vest it back in the public area and the other was to use the savings of the people for regeneration of wealth in this country and get it to the poor man and get better service for the general public. The second part has totally failed. This is the assessment of the common man and it is the common man's impression that was reflected in the remarks of the Prime Minister when she made a survey of the economic situation in this country. I do not know how far this has been taken note of. This malady has to be rectified. Will it be rectified merely by recruiting the proper type of people? At the stage of recruitment a person is absolutely perfect but once into it, once his tenure seems to be assured, circumstances are such that he can lord over everybody; even the best person starts degenerating. You may try to recruit the best people. Subsequently the fact has to be taken into account that in the banking industry there are trade unions. Those unions are not affiliated to the central organisation but they are known to have their sympathies with them. Unlike other industries there is collusion between the so-called leadership of the trade union front and the so-called managers who are in control of the industry. Industrial peace can easily be had if this arrangement is cultivated—arrangement whereby collection of commission is permitted and distributed, arrangement whereby recruitment is made at the dictates of the union, arrangement whereby victimisation could be inflicted by transfers, arrangement whereby favouritism could be shown by keeping particular persons in particular area and no transfer being effected. If there is to be collusion like this, what is the industrial peace worth? There is a third factor, that is, the people at large, people who are dealing with it. If banks are allowed to have this sort of arrangement and people are allowed to be fleeced and service, is vitiated what purpose has it served? That is the total experience that is given. I am happy that the Labour Ministry is represented here today in full force. Shri Raghunatha Reddy was here; he had just gone out. Well, now, we are trying to revamp the entire section. A new concept is also now sought to be injected into the whole sphere, that is to say, it is not the employer and the employees alone who count, it is not the management and the workers alone who count but there is a third factor also. The third factor is the community, the people. That third factor must also be there. Now, a concept is developing that the Industrial Committees must be there, there must be an apex body to take care of the total policy in the country and below that with respect to different

industries there must be industrial committees taking stock of the situation in different industries and to giving directions there limiting not merely to the management labour relations but something higher and something larger. With this view, an attempt is being made, an effort is being made. My understanding is that in the banking industry there was a conference where the Government, the banking management, Finance Ministry and the national trade union leaders were also present and there was an agreement reached that an industrial committee should be formed. But I come to understand that an effort is being made to scuttle that agreement. I would like to know—of course during this session I may not able to know —what exactly the reaction of the Labour Ministry to this is, Banking industry is not something with which somebody can play. Nor the Labour Ministry can afford to permit it to play with it. I would like to draw the attention of the Labour Minister, Mr. Verma, to the fact that the whole purpose of this bill is to improve the conditions and to improve the serviceability of the institutions and I would like to point out that by mere recruitment serviceability would not come, serviceability would come only if they can set up this committee whereby apart from the management and the workers, the community is also taken into account. With that, the industrial committees were thought of in the textiles industry also. So in the banking conference there was a move to set up an industrial committee. That is my information. Subsequently, a move is being made to scuttle this idea. I would like to know what the reaction of the Labour Ministry is. On the floor of this House, I want to make an emphatic announcement, as a representative of the major trade union movement of this country, if this industrial committee for the banking is going to be scuttled by anybody take it from me that there will be no industrial committee in any other sector also. Let not partisanship and factionalism come into the picture. I am saying this with all seriousness. Let it be remembered the persons in authority who are guiding the bureaucrats, who are in the national front, who are in the labour front are not persons who can react also. We can understand things and we know how to tackle things. But let not any attempt be made to scuttle this move. This is my humble submission. If this bill is to have its proper effect, then the subsequent stages may also be taken into account and by the subsequent stages, I mean, a proper national set up whereunder the working of the banks could be reviewed, could be kept under surveillance policies can be evolved and policies can be implemented so that the banking institutions may not become the happy hunting ground for some people at the expense of the general public. If that is done, the logistic whereunder nationalisation was effected, whereunder this bill is brought about, will have its proper effect as far as the people at large are concerned. This is what I have got to say with reference to the Bill. I support the Bill and I hope this will be a deviation from the *status quo* arrangement and it will bring about better integrity, better efficiency and better serviceability for the institutions, for the people at large and nationalisation will be taken to its logical conclusion keeping in view the purpose for which the banks were nationalised. With these words I support this motion.

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष जी, कई मित्रों ने इस विधेयक में कई प्रकार की त्रुटियां बतलाने की कोशिश की है । उन त्रुटियों के बावजूद यह विधेयक कुछ काम का है । इसलिए मैं इस का समर्थन करते हुए कुछ बातें कहना चाहता हूं ।

यह बैंकिंग सेवा आयोग जिस का गठन करने की बात इस विधेयक में की गई है, उस के सम्बन्ध में बहुत सारी बातें कही जा चुकी हैं । मैं मंत्री महोदया से कहना चाहता हूं कि इस आयोग में ऐसे ही लोगों को रखना चाहिए जिन की आस्था आप की नीतियों

[श्री रामावतार शास्त्री]

में हो, सरकारी क्षेत्र सफलीभूत हो, राष्ट्रीयकृत संस्थाएं आगे बढ़े, जिन का विश्वास इस में हो, जिन का विश्वास धर्मनिरपेक्षता की नीति में हो, जिन का विश्वास समाजवाद में हो और जिन का विश्वास जनतान्त्रिक प्रणाली में हो, ऐसे ही लोगों को इस आयोग में सदस्य बनाया जाना चाहिए। अगर यह लोग इस तरह के होंगे तो जाहिर बात है कि जिन कर्मचारियों को यह नियुक्त करेंगे, उन कर्मचारियों में ऐसे ही लोग भर्ती किये जायेंगे जिन का विश्वास इन सिद्धान्तों के प्रति होगा। अभी स्थिति दूसरी है। जो बैंकों के बड़े बड़े अफ़सरान हैं, बड़े बड़े कर्ताधर्ता हैं, जो नौकरशाह हैं, उन का न जनता से सम्बन्ध है और न बैंकों के कर्मचारियों से सम्बन्ध होता है। उन की दुनिया कोई तीसरी ही होती है और यही वजह है कि बहुत जगहों पर ठीक से काम नहीं हो पाता है। मजदूरों और कर्मचारियों और प्रबन्धकों में समय-समय पर झगड़े आमतौर पर होते रहते हैं और काम में नुक्सान होता है। मैं इस के बारे में उदाहरण देना चाहता हूं। यह हमारे सूबे बिहार का उदाहरण है और मुजफ्फरपुर शहर का उदाहरण है। मुजफ्फरपुर के बिहार स्टेट सेन्ट्रल बैंक एम्पप्लाइज यूनियन के प्रेसीडेंट ने भारत सरकार के श्रम मंत्री के पास एक तार भेजा है और उस तार की प्रति वित्त मंत्री के पास भेजी गई है और हमारे कम्युनिस्ट दल के नेता श्री इन्द्रजीत गुप्त के पास उस की कापी भेजी गई है। मेरे पास भी भेजी गई है और अन्य कई संसद सदस्यों के पास उस की प्रतिलिपि भेजी गई है। मैं उस को इसलिए यहां सुना देना चाहता हूं ताकि आप को नोटिस में यह आ जाए कि आर के अधिकारी मामूली-मामूली बात के लिए किस तरह से कर्मचारियों के साथ पेश आते हैं। वह तार इस प्रकार है :

"Mr. Davar Zonal Manager Central Bank Patna has ordered wage cut for our demonstration on 11th March last against Zonal Manager's unlawful whimsical antilabour works, apathy to institution and workers which invited demonstration stop. So Zonal Manager was fully responsible not the workers stop. He although bears antilabour attitude causing disturbance in industrial peace stop. He trampled workers with shoes during sitdown strike favouring nationalisation on 8th February, 1968 and apathy to advances to poor and neglected sectors leaves no doubt about his antinationalisation attitude stop Squandering of public money by ill motivated bad advances about 67 lakhs with packrukhi sugar mill amount exceeding even face value caused resentment amongst workers stop Umbrella to corrupt officers has allowed rampant corruption stop Necessary enquiray and Action solicited or serious breach of peace apprehended."

यह तार है जो कि भेजा गया है। इसलिए मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की बातों को आप को देखना चाहिए और कम से कम ऐसे लोग इस बैंकिंग सेवा आयोग में न रखे जाएं और न ऐसे लोगों को राष्ट्रीयकृत बैंक में रहने का अधिकार है। इस लिए आप की नीति के प्रति जिन में आस्था हो, ऐसे ही लोगों को आप इस में रखिये।

दूसरी बात अनुसूचित जाति और जन जातियों के बारे में कहना चाहता हूं। उन को सुरक्षा देने की बात कही जाती है और नियुक्तियों में उन के लिए विशेषाधिकार दिये गये हैं लेकिन इस सिलसिले में मैं एक ही उदाहरण और देना चाहता हूं। आप के यहां कानून ठीक है लेकिन उस पर अमल नहीं होता है। इस चीज को भी देखा जाना चाहिए और यह जो इस तरह का कमीशन बन रहा है या जो आप के दूसरे अफ़सरान हैं उन का यह कर्तव्य है कि वह देखें कि आप ने जो नीति बनाई है, उस का पालन होत

है या नहीं। पटना के रिजर्व बैंक में शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के 100 से भी ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं लेकिन उन का प्रोमोशन नहीं हो रहा है। मैंने पिछले सत्र में भी यह सवाल उठाया था और वित्त मंत्री जी की तरफ से मुझे यह जवाब दिया गया था कि आल इन्डिया रिजर्व बैंक एम्प-लाइज एसोसिएशन से शायद कोई उन का समझौता हुआ है, जिस समझौते के कारण कठिनाई हो रही है और हम कुछ नहीं कर सकते हैं जबतक कि एसोसियेशन के लोगों से पुन बात न हो जाए। जब यह बात शेड्यूल्ड कास्टस और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के कर्मचारियों को मालूम हुई, तो उन्होंने आल इन्डिया रिजर्व बैंक एम्पलाइज एसोसियेशन को एक चिट्ठी लिखी और उस के जवाब में आल इन्डिया रिजर्व बैंक एम्पलाइज एसोसियेशन के सचिव ने जवाब दिया, जिस की कापी अभी मेरे पास नहीं है और अगर मंत्री जी चाहेंगे तो मैं उन के पास उस को भिजवा दूंगा, कि हमारा ऐसा कोई समझौता सरकार के साथ नहीं है कि आप लोगों को प्रोमोशन या दूसरे अधिकार नहीं मिलने चाहिए। तो ये आफिसर किस तरह से जवाब देते हैं? ये इस लोक सभा का बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं अनुसूचित जातियों और जन-जातियों के प्रसंग में यही निवेदन करूंगा कि आप इस बात की जांच करवाइए कि यह बात कहां तक सही है। अगर इस में कोई गलती है तो उस को सुधारा जाए और शैड्यूल्ड कास्टस और शैड्यूल्ड ट्राईब्स के जो 100 से ज्यादा लोग हैं उन को प्रोमोशन देना चाहिए और उन को दूसरे अधिकार मिलने चाहिए।

अध्यक्ष जी अभी कई सदस्यों ने कहा कि जातिवाद के आधार पर बहाली होती है, तो मैं भी यह कहना चाहता हूं कि बिहार में बहाली में पैसे ले लिये जाते हैं और मुझे उम्मीद है कि यह जो सर्विस कमीशन आप बना रहे हैं उस के बाद ये बातें रुकेंगी और योग्यता के आधार पर भर्ती होगी। जो आप का क्राइटीरिया है या मापदंड है, उस के आधार पर भर्ती का काम चलना चाहिए और जातिवाद के नाम पर अयोग्य आदमियों को न रखा जाए और पैरवी के नाम पर जो नियुक्तियां होती हैं या अफसरों के लोगों को नियुक्त कर लिया जाता है, वे नहीं होना चाहिए।

इस के बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि आप के बैंकों में बहुत से अस्थायी लोग भर्ती हैं। उन लोगों का क्या होगा? उन लोगों को निकाल कर फेंक नहीं देना चाहिए। ऐसा न हो कि जब यह कमीशन बैठे तो ऐसे तमाम लोगों को रफूचक्कर कर दें और कह दें कि अब आप लोगों की जरूरत नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि टैम्पोरेरी तरीके से जिन लोगों की नियुक्ति हुई है, उन को भी रखा जाए।

यह बहुत आवश्यक है कि विभिन्न क्षेत्रीय आयोगों के सदस्यों को उन इलाकों की भाषायें जाननी चाहिए। ऐसा न हो कि कोई हिन्दी इलाका है, और वहां के आयोग का कोई सदस्य हिन्दी भाषा ही नहीं जानता है और अंग्रेजी में बात करता है, या किसी गैर हिन्दी इलाके में आयोग का कोई सदस्य केवल हिन्दी ही जानने वाला हो। इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए कि क्षेत्रीय आयोगों में विभिन्न भाषायें, और खास तौर से उन क्षेत्रों की भाषायें, जानने वाले लोग रहें।

क्लास फोर के बहुत से एम्पलाईज मैट्रीकुलेट होते हैं। अब तो कई बी० ए० पास व्यक्ति भी चपरासी का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए ऊपर की नियुक्तियां और प्रोमोशन का रास्ता खुला रहना चाहिए, क्योंकि वे बरसों से बैंकों की सेवा करते रहे हैं।

[श्री रामावतार शास्त्री]

बैंकों की नियुक्तियों में जहां जात-पात का विचार नहीं होना चाहिए, वहां हिन्दू, मुस्लिम, सिख ईसाई आदि का भेद भी नहीं करना चाहिए । कमीशन को यह समझना चाहिए कि हम सब हिन्दुस्तानी हैं, सब धर्मों के लोग भाई-भाई हैं और एक भारत माता की सन्तान हैं । इस लिए कर्मचारियों की नियुक्ति में इस प्रकार का कोई भेद-भाव नहीं होना चाहिए ।

इस समय बैंक उद्योग में आल-इंडिया बैंक एम्पलाइज एसोसियेशन एक मात्र प्रतिनिधि-मूलक संगठन, या कर्मचारियों के विशाल बहुमत का प्रतिनिधि संगठन है । मैं यह बात जानता हूं क्योंकि बैंक कर्मचारियों के संगठनों से मेरा भी कुछ सम्बन्ध रहा है । सरकार को उन लोगो का सहयोग जरूर लेना चाहिए । इस समय बैंकों में जो गड़बड़ियां और त्रुटियां हैं—काम में ढिलाई हो जाती है, समय पर काम न होने के कारण जनता असंतुष्ट और नाराज होती है और बैंकों में भ्रष्टाचार भी घुसने लगा है—, सरकार उन को कैसे दूर करेगी ? ये त्रुटियां केवल सरकारी डंडे से दूर होने वाली नहीं हैं । ये केवल इमर्जेंसी से दूर होने वाली नहीं हैं । यह ठीक है कि इमर्जेंसी का असर जरूर पड़ा है, लेकिन आल-इंडिया बैंक एम्पलाईज एसोसियेशन आदि जो बैंक कर्मचारियो के प्रतिनिधि-मूलक संगठन हैं, उन का सहयोग लेना जरूरी है ।

आल-इंडिया बैंक इम्लाईज एसोसियेशन इस दिशा में काम भी कर रही है । क्रेडिट पालिसी में जो गडबडी और कमी है, जिस की वजह से इजारेदारों को ज्यादा कर्जा मिल रहा है, उस नीति को बदलने के लिए आल इंडिया बैंक एम्पलाईज एसोसियेशन सरकार से बहस मुबाहसा कर रही है, सरकार पर दबाव डाल रही है । कर्मचारियों में जो ढिलाई आ गई है, बैंकों में जो भ्रष्टाचार घुसने की कोशश कर रहा है, उस के खिलाफ भी यह संगठन चुस्ती के साथ काम कर रहा है, और आगे भी करता रहेगा । इस लिए सरकार को उस का सहयोग जरूर लेना चाहिए ।

बैंक बड़े महत्वपूर्ण संगठन हैं । आम जनता और किसानों तथा गरीबों के साथ उन का सम्बन्ध है । मुझे विश्वास है कि यदि सरकार द्वारा निर्धारित नीति के आधार पर आयोग ने काम किया और उस के मुताबिक कर्मचारियों की भर्ती हुई, तो हम अपने देश में राष्ट्र-विरोधी शक्तियों, फाशिस्ट शक्तियों और जनतंत्र विरोधी शक्तियों को कमजोर कर सकेंगे और चाहे वे लोग आनन्द मार्ग में हो, या आर० एस० एस० या जमाअते इस्लामी में हो, हमे उन को निकाल बाहर करने मे आसानी होगी ।

अध्यक्ष महोदय यह बिल बड़ा स्पेसिफिक है । मैं समझता था कि आप इस पर भी आयेंगे । आप ने तो इस को जेनेरल डीबेट बना दिया है ।

श्री रामावतार शास्त्री मैं तो बिल पर ही बोला हूं । कमीशन कैसे बहाल हो, उस का क्या रूप हो, इस बारे में मैंने सारी बाते कही हैं । मैंने बैंक एम्पलाईज से सहयोग लेने की बात कही है, क्योंकि आज के जमाने मे वह बहुत जरूरी है । विदेशी बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात कहना मैं भूल गया, क्योंकि उस का इस विधेयक से तालुक नही था ।

SHRI RAJA KULKARNI (Bombay-North-East): I welcome this Bill. The proposed appointment of the Banking Service Commission is no

doubt a welcome step but at the same time it should be realised that the Bill has a very limited scope and, as you just now said, has a very specific purpose. It marks the beginning of the process of rationalising and of raising efficiency that the Government want to introduce in the banking service as a whole. From that point of veiw, people have got high expectations. Therefore, I am very much interested in seeing that even with this limited scope of the Bill, the step that is now being taken becomes an effective step and becomes a success.

We are told that this Bill has been taken from a model. It has come out of the recommendations of the Banking Commission and the model that has been suggested is the Union public Service Commission. I doubt very much whether we can take today the model of the Union Public Service Commission for the nationalised banks. I have nothing to say about the Union Public Service Commission, and besides here it is not the also. But if needs to be noted that the requirements, the purposes and the objectives that have to be fulfilled m respect of the services to be rendered by the banks and the role to be played by the banks in bringing about social and economic change are diffrent. The recruitment of the clerical and allied categories and junior officers is sought to be centralised now. Though the purpose is laudable, the way in which it has been drafted is not very conducive to the fulfilment of the objective. The important Clauses of the Bill are 4, 7, 10 and 12 as they laydown the composition of the Commission and its powers and functions. However, there is a big gap between the objective of regularising recruitment and providing good people to the banks. The objective is to take away these functions from the individual banks and vest them in the Commission, but it is not completely vested in the Commission. The employment policy and personal policy pursued by nationalised banks have not been covered in the Bill. In the matter of recruitment, the utmost that has been done is to provide for holding examinations for appointments. Examinations only decide the eligibility for selection and do not constitute employment in itself. Employment implies not only the selection processes but also the actual placement on the job. Placement of the right man at the right place is a very important function which has been deleted from the function of this Commission.

12.30 hrs.

[SHRI G. VISWANATHAN *in the chair*]

A statement is to be submitted by each bank during the remaining period of the first year and then as early as possible in the beginning of each subsequent year, regarding the vacancies available in various categories. The Commission will keep a record of these vacancies but it has no power to force them to make the placement It can only recommend and the banks are completely free to decide whether the vacancies are to be filled or not. There is no time limit fixed within which the vacancies have to be filled. We do not want to have frustration among the educated young people of this country. Therefore, let there be some kind of an advisory committee in which the representatives of the unions and the representatives of the management can lay down jointly the employment policy which includes not only the selection of persons and the rules for the selection of persons but also the new employment potential. These rules should be applied for regulating the management's right on reorganisation of the Department which touches the employment schedule also. So, these things are necessary. Further, not only the reorganisation policy of the Management, but even transfers, promotions are to be considered. They are also part and parcel of the employment policy. Unless you touch and regulate the promotion policy of the bank Management, and if transfer policy, how are you going to fill up posts? And your recommendations will also have no meaning.

[Shri Raja Kulkarni]

Suppose the Central Bank of India in Bombay, communicates that there is a vacancy in its Calcutta office. They are transferring a man from Bombay office to Calcutta office. Are you going to create a conflict? What are the rules? I want to know whether a man recommended by the Calcutta Regional Office of the Commission should be employed by the Central Bank or a person should be transferred by the Central Bank from Bombay office to Calcutta office? What are the priorities to be laid down for transferring a person from one place to another, from one region to another and from one location to another ? These are the policies which should be laid down jointly by the employees and the Management There should be some guidelines for the Commission They should reguarly be in touch with the Management and the Management must follow these guidelines. Unless the Commission has got this kind of powers and functions, merely holding examinations and preparing lists of eligible candidates will not be very effective in bringing efficiency in the cadre of the banks

We have been seeing that the UPSC has been there for a very long time They are holding examinations for Railways, for Posts & Telegraphs and for other Departments. Yet we are not in a position to say that it has caused efficiency. Something else then is required We would, therefore, like the Minister to assure us about all these functions which are necessary There are complementary and auxiliary in nature to make the main function of the recruitment a success

In the objectives of the Bill, it is stated that so far as the fresh recruitment in the Jr. Officers, Cadre is concerned, it shall not be less than 25 per cent. Now, there are agreements in some banks. In seome of the agreements, it is stated that the fresh recruitment in the Junior Officers' Cadre can only be upto 15 per cent. Now, what will you say about the existing agreements? Are these to be set aside ? You are going to tell the Management to recruit fresh candidates in the Jr. Officer Cadre when the agreement provides that it cannot be more than 15 per cent. So, there ought to be categorical assurances from the Minister on the Floor of this House that in the existing agreements with the unions of the banks, if there are a specific provisions in respect of promotion, recruitment and transfer, these will be protected under this legislation, so that they can implement those provisions effectively and efficiency can be increased. If this is not done, then it would be very difficult to make this effective.

Many of these managements have got separate training colleges and schools. If the Banking Commission is going to hold examinations, it is also necessary that this Commission takes over the functions of coordination and centralisation of the training institutions which are existing with these 14 nationalised banks. It is then and then alone that they will be able to provide a good cadre to the banks.

With these observations, I support the Bill.

SHRI SHYAM SUNDAR MOHAPATRA (Balasore) Mr. Chairman, Sir just as the people of Great Britain, the Magna Carta was the beginning of popular representation to bank nationalisation was the beginning of all positive and radical measures in our country.

I am reading out from page 2 of the Bill regarding the Chairman and members of the Commission. It says:

"The Chairman and members shall be persons who, in the opinion of the Central Government, are men of ability, integrity and standing and have special knowledge of, or practical experience in,

financal, economic or business administration or in the administration of Government or any other matter which would render such person suitable for appointment as Chairman or memer."

What I want to emphasise is this. In a radical economy or in a society which is having radical transformation from feudalism to socialism what is essential for the selection of a Chairman is the commitment of a person in terms of integrity commitment in terms of honesty and commitment in terms of representing the general will of the people. Unless the Government is going to translate this attitude into action, all these things will sound only hyperbolic.

Mr. Chairman, all these IAS officers today enjoy a certain amount of independence, they try to feel that they are probably a separate class of people, a separate species altogether to guide the decisions of the Government. Similarly, if these people, bank executives, go to feel that they are all big bosses (*bara sahib*) in the national economy, then the entire purpose will be lost. So, I would urge upon the hon. Minister certain salient points in selecting an executive, the first criterion of selection of the Chairman and members of the Commission should be the commitment of the Chairman and the members to the purpose for which they have been selected. Unless this is done, we cannot have the right type of persons. If the Chairman does not feel one with the popular impulse, one with the general will, one with the general reaction in the country to the Government policy, the entire recruitment will be based on fallacious assumption. Here it is written that the term of the Chairman will be five years and he will be there until he attains the age of 65. Well, there is nothing wrong in it. He may be there for five years or seven years. But why do you fix the age of 65? Why not have young people,? Why do we lose sight of the fact? Mr. Chairman, you are a young man. You represent the younger generation. Do you feel, therefore, Mr. Chairman, that a man of 60 or 65 will feel the same thing as I feel? There will be a generation gap. So, I think the age limit should be fixed upto 60. When we are retiring our people at 58, why cannot we fix the maximum age limit at 60?

We know that there will be different classes of people who will be recruited. There will be Clerks, Junior Executive and Senior Executives. The total number of bank employees has increased three-fold during the last 15 years. By the end of June 1971, there were two lakh banks employees spread over 2,000 branches. The Adarkar Committee estimated in 1968 that there were 20,000 officers and 1.32 lakh Clerks.

So, in the fitness of things there should be a Bank Service Commission. In my speech in Lok Sabha in 1972, I had suggested that there should be a Service Commission like the Railways Service Commission or as we recruit our IAS and allied officers. Unless this is done, the banks will have the independence to recruit persons as they like, as they choose and as they determine. There would not be any guidelines or a specific policy.

Mr. Chairman, the number is increasing day by day. Probably, every year, we are recruiting 47,000 people in the banks. About 18 per cent of them are officers; 24 per cent of them are subordinate officers and 58 per cent of them are clerks. What will be the number of these people? According to Mr S. D. Varde, there will be 3.38 lakh people by 1975, 4.97 lakh people by 1980 and 7.30 lakh people in 1985. It is a monstrous number. Unless the Service Commission is geared up to the extent that they should determine the right type of people, the very purpose for

[Shri Shyam Sunder Mahapatra]

which the 14 banks were nationalised will be lost.

While speaking on this Bill, I would like to suggest another thing to the Government which, probably, another hon. Member has also suggested. That is very important. These executives must know the local language. When we send IAS and IPS officers to different States, the first emphasis laid is that within two years they must learn the local language upto the middle standard. We must emphasize that these people must also learn the local language. I have seen it with my own eyes and I have once represented to our dynamic hon. Deputy Minister that these Bank Managers do not behave properly with the rural people. They take them as cats and dogs, not even as Tom, Dick and Harry. There behaviour is very bad, absolutely beyond imagination. Why? Because they hold in their hands the power of money. So, the poor people coming from villages for credit are turned out by clerks. They do not understand the local language. So, the first thing that we must emphasize is that they must learn the local language.

The Banking Commission had stated in their voluminous report about recruitment that "to be effective, the recruitment should be attempted to attract appropriate talent in terms of skill and attitude." The Banking Commission in their wisdom had suggested that, while selecting people, we must select them in terms of skill and attitude. By "attitude", I mean "commitment". They should be committed to the social transformation, committed to the socialist objectives and committed to the need of the time. Unless it is done, I think, we will lose sight of the basic fact.

Now, there will be socialists also in this category of officers. There will be economists also, there will be statisticians and legal experts also. Again, while selecting these people, we should not lose sight of the fact that we need certain type of specialists; certain type of economists. There are economists who believe in laissez-faire; there are economists who believe in Marxist economy; there are persons who believe in Gandhian economy. The present Government is committed to a definite type of economic transformation. While selecting these people, we must bear this in mind that we need particular type of specialists, particular type of economists, to lay down the policies of our banking operations.

Today, what we see is that there is a fall in deposits in the banks. There is a disparity between the bank activity in the rural areas and in the urban areas. Every bank wants to open branches in the urban areas. They do not feel that they should devote more energy in elevating the standard of the rural people. They should have a comprehensive plan to establish rural banks. What do we mean by a rural bank? As the Banking Commission had said, it means, "A primary rural bank is to serve a rural population of 5000 to 20,000" Wherever there is a large village, wherever there is a population of 20,000, to give credit facilities to these people, a rural bank should be established As you know, 80 per cent of people in our country live in villages. The vulnerable section of people, the tribals, the Harijans, the backward people the Muslims, come from villages rural areas. Unless we try to improve their standard of living, unless they feel that bank nationalisation has been a success, unless they feel that nationalisation of 14 scheduled banks is the Magna Carta of India's social transformation, everything would seem to be a hyperbole and we will feel that we have done nothing.

With these words. I support this Bill. While doing that, I must mention one thing more and that is that

there are banks other than these nationalised banks. What about the recruitment policy of those banks? The Banking Commission had stated, "If any Commercial Bank in private sector also desires to make use of the services of the Commission, it should be able to do so on mutually agreed terms." It is also there in the Bill. Why wait for a request from the private banks? Why not make it compulsory that those banks also when they want to make recruitment must go through Banking Service Commission. The banks which have not been nationalised also serve the people. I would urge the Minister to think over this proposal that the other banks also while making recruitment should take the service of the Banking Service Commission.

Mr Chairman, Sir, I think, I have put my points very squarely here and the hon. Dy. Minister while replying must also try to answer one or two points

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): Sir, I am grateful to you for giving me time to speak. I would not have spoken on this Bill; I had no mind to speak, but some of the utterances or a portion of the speech of Mr Stephen has really provoked me to speak I am sorry, my hon friend, Shri Stephen is not here now.

During the course of his speech, while bringing to the notice of the hon. Minister certain mal-practices of the banks, Shri Stephen said that there was a collusion between the bank management and the bank employees. I do not know how he got this impression of collusion. If there is any understanding between the employees and the management in the nationalised banks, that should be hailed by this House and I must appeal to my hon friend Mr. Stephen to kindly consider one point very seriously. The All India Bank Employees Association is the most powerful organization and today, Sir, when we are talking of 14 banks being nationalised, let us remember those employees and pay them proper compliments for raising the slogan of nationalisation since the very inception of the All India Bank Employees Association. I know, day in and day out, whether in the offices or in the streets, whether in the towns or in the rural areas, every bank employee under the banner of the All-India Bank Employees Association was shouting everyday practically that the banks should be nationalised. We called these banks a sort of *Alladin* lamp in the hands of the capitalists and monopolists. We were insisting all the time that you shou'd take away these banks from their hands because this was the *Alladin* lamp by which they could create anything they wanted. Instead of congratulating the bank employees, he says that there is a collusion between the management and the bank employees and what is the collusion for? For exploiting the peasants and for exploiting the farmers. I do not know, if Mr. Stephen is suffering from some obsession of corruption. I can vouch for the organization which I represent, the All-India Bank Employees Association which is the strongest. It has been proved even by verification that their leaders Shri Parbhatkar and the late lamented Shri Parwana never colluded with the management; they fought with the management, but on the other hand, the union affiliated to INTUC which is headed by Shri Stephen tried to break the strike Whether that was the collusion or this was the collusion, I do not know. I can assure you once again and assure my hon. sister, I should say, of the support of the All India Bank Employees Association. After the emergency when the meeting was called recently by the Labour Minister, Shri Dange, who represented All India Trade Union Congress and Shri Parbhatkar who represented the all-India Bank Employees Association, voluntarily decided to cut 50 per cent of the overtime. Was it not an act of

[Shri S. M. Banerjee]

patriotism? Was it not an act of nationalism? Do you call them colluding? I should say that we should not condemn those who cannot possibly defend themselves. I do not say that all employees are honest and I do not say that all M.Ps are honest. How can I vouch for everyone? There is dishonesty everywhere and in every facet of our life. Those employees who are corrupt should be punished. By all means, do it. I can understand if some employees are in collusion with the management which affects ordinary people which affects even businessmen or peasants or any kind of people. Then they must be brought to book but let us not condemn everyone of them.

Then, again, he said that the Labour Minister is in the know of the leader who wanted a bipartite committee. He said that if a bipartite committee was demanded, then he would scuttle all the tripartite committees. I do not know what he meant by it. Is he aware that the apex body of the banking industry is a bi-partite body and the Labour Minister is just an associate member? We have been demanding that there should be bipartite agreement, bipartite negotiations, bipartite settlement and a bipartite committee to settle all the outstanding problems. Why should I ask the government to intervene every time? We do not want the government to intervene. Supposing there are two wings, the management and the employees and they sit together presided over by the Finance Minister or the Deputy Minister and if they can possibly settle all the issues, why should there be any tripartite body? We have always demanded bipartite committees. That Mr. Stephen should know and he should ask Mr. Bhagwati who is the Chairman of INTUC whether the apex body of the banking industry in a bipartite body. Knowing that, why should he threaten the poor Deputy Labour Minister? I do not know what is in the mind of the Member. We have demanded a bipartite body in every industry whether it is textile or whether it is the sugar industry or any industry and only where the employees and the management could not come to a settlement, we want the Labour Minister or the government to come and help us.

About direct recruitment, it has been raised to 33 per cent from 25 per cent. I want young and energetic people to come in. I have nothing against the younger generation. I want them to come up. In this case if the percentage is increased, what happens to the existing employees? Stagnancy. Stagnancy of 5 years or 6 years or 10 years in a particular bank. The net result will be that they will lose all incentive. Everywhere we are asking that there should not be any stagnancy for more than 5 or 6 or 10 years. Otherwise, they will lose incentive. I would request whether this 25 per cent should not be kept as it is and not raised to 33 per cent. If it is a question of more employment, let more banks be opened. Have a bank for every village and if not for every village, have one for every five villages combined and if you do that, I am sure the banking industry will prosper.

I would request the hon. Minister to kindly consider this point whether the same rules should not apply to those banks which have not been nationalised I would mention the foreign banks. Take the Grindlays Bank. What is happening there? During Pakistan's aggression, they published a map in which Kashmir was shown as a disputed territory It was not necessary for the Grindlay Bank to do that I do not know whom they wanted to please. They published a map in which Kashmir was shown as a disputed territory. This helped Pakistan. They quoted it too I would request the hon. Minister to kindly see that these rules are made

applicable to those banks too—commercial or otherwise.

13 hrs.

All India Banks Association recently gave an assurance that they will serve the people to the best of their ability. If there is a complaint against anyone that can definitely be looked into. We can definitely distinguish between a worker and a shirker. Worker is a worker, shirker is a shirker. Shirker is a liability both on the union as also on the country.

I once again request my hon. friend Shri Stephen to kindly read my point and let the hon. Deputy Labour Minister not be threatened. He is shivering every time. We stand for a bipartite body and not for a tripartite body.

With these words, I conclude.

SHRI P. K. GHOSH (Ranchi): I welcome this Bill since this will eliminate nepotism, favouritism and corruption in the matter of employment to a great extent. This will also enable us to select the right type of personnel for clerical and executive level.

While welcoming the Bill I would like to make one or two suggestions. I want that Clause 3(4) should be amended. This clause says:

> "The Commission shall have regional offices in such State or group of States as the Commission may, with the previous approval of the Central Government, determine and no such regional office shall be abolished without the previous approval of the Central Government."

I would suggest that the regional offices should be established in every State. I want to stress this because it has been our experience that wherever the regional offices are located, the people of that particular State can take the advantage in the matter of employment. The people of the other neighbouring States are mostly deprived of employment as there are no such regional offices there. Therefore, there should be regional offices in every State so that local people of that particular State get priority in the matter of employment in that particular region.

Government of India has laid down a policy in regard to recruitment in all the public sector undertakings. Although banks had been nationalised five years back, yet banks are not following this policy. As per policy of the Government of India recruitment for the post carrying pay up to Rs. 500 p.m. should be made from out of the local people. But this is not being practised by the nationalised banks. There is a lot of favouritism and nepotism. Very few Scheduled Tribes people get employment there. While I say, there should be regional bank in every State, there should also be regional banks in the areas where there are Scheduled Tribes. The Scheduled Tribes do not want to go out of their homes. Therefore, in all the tribal areas there should be one regional bank so that the Scheduled Tribes get ample opportunity for getting employment in the banks

If you look to the figures of employment of Scheduled Tribes and Scheduled Castes as well as the members of the minority community you will find that their percentage is extremely low. Although in the Bill it has been provided that certain percentage of reservations will be kept for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I would also suggest that in order to see that proper opportunities are given to scheduled castes and scheduled tribe people. the membership of the commission should also be given to one scheduled caste and one scheduled tribe person and also there should be a member of the minority community to protect the interests of the minority community, because, we find that

[Shri P. K. Ghosh]

in many cases the minority communities do not get the proper opportunities of employment in the banks.

There is a lot of other irregularities in the banks and the banks' functioning needs to be toned up properly. After the nationalisation of the banks, efficiency has gone down very much. The depositors are harassed and they have to wait for hours for clearing their cheques. If you want to clear some cheques through these banks, it takes months. I have experience about this. For collection of cheques by one bank from another bank which is situated seven miles away, it takes one month. This is the situation which prevails in the banks now-a-days. Normal courtesy is not shown to the depositors by these bank employees. After all it is because of the bank depositors that these bank employees get their salaries, but the depositors are being treated like beggars when they go to the banks. The functioning of the banks should, therefore, be properly toned up. It should be seen that the depositors are properly treated by the bank employees.

There is too much of corruption in the banks. When banks give loans, in some of the cases the loanee has to give some money for grant of the loan. I am told by some of the applicants that in some banks they charge 10,000 rupees for granting a loan for a bus or truck chassis. Another thing, Sir. For mini-buses, we have evolved a scheme that the unemployed diplomaholders and graduates will be given loans. But the banks insist on them to apply for a particular brand of mini-bus. Only then they will get the loan. The agent of a particular brand of mini-bus tells the applicant that he will get the loan sanctioned for him if he applies for this particular brand of mini-bus. He says 'I will ensure that the loan is granted by the bank'. It is said that the particular brand of mini-bus company pays Rs. 2,000 per mini bus to the bank management. There should be vigilance on the proper functioning of the banks. The small-scale industries and the small farmers are not getting the loans whereas big people are taking away most of these loans. Some of the executives are out to frustrate the whole purpose of nationalisation.

I suggest that in all branches of the banks there should be a 'Public Complaint Book' like the Railways. Whenever there is a complaint the public may be allowed to enter their complaints in the complaint book. The management should go into each and every complaint and take prompt action. We should not solely depend upon the bank management, for taking action against such complaints because the management may have sympathy or some softcorner for their employees. There should be a vigilance squad appointed by the Ministry of Finance to go in to the complaints about the banks and see to the complaint books and examine as to what action has been taken by the bank management against such complaints and, if they are satisfied that the bank management has not taken sufficient and requisite steps to mitigate such complaints or has not taken proper care to remove the grievances of the public, then the vigilance squad should recommend to Government for taking suitable action against the management of the bank And only if this is done, we can expect that the banks will function properly.

With these words, I support this Bill.

SHRI KARTIK ORAON (Lohardaga): Mr. Chairman, Sir, I welcome the Banking Service Commission Bill, 1974. In fact, I am one who has always been pleading for the creation of Public Sector Service Commission. Experience has shown that there were

divergent and conflicting service conditions with regard to recruitment, promotion and dismissal in various public sector undertakings, instead of being uniform. What is more important in these public sectors is the well known maxim "not who knows what but who knows whom". In some of the Heavy Engineering concerns in public sectors, I found that one used to be promoted as Executive Engineer after three or four years of service, whereas in others, there were engineers who even after ten years were still rotting as Assistant Engineers, that is, in Bokaro Steel Ltd., N.C.D.C., H.S.L., or MECON and H.E.C. The same is true of the banking services also As a member of the Parliamentary Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, we have found that sons and relations of bank employees were enjoying more protection and getting greater weightage than even the members of the scheduled castes and scheduled tribes. Favouritism, nepotism and corruption, if I may say so, are rampant in some form or other in certain levels in all the banks. Therefore, the creation of the Banking Service Commission is a welcome move and in the right direction provided the direction is known. I hope that the ills that are prevalent in banking services will be rooted out and we will carry forward the onerous responsibility of bringing about a social change, and the purpose for which the fourteen banks were nationalised, will be served.

In this connection, I would like to sound a note of warning that the Members of the Commission including the Chairman should be properly selected and not by political consideration. They should be persons of high integrity, efficiency and drive and should be fully conscious of the policies and programmes of the Government. In this, as in many others, men of character are more important than money, machine and material. In the present context, the choice the personnel of Banking Service Commission carries an extraordinary and important burden. Let there be no mistake in this. If this aspect is lost, I am afraid that everything will end in a fiasco. I am reminded of a Hindi saying which says:

हरामी करने पर किसी को नमक हराम तो कह लेते थे

लेकिन नमक ही हराम हो जाये तो किससे शिकवा करे ।

That means if we want to cure the ills that prevail in the society, or say, in the body of a person, a suitable medicine is required. But, if the medicine itself is poisonous, then it will eat up the entire body. It must be clearly borne in mind that public servants are the greatest instruments of social change.

Here, I would like to invite the attention of the hon. Minister to Page 2 of the Bill, Clause 4(2). It says:

> "The Chairman and members shall be persons who, in the opinion of the Central Government, are men of ability, integrity and standing and have special knowledge of, or practical experience in, financial, economic or business administration or in the administration of Government or any other matter which would render such person suitable for appointment as Chairman or member."

Here, I would like to say that I do not think that there is even the remotest possibility...

SHRI S. M. BANERJEE: What is that book?

SHRI KARTIK ORAON: This is in the Bill. This is an indirect way of excluding the members of scheduled castes and scheduled tribes. By no stretch of imagination, a member of

[Shri Kartik Oraon]

scheduled caste or scheduled tribe will ever become a member. The question of his becoming the Chairman does not arise. Therefore, I suggest that persons for the appointment of the Chairman and members of the Banking Service Commission, apart from their being men of ability, integrity and standing, etc., it should be specifically mentioned that they must also have zest for the upliftment of the weaker sections of the society. Only then, will they be able to select persons of the right type for the other categories, in the lower levels, like the clerical and allied cadres, the junior officers cadre, minorities and other categories in the banking service. It may be argued that this would be taken care of. Government will always say that it will be taken care of, but. it is not possible to know the working of the mind of a man. It has been well established that men do not possess the facilities for investigating the working of a man's mind, and were uncertain as to the possibility of assessing it accurately. It is common knowledge that intentions of man cannot be probed for even the devil does not know men's intentions.

I would, therefore, like to suggest that Clause 4(2) should provide for inclusion of one member each from scheduled caste, scheduled tribe and minorities in the banking service commission and also in all regional offices. Either, they should be accommodated within the eight members of the Commission or number should be raised to ten or eleven. I think this point has been touched by the other members also. I am greateful to Shri Jamil-ur-Rahman who has advocted the cause of scheduled castes and scheduled tribes ably and rather forcefully. Only then, the cause of the weaker sections of the society would be served. Even in the selection of members from scheduled castes and scheduled tribes, special care should be taken to select the right type of person. Merely taking a member of the scheduled caste and scheduled tribe is not enough. He should be conscious of his rights, responsibilities and obligations to the society to which he belongs. He should not be a deaf and dumb representative in the Commission.

Sir, in this Bill, of course, provision has been made that reservations should be made in favour of scheduled castes, scheduled Tribess and other categories of persons. But, I am sure, Sir, that this will not be operative unless Clause 4(2) is suitably amended to include one member each from the scheduled caste and scheduled tribe and minorities. Sir, I am aware of the lacunae. Provisions of this nature alone have not worked well in many cases I will cite a few instances to clarify the position.

Firstly, a member of scheduled tribe was selected for appointment in the LIC in a reasonably higher position at Trivandrum. But, he was not allowed to join as the authorities were planning to circumvent his appointment by filling up the post by a person from other division. Secondly, during the visit of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled tribes to Bombay, it was pointed out that a person was wrongfully selected as a scheduled tribe for a Class I post in the Post and Telegraphs Department. It was investigated and later on it was found correct. But, the very top official who was at the helm of affairs ruled that we must not be so harsh as to remove him from service. One may show mercy, but, one must not be allowed to sell mercy.

Another case is one in which the UPSC had recommended two girls for IAS from Bihar as members of scheduled tribes when in fact they were not members of the scheduled tribes.

It is, therefore, that I suggest that the Commission should not only be a

rubber-stamp to go merely by records but should also exercise all reasonable care to see that wrong entry does not go unchecked. Only a member of the scheduled castes and of scheduled tribes will be able to help the Commission in this respect. It is, therefore, of paramount importance that the Commission should bave provision for the inclusion of a Scheduled Caste and a Scheduled Tribe to oversee that the reservation quotas for scheduled castes and scheduled tribes are resolutely filled up and the policies properly implemented in the scheduled banks.

I would like to invite your kind attention to the provision of regional offices. Bank nationalisation came as a clarion call to the nation to lift up the face of the teeming millions of the poorer sections. But bank nationalisation, so far as the scheduled tribes are concerned, has not been able to deliver the goods. I would, therefore, suggest that regional offices are located in tribal belts all over the country. Let the scheduled castes and scheduled tribes be associated with the policy-making body and not merely serve as dumb, riven cattle. Let the Commission be within the reach of the tribal people where invariably in all cases gigantic projects are located, not because of any favour or special consideration to the tribals but because the raw materials and infra-structure are available.

If you wish, hon. Deputy Minister—I hope you do—that the benefit should flow to the weaker sections of the people, my suggestions may kindly be accepted. If not, the creation of this Commission, or for that matter any other Commission, will run counter to the accepted policy of the Government.

Finally, therefore, I appeal to the Government to lay the foundation of this Commission on a sound footing. The Commission, if I may say so, should expressly and impliedly, directly and indirectly, serve as a prime mover in the implementation of the 20-point economic programme of our dynamic Prime Minister. It should not be a thing of beauty to look at but should be a thing of beauty to serve as a model and a source of inspiration to other Service Commissions existing in our country.

With these words, I support the Bill and wish the Bill and the Deputy Minister of Finance the best of luck.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINSTRY OF FNANCE (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI): Thank you. I need it.

SHRI D. BASUMATARI (Kokrajhar) At the outset, I congratulate the Minister and thank her for bringing forward this Bill. When I read the statement of objects and reasons, I felt encouraged to speak on this subject, though I did not think at all of speaking in the beginning.

You know Parliament has constituted a Committee which is known as a watch-dog Committee and a high-power Committee. There we examined all the banks in India and also all the public undertakings in India. From my experience as Chairman of that Committee I am reminded of what happened when we first examined Air India. The Chairman of Air India happened to be an ex-military officer at the highest level. In the beginning, he talked with a certain air as if to ask why Parliament has taken up such a subect, it will deteriorate the standard of this water-tight compartment, Air India. Like that he went on. I allowed him to speak for about half an hour. After that, I put my first question. 'Please remember whom you are serving, whether you are serving the British Government or the National Government.' I repeatedly told him feel yourself whether you have been serving under the British Government or under the National Government of India. "Of course, I am under the National Government," he

[Shri D. Basumatari]

replied. Then, in that case, are you to sermonise the Government of India? I asked him and then I scolded him and brought sense into him. Then there was the case of the Reserve Bank of India. When I first examined them, the Deputy Governor of the Reserve Bank was very reluctant about the reservation of the posts for Scheduled castes and Tribes. Whlie we read out the terms of our committee, he had to apologise. Many banks were opposed to the principal of reservation but after our examination they agreed in principle for the reservation of posts for SCST. But then they pleaded dearth of candidates. When they said so; I started going to them with the copy of the applications along with the counterfoil of receipts for payment of the prescribed fees of Rs. 5 or 2.50. I told them that so many graduate applicants were waiting outside and if I wanted I could call them to prove that there was no dearth of candidates. This is the kind of attitude that they have to this problem. In Bombay in one bank I asked them to call the clerk who receives the applications and showed him the copy of the applications that I had and asked someone to trace out the applications that were with the office; he traced them out and said that there were those applications. I find that SCST candidates with MA First class qualifications are refused appointment saying that they are not suitable. That is the dirty mentality, and the rigid mentality of those people which I term as mental reservation. When we found that there were no SCST candidates in the IAS and IPS, we insisted that the Government of India should set up pre-examination centres. One is now at Allahabad, the second in Madras, the third in Punjab, the fourth in Assam and the fifth is in Delhi itself. By the establishment of these centres, I find now that the performance of SCST candidates is better in the IAS and IPS examinations, than the Class I and II service examinations in the centre and in the States. There is no dearth of intelligent candidates among the SCST. But they do not have the facilities. They cannot send their children to the public schools or Kendriya Vidyalaya because in Kendriya Vidyalaya only the children of Central Government servants are admitted and how many SCSTs are there in the Central Government service?

How can the students belonging to SCST get best education in the slum areas? How can they get best tuitions from the best teachers who are working in the Kendriya Vidyalaya and in the Public Schools? How can you expect them to compete in the public examinations with those candidates who have got their education from the Public Schools?

13.30 hrs.

[SRRI VASANT SATHE *in the Chair*]

Sir, the difference is not seen in this house or in the high official ranks. Here we are getting on all right. We have asked all the Departments and the appointing authorities to conduct examinations separately for Scheduled Castes candidate and separately for Scheduled Tribes candidates before the examinations for the general candidates are conducted. If the examinations for the general candidates are conducted first and for the SC ST some time after you will find that the standard of the general candidates will be high. Candidates belonging to the SCST appearing for the competitive examinations will be of lesser inteligence and therefore such examinations should be conducted earlier than these conducted for the general candidates. Now, the whole of the appointing authorities have agreed to conduct examinations separately for SCST. I hope that the banking institutions will follow the same principle. Hon. Deputy Minister should see to it that necessary circular to this effect is issued to all the banking institutions. The Minister may kindly see to it that within a period of three years, quota

for SC ST candidates is completed in these institutions as time bound programme. Do you know where we stand? In the field of services the percentage of SC is 2.29 and the percentage of ST is 0.39. This is the plight of our community. But people say that they have done many things, a lot of things for the SC ST. Therefore, in the line of the policy adopted by the U.P.S.C. to conduct examinations separately for the SC ST, we have requested that banks should also have pre-examination centres to recruit SC ST candidates as in the case of IAS and IPS stated before. They have agreed to do so and they are waiting for the orders to be issued by the Government. I request you kindly to see that the orders to this effect are issued at a very early date. Another suggestion I would like to make is that Clause 4(1) of the amending bill may be modified to include two persons from SC ST in the total number of eight members of the Commission. In the UPSC also there are two highly qualified Members, one belonging to SC and the other belonging to ST. They are Ph.Ds. Here also in your recruiting Commission I would request you to include one Scheduled Caste member and one Scheduled Tribe member. I may also point out that there is no dearth of SC ST persons to serve the Commission. Mrs. Rohatgi, I have examined all your banks and I have found that they are all lagging behind in the recruitment of SC/ST candidates. I request you to set a particular date, say two years or three years, and by that date the reservation obligations should be fulfilled by all the banks. There is no dearth of talents in our community, only the mental reservation should be removed.

With these words, I congratulate you for bringing forward this Bill and hope that our community will be taken care of by you.

PROF. NARAIN CHAND PARASHAR (Hamirpur): Sir, in the very beginning I would like to extend a word of thanks to the hon. Deputy Minister, through you, for bringing this long awaited measure.

Perhaps, you might be remembering Mr. Chairman, that in April, 1972 you and I were among 206 Members of Parliament who made a representation to the hon. Minister at that time, Shri Y. B. Chavan, for the appointment of a Parliamentary Committee to examine the recruitment policy of the banks and we were hoping that the mess which had been going on even after nationalisation, would be brought to an end. Three years is a long period and after three years 206 Members of Parliament have found that their voice has been heard. Anyhow, the appointment of this Commission will result in some healthy practice so far as recruitment is concerned. It would not be out of place to refer to the practice, the mess that had been prevailing in the past. I quote from the Report of the Banking Commission, page 350, para 14.9. It says:

> "Recruitment at Clerical Level—The recruitment policies followed by Indian banks in the past had hardly any scientific basis. In several cases minimum qualifications were not insisted upon and even non-matriculates were recruited for clerical posts. There was no proper evaluation of capacity and aptitude and often relationship, caste, community and recommendations played a big part in selecting persons."

Now, this speaks for itself, I would again refer to a document which is known as 'New Trends in Banking'. I think, this is the latest publication. When I come to recruitment in public sector banks I find these remarks:

> "When banks were in the private sector, they were naturally keep to restrict their recruitment to a particular group of candidates, sponsored by their friends, clients and employees, on the ostensible ground that trust is an important requirement in banking."

[Prof. Narain Chand Parashar]

These were the clients who were sheltered away even from the Parliamentary committees in the name of secrecy. And in the name of trust misdeeds were done on a large scale. Between 1969 and 1972 as many as 85,000 persons have been provided with employment in public sector banks without any competitive examination and without any common recruitment. An army of 85,000 persons had been mustered into the nationalised banks ostensibly to serve the nation on this very criteria which, I hope, is still continuing. I would request the Minister, through you, to find out as to what has been done to the existing people who were recruited on the basis of relationship, caste, community and recommendation and what is the answer to those young Graduates who have qualified but do not have the privilege of belong to the circle of relationship, caste, community which was demanded in these banks. This is a serious question. At least, they must be given some sensible training in human behaviour; and they must be shown that banking is a service-oriented programme. It is not a place for pleasure, where you can draw fat salaries and declare strikes at the slightest provocation, or even without provocation, even when you happen to be the highest-paid in the land. I would like to quota further; and also to say that these are the remarks which these people are supposed to have accepted while agreeing to sponsor the legislation for this Commission:

> "Whole accepting the recommendation for setting up of an independent common recruitment agency, it has been decided for administrative reasons and particularly in view of the large numbers involved in clerical recruitment that the common recruitment agency may, to begin with, confine itself only to recruitment of junior officers in the nationalised banks. The procedure for recruitment of clerical staff in banks is, however, kept under constant review...."

Which review? That review which suits them; not the one which suits the candidates, but those who manage the recruitment. It says further:

> "With a view to keep it not only absolutely fair and impertial..."

But now, something has to be done. What is the new slogan? It goes on:

> "but also to meet the employment aspirations...."

Here is the long-needed sentence, for which 206 MPs. were itching:

> "....of the people of the area where the bank offices are operating."

At last, the high wisdom has dawned on the high personnel of the banking department and the bank managers and directors and all these people, that the area where the bank is situated, should also be somehow linked to the bank, or to the branch. Mr. Chairman, this bill for the Service Commission, I am sorry to state, does not provide for even this hope that has been there, except that there is some vague reference in this documents to the employment exchanges. But what goes on the employment exchange is sheer mockery, because when you talk in terms of English, you forget the native language and the people of India, who hardly know what English language is. Not more than 5 per cent in India are conversant with English language. A majority of your clients and a majority of your borrowers are people who know only regional languages. I am sure, Mrs. Rohatgi, you would be giving a new gift to this country in this period of Emergency, if you announce that the examinations to be conducted for recruitment to banks will not insist upon the compulsory knowledge of

English; and further, that the knowledge of the local or regional language will be a 'Must'. Otherwise, you will ensure that no person is selected in Maharashtra who does not know Marathi; and no person is selected in Tamil Nadu who does not know Tamil. This is a very strange state of affairs in India that we go on thinking in terms of national development and all the time we are gravitating towards our own kith and kin either in the name of a universal language or in the name of efficiency or proficiency. God knows what. So, I suggest that the proposed test and the proposed rules for this test should take into consideration the fact that there are many schools in India to-day where the students do not know English, that they are coming only with the national language or any other languages. They may say that other languages are also national languages; I do not object; but they should not be debarred on this very score. Secondly, I want to support what Mr. Basumatari had said; because though I do not belong to that section of society, *viz.* the scheduled castes, I feel that when we make promises—and when in the Emergency we promulgate this 20-point economic programme, one of our most important programmes is that we shall take care of the weaker sections of the society; how do we take care of the weaker sections? We take care of them by not allowing a first class MA to be selected! That is the way our bureaucracy has been taking care of the weaker sections of the society. I want to ask the Minister whether this procedure will change or not. If it is not changed, then it will be a sad day for the country. Here I would very much recommend what the hon. Member Shri Basumatari has suggested. If you want to do justice to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, you must have separate examinations for their recruitment. Otherwise, there is no hope of their getting fair representation. When you can recommend and create special training centres for recruitment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes to the IAS, IPS and other civil services, how is it that you neglect them so far as banks are concerned. If you do not want the present position to continue, you must create training centres for the recruitment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates for employment in banks on a crash programme basis.

The number of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in employment in the various public sector banks has increased. But what has been the increase since 31st December 1970 when the figure was 47? According to this document the number has gone up to 116. In the case of clerks, 85,000 candidates have been recruited. The number of Scheduled Caste and Tribe candidates has gone up from 697 to 2,827. Is it fair representation? If 20 per cent of the people are from this section of the society, then for 85,000 their representation should come to 17,000. But, instead of 17,000 we have got 2,827 on 31st December 1972, according to this document, which is a Government of India publication. Therefore, the representation for the weaker section is woefully inadequate and something drastic, as suggested by Shri Basumatari, should be done so that thy can feel that they are given their due.

Shri Jarilurrahman raised a point when some people had some doubts in their minds. Clause 6 of the Bill says;

> "The Central Government may remove from office the Chairman or any member, who....
>
> (a) is adjudged an insolvent...."

He referred to the case of an officer, occupying the very high chair, who belongs to the Anand Marg. What prevent you from sacking that officer. Let Shri Jamilurrahman give the particulars and the House wants to know what action you have taken.

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI: I have requested him to give the particulars.

PROF. NARAIN CHAND PARASHAR: When you are banning Ananda Marg and RSS, how is it that shelters are created either in the Ministry of Finance or in the Banking Department where these people can sit tight and finance these institutions from outside. We want firm action to taken against these people, if it is legally feasible. Anybody who is detected to have any leanings or connections with the banned organisations, if proof is available, should be debarred from becoming a member of the Commission and, if it comes to the notice of the Government after selection, he should be removed as soon as it comes to the notice of the Government. We are not afraid of anybody. If the Ananda Margis have selected 50 persons to be killed and if some of us are in those 50 persons, it is all right, but we will not allow them to have sheltered existence in the air-conditioned offices of the Secretariate or in the banks. You must be very strict here and you must mean business. We want to be sure that the people whom you are going to select are men of integrity, who are committed to the 20-point economic programme.

Then you say that half of the members of the Public Service Commission must be from the banking industry. If you want experts to be associated with the selection, you can have them as advisers. When we select lecturers or professors, we always have advisers. But if you insist that half of them must be from the banking industry, or from people who have experience of banking, it is trying our patience a bit too much. We cannot believe that those who have not been in the banking industry are not able to understand the mysteries or intricacies of banking. We cannot agree for a moment that the other four of the eight members who do not belong to the banking department are in any way inferior to those who belong to the banking department. This clause is highly unfair. If you are particular of having people who have special aptitude for banking, you can have them as advisers. They will give you their advice. Whenever in an agricultural university we have to recruit a professor, we always have as advisers people who are trained in the field of agriculture. But to insist that only those people can select fit candidates for the banks who have their connections with the banking department is not right, especially in the context of the state of affairs prevailing in the banks, as I have read out from the Banking Commission Report, which states that candidates have been selected on the basis of caste, community, relationship, kinship, friendship, recommendation and so on. So, what right have you to put forward this recommendation here in this Bill that at least four members of the Commission must be from the banking industry. This is not a desirable provision and the sooner it is removed the better it is.

Lastly, what have you provided for the ex-servicemen ? You have referred to the recuritment and reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. But what about the ex-servicemen? Now they are included in "other categories". I wish they should also be mentioned in particular, like Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

One hon. Member suggested that the clause which provides for employment on compassionate grounds should be removed. I do not agree with that suggestion. If an employee of the banking department dies, a member of his family, his son or daughter, should be provided with employment on a priority basis on compassionate grounds. Here, an addition to "death". I would add "permanent disability", so that the family does not starve when he dies or is disabled. We may be angry or annoyed with an employee who is inefficient. But that annoyance should not be extended to his family in the case of his death.

Then, in the creation of regional offices, for heaven's sake please do not club the States. You consider it desirable that Manipur should be a full-fledged State which should have a High Court of its own and that Himachal Pradesh should have a High Court, a full-fledged Assembly and a Governor. Yet, you think that it does not deserve to have a regional office of the banks. Why is it so ? If you consider a particular area or particular region to be specially qualified to become a full-fledged State, to have a Governor, to have a University, to have a Public Service Commission and to have a full-fledged Assembly, what is the reason that it should not have a regional banking office? You must equate it with the other States so that the big States cannot dominate and so that the small States are not unrepresented by banks. I want to lay stress on the fact that every constituent State of the Indian union must have a region for itself in the banking structure. Whether their needs are big or small is immaterial; when they have their own Assemblies, High Courts and Public Service Commissions, they should have their regional banking offices.

Then, there must be a proper share of these posts for the local people. Otherwise if you create an all-India cadre for every post and make them transferable from one place to another there is scope for victimisation. The management can transfer one person from Kashmir to Kanyakumari. Or, if the bank manager or the Chairman happen to be from a particular State, he will select people from his own area and feel satisfied that he has done justice. The bank must be rooted in the soil; it must not float in the high seas. The recruitment policy should be so framed that preference will be given to the local people.

Then, there should be a report to the House every year about the recruitment that has been done, giving State-wise figures of employees in the bank, so that the people and their representatives know that people from their State are recruited in the bank and that the old practice or recruitment on the basis of kinship, caste, friendship, recommendation and relationship has been discarded once and for all.

With these words, I support the Bill.

श्री राम हेडाऊ (रामटेक) : सभापति महोदय, बैककारी सेवा आयोग विधेयक का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। बैंकों का व्यवसाय जो आज तक इस देश में रहा है, वह पूंजीपतियों के हाथ में रहा है। इतना ही नहीं आर्थिक क्षेत्र में जो वैस्टेड इन्टरेस्ट के लोग रहे हैं, उनके हाथ में यह धंधा रहा है और उसका परिणाम यह हुआ है कि पूरा संचालन उन्होंने आपस में बांट लिया, बराबर अपने अपने लोगों का उसमें नौकरी पर रखा, अधिकारियों के पद पर रखा और इतना ही नहीं, बैंकों में जो भी जमा होता था, उसका उपयोग भी निजी स्वार्थ के लिये किया। अब हमें उस परिस्थिति को बदलना है, इस दृष्टि से यह बिल बहुत महत्वपूर्ण है—ऐसा मैं मानता हूं।

इसमें नियुक्तियों के मामले में जो आयोग बैंको के नियन्त्रण के लिये बनाया जा रहा है, इसमें कुछ सतर्कता का बर्ताव बहुत अपेक्षित है। क्यों ? हमने देखा है कि राष्ट्रीयकृत बैंक हो या प्राइवेट सैक्टर में कोआपरेटिव बैंक हो, आज बैंकों के व्यवहारों में समानता का बर्ताव जनता से नहीं किया जा रहा है। इसमें दो वर्ग के लोग होते हैं। एक गरीब तबके के लोग जो आज तक बैंकों की ओर आकर्षित नहीं हुए, लेकिन जो दूसरे बड़े लोग थे, उन्होंने बैंकों से काफी फायदा उठाया, काफी पैसा उनको बैंकों से मिलता रहा। इसका कारण है—वहां का नौकरशाह उन्हीं के इशारों पर चलता था, उनको खुश रखने की कोशिश करता था और इसी दृष्टि से जाति, रिश्तेदारी के बलबूते पर वहां की नियुक्तियां हुई हैं।

[श्री राम हेडाऊ]

मिसाल के तौर पर मैं आपको बतलाना चाहता हूं—भण्डारा जिले में, जो महाराष्ट्र में आता है, वहां एक कोआपरेटिव सैन्ट्रल बक नामक संस्था है, जो कुछ महाभागियों ने 25–30 साल पहले स्थापित किया था। गांव के जो पूंजीपति लोग थे, वे ही उसके डायरैक्टर रहे, कुछ विशिष्ट जातियों के, वर्ग के लोग उसमें प्रमुख रहे और उन्होंने उस बैंक में जितने कर्मचारी भरे हैं, वे सब एक विशिष्ट जाति के थे। और उस बैंक का पूरा-पूरा लाभ आज तक वह उठाते रहे हैं। और आज भी यह स्थिति है कि वहां दूसरे लोगों को नौकरी पर नहीं लिया जाता है। उस बैंक की जिले में 18, 20 शाखायें हैं लेकिन शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब के लोग उस बैंक में नहीं के बराबर हैं। जिन महानुभावों ने इस बैंक को खोला वह सदा लाभ उठाते रहे तथा नये नये बैंक खोलते रहे। अभी अर्बन कोआपरेटिव बैंक उन लोगों ने खोला, जिसमें नौकरी देने के लिये एक एक व्यक्ति से दो, दो हजार रु० लिये गये। उनके दलाल इस काम के लिये हर वक्त तैयार थे। इस प्रकार जिनके हाथ में बैंक की सत्ता रही है उन्होंने इस का दुरुपयोग किया है। यह बात नहीं होनी चाहिये। इस बिल से उम्मीद है कि इस बात को रोका जायगा।

14 hrs.

अब मैं भर्ती के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। हम देखते हैं कि बैंकों में भरती के लिये एम्प्लायमेंट एक्सचेज से नाम मंगाये जाते हैं। किन्तु वहां भी एम्प्लायमेंट अफसर किस मनोवृत्ति का है इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है क्योंकि उसकी कारगुजारी को देखने का हमने अभी तक कोई यंत्र तैयार नहीं किया है कि वह सही ढंग से उचित और योग्य व्यक्तियों का नाम, जिस क्रम से नाम दर्ज किये गये हैं उसके अनुसार बराबर भेजता है कि नहीं। परिणाम यह होता है कि अगर वह अधिकारी एम्प्लायमेंट एक्सचेंज का जातिवाद को मानने वाला हुआ तो वह हेरफेर करके अपने आदमियों के नाम ही भेजता है, और जो बैंक के अधिकारी होते हैं उनसे उनकी तालमेल हो जाती है और वह बोलते हैं कि हमारे ही रिश्तेदारों के नाम भेजो, और वही लोग नौकरी में रख लिये जाते हैं। यह बात इसमें नहीं होनी चाहिये।

जो आयोग स्थापित हो रहा है यह रीजनल बैसिस पर भी होना चाहिये क्योंकि जो डायरेक्टर्स हम लेंगे नियुक्ति करने के लिये, जो आयोग में प्रमुख लोग लेंगे उनमें सामाजिक और राजकीय कार्यकर्ताओं का भी स्थान होना चाहिये। इसके साथ-साथ अर्थ-शास्त्र के प्रोफेसर आदि लोगों को भी, जो बैंकिंग के व्यवहार को अच्छी तरह से समझते हैं, कुछ तबदीली लाने के लिये अच्छी सिफारिश कर सकते हैं, ऐसे लोगों को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये। साथ ही आदिम जन-जाति के प्रतिनिधियों को भी इस कमीशन में स्थान मिलना चाहिये। और बैंक के अधिकारी तो रहेंगे ही। इस प्रकार से अगर इस आयोग को बनाया जायगा तो बैंक में कर्मचारियों की नियुक्ति करते वक्त जो अन्याय आज तक होता आया है उसको हम दूर कर सकेंगे।

वास्तव में नीचे के तबके के आदमी का उत्थान हमारे नये आर्थिक कार्यक्रम की बुनियाद है। बैंक की ओर गरीब आदमी आकृष्ट होना चाहिये। हम देखते हैं कि बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों का व्यवहार आने वाले आदमियों के साथ समान नहीं होता। देहात से जो गरीब काश्तकार आता है उसके साथ जो व्यवहार होता है उससे कुछ अलग व्यवहार वहां के पूंजीपतियों के साथ होता है। पूंजीपति जब बैंक में जाता है तो उसको वहां बैठने को कुर्सी दी जाती है, लेकिन काश्तकार के साथ ठीक ढंग से बात

ली नहीं की जाती, बैठाने की बात तो दूर रही । पीछे से आने वाले का काम पहले होता है और छोटे आदमी की उपेक्षा की जाती है । यह बात नहीं होनी चाहिये । बैंक और उसके कर्मचारियों का सम्बन्ध सीधे जनता से होता है इसलिये उनको जनता के साथ कैसा बरताव करना चाहिये, समानता का व्यवहार कैसे करना चाहिये, इसकी ट्रेनिंग भी देना बहुत जरूरी है । इस बिल को लाने में सरकार ने जो दिलचस्पी दिखाई वह उचित ही है, हालांकि इसको और पहले ले जाना चाहिये था । फिर भी यह सही कदम सरकार ने उठाया है ।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : अधिष्ठाता महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों की अत्यन्त आभारी हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर साढ़े तीन घंटे तक चर्चा की और हालांकि इस विधेयक का एक बड़ा सीमित दायरा था परन्तु उन्होंने बैंकिंग के सम्बन्ध में हर अंचल पर अपने सुझाव दिये हैं और टिप्पणी की है और जहां भी उन्होंने उचित समझा उनको अच्छी तरह से रगड़ा भी है । मैं खुश हूं कि इसी मौके पर कम से कम बैंक के सारे कार्य भार को अच्छी तरह से देखा गया और जहां कमी देखी गई उस पर प्रकाश डाला गया । मैं अपने साथियों का ध्यान जब राष्ट्रीयकरण किया गया था उस पहलू पर भी ले जाना चाहूंगी । राष्ट्रीयकरण के पहले क्या उद्देश्य हमारे सामने थे, किन मान्यताओं को लेकर के बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, कहां तक हम उस मंजिल तक पहुंचे हैं और क्या-क्या कमियां हैं, उनका निराकरण करने के लिये माननीय सदस्यों ने कुछ सुझाव दिये हैं । इसके अतिरिक्त सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये उन की भी चर्चा की गई । इसमें दो राय नहीं हैं कि सारे देश के आर्थिक ढांचे में राष्ट्रीयकृत बैंकों का एक बड़ा भारी कार्य-क्षेत्र है । हमारे माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि जो निजी क्षेत्र में बैंक हैं उनका राष्ट्रीकरण क्यों न किया जाय । सही है कि 80, 85 प्रतिशत बैंकों का काम राष्ट्रीयकृत है इसलिये जो उनका कार्य है वह जनता के सामने आता है, और उनकी सारी चीजें जनता के सामने आती हैं ।

जब राष्ट्रीयकरण किया गया था उस समय बैंक का नजरिया ही दूसरा था, उनका कार्य क्षेत्र दूसरा था, उनकी प्रणाली दूसरी थी, उनका ढांचा और मान्यताएं दूसरी थी । बैंक ग्रामीण इलाकों से दूर रहते थे क्योंकि उनका सम्बन्ध कामर्स, इंडस्ट्री और बिजनेस से रहता था । इसलिये उनका नजरिया उसी तक सीमित था । आपने देखा कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें 8 हजार थीं जोकि 6 साल में बढ़ कर 18 हजार हो गई हैं । और खुशी की बात यह है कि करीब-करीब 50 प्रतिशत शाखायें ग्रामीण अंचल में खोली गई हैं । ग्रामीण अंचल में उनका आगे बढ़ना, उनके दृष्टिकोण को बढ़ाना और व्यापक करना आवश्यक हो गया और इसीलिये उनकी शाखायें गांवों में खोली गईं । जनता की आवश्यकताओं को देखते हुए ऐसा किया गया । अभी हमारे पास बहुत से ऐसे ब्लाक्स हैं जहां शाखायें नहीं खुली हैं । राष्ट्रीयकृत बैंकों का कार्य-क्षेत्र यह भी है कि जहां-जहां ब्लाक हैं, जहां राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें नहीं हैं, हम ने पांच-छः राज्यों का ऐनालिसिस करके देखा है कि बहुत से ब्लाक्स ऐसे हैं जहां तीन हजार से भी कम वहां की आबादी है । राष्ट्रीयकरण के समय औसत पापुलेशन प्रति बैंक 65,000 थी, जो 6 साल के बाद घट कर 30,000 प्रति बैंक औसत पापुलेशन हो गई है । फिर भी हम इसको और कम करना चाहते हैं । किसी-किसी जगह औसत इससे कम पड़ता है और कहीं कहीं इससे अधिक

[श्रीमती सुशीला रोहतगी]

भी पड़ता है। जहां हमारे पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, जहां बैंकिंग की अधिक आवश्यकता है, जहां शाखायें कम खुली हैं वहां पर ज्यादा पदार्पण किया जाय यह हमारी इच्छा है। और इसी-लिये रोलिंग प्लान बनायी गई है जो तीन साल को ध्यान मे रख कर रैशनल स्ट्रक्चर तरीके पर परिवर्तन करने की कोशिश की जाती है जिस से राज्यों में जो असमानता है, राज्य के अलग अलग अंचलों में जो असमानता है उसको दूर करके एक सामंजस्य लाया जा सके। यह सब होते हुए, मान्यवर, मुख्य चीज यह है कि केवल शाखा खोलने से तो काम नही होता, काम करने वाले ढांचा से काम नही होता है बल्कि अंदर की जो आत्मा है, जो आदमी हैं उनमें काम करने की निष्ठा होनी चाहिए, आदमियों के काम करने के विचार होने चाहिये, दृढ़ता होनी चाहिए और सब से ज्यादा क्षमता होनी चाहिए कि जो वह अपना कार्य कर रहा है उसको अच्छी तरह से वह कर सके। इसलिए जब से राष्ट्रीयकृत बैंक बने हैं, उनके लिए निरन्तर ट्रेनिंग का काम बढ़ता चला जा रहा है। मैं कुछ आंकड़े सदन के सामने रखना चाहती हूं कि हमारा ट्रेनिंग का कार्य क्या हो रहा है। मैं आपको बताऊंगी कि सारे ही राष्ट्रीयकृत बैंकों के अपने अपने ट्रेनिंग के कार्य हैं, कुछ में कम है और कुछ में ज्यादा, मगर एक मशीनरी के रूप में, एक यंत्र के रूप में यह काम चल रहा है। मैंने शुरू में अपनी स्पीच में कहा था और जो आंकड़े हमारे पास हैं उन से यह सिद्ध हो जाता है कि हर साल हमारी ट्रेनिंग का कार्य बढ़ता चला जा रहा है और 1967 में राष्ट्रीयकरण से पहले जो एम्प्लाइज की ट्रेनिंग कराते थे, उनकी टोटल संख्या 1280 थी लेकिन जब से हमारी यह ट्रेनिंग शुरू हुई है, हो सकता है कि उसका कार्य कुछ ढीला रहा हो. उसमें यह संख्या बराबर बढ़ती जा रही है। 1973 में उन अफसरों की संख्या, जिनको ट्रेनिंग मिली है, 8,875 थी और क्लर्क्स की संख्या 14,986 थी, 1974 में अफसरों की संख्या बढ़ कर 16,880 और क्लर्क्स की संख्या 22,814 हो गई और इस साल जो ट्रेनिंग कार्य चल रहा है यानी 1975 में अफसरों की संख्या बढ़ कर 21,704 होगी और क्लर्क्स की संख्या 34,499। इस प्रकार यह ट्रेनिंग बराबर बढ़ी है परन्तु जैसा कि हम लोगों का विचार है और हम दृढ़-प्रतिज्ञ हैं कि बैंकों के माध्यम से, आर्थिक ढांचे को ठीक किया जाए और उसकी गति बढ़ाई जाए और ज्यादा से ज्यादा अंचलों तक इन सुविधाओं को ले जाया जाए, तो आज इस गति को बढ़ाना होगा और ऐसा करने के लिए कार्य-क्षमता, शैली और सभी चीजों का नवीनीकरण करना पड़ेगा। इसीलिए यह बिल आज आप के सामने आया है। माननीय सदस्यों ने जो यह कहा है कि इसमें विलम्ब हुआ है और ऐसे महत्वपूर्ण बिल को पहले आना चाहिए था, यह सही बात है लेकिन मान्यवर यह विलम्ब हमारी ओर से नहीं हुआ है और इसके जो कारण है वे आप में से बहुत से माननीय सदस्यों को मालूम है और आप को भी मालूम है। सरकार की ओर से यह बिल पिछले साल नवम्बर में सदन के सामने आ गया था और काफी एमेंडमेंट्स भी आ गये थे पर सदन में उस वक्त इस पर विचार नहीं हुआ और उसके कारण भी स्पष्ट हैं। आज इस पर चार घंटे का समय लगा है। उस वक्त भी अगर यह महत्वपूर्ण बिल सदन के सामने विचार के लिए आता तो माननीय सदस्य अपने विचार देते। कहना यह है कि अब जब यह निश्चय हुआ है कि इस तरह का कमीशन स्थापित किया जाए, तो कमीशन स्थापित करते वक्त माननीय सदस्यों ने बहुत से सुझाव दिये हैं, मैं उनको आश्वासन देती हूं कि उनके हरेक सुझाव पर अच्छी तरह से विचार किया जाएगा और सरकार चाहती है कि माननीय सदस्यों ने जो विचार

रखे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए, उस कमीशन की स्थापना होगी, परन्तु मौलिक रूप से मैं कहना चाहूंगी कि इसमें जो दो चार चीजें हैं वे यह है कि यू० पी० एस० सी० के मौडल पर यह बिल बना है और प्लानिंग कमीशन की रिकमेंडेशन्स के अनुसार इसको बनाया गया है ।

उम्र के बारे में जो जिक्र किया गया है और शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में जो बातें कही गई हैं, ये सारी ही चीज यू० पी० एस० सी० के जो नियम है उन्हीं के आधार पर होंगी । मौलिक रूप से उसी आधार पर यह चीज बनी है । यह जो कहा गया है कि कमीशन में एक सदस्य शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स का हो और उसके बारे में जो विचार रखे गये है उसके बारे में मैं अवश्य यह कहना चाहूंगी कि बिल में इस वक्त कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जो इस चीज को रूल आउट कर दे कि वह नहीं आ सकते । बिल में ऐसी कोई स्पेसीफिक बात नहीं की गई है परन्तु यह भी जरूर है कि इसके लिए कोई रोक भी नहीं है । जो विचार यहां पर प्रकट किये गये हैं और जैसे यू० पी० एस० सी० का कार्य चल रहा है, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, यह सब किया जाएगा ।

हमारे बसुमतारी जी ने बड़ा मार्मिक भाषण दिया और उस से मैं सहमत हूं कि जिस तेजी से राष्ट्रीयकृत बैंकों में शैड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को आना चाहिए था, वह नहीं हुआ । मैं इस को स्वीकार करती हूं, इसलिए नहीं कि सरकार की ओर से मैं ऐसा कहती हूं बल्कि एक मां की हैसियत से यह बात कहती हूं कि उन की जो दिक्कत है उस को दूर किया जाए । उन के दिल पर जो चोट है, वह मैं जानती हूं और मैं उन को आश्वासन देना चाहती हूं, मैं यह तो नहीं कह सकती कि इतने समय के अन्दर यह चीज हो जाएगी पर यह जरूर है कि इस काम में तेजी लाएंगे । उन्होंने कहा कि एक फर्स्ट क्लास शैड्यूल्ड कास्ट का लड़का है और सब तरह से क्वालीफाइड है लेकिन फिर भी उस को आज तक नहीं रखा है । मैं यह जरूर चाहूंगी कि यह चीज देखी जाए ।

सभापति महोदय : उन का कहना यह है कि क्या आप कुछ गाइडलाइन्स ले डाउन करेंगी कि आगे चल कर यह जो कमीशन बनेगा और वह जो रिक्रूटमैंट करेगा, उस में कोई परसेन्टेज उन की लेंगे ? ऐसी कोई गाइडलाइंस आप उन को देंगी ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मान्यवर, जैसा कि मैंने पहले कहा कि यह सारी चीज उसी मोडल पर है जैसा कि यू०पी०एस०सी० में होता है लेकिन इस में कोई रूलआउट करने वाली बात नहीं है ।

सभापति महोदय : यह तो निगेटिव बात हो गई । कोई पाजीटिव बात आप करेंगीं और कोई आश्वासन देंगी, जिस से उन को तसल्ली हो जाए ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : यह एश्योरेंस दे रही हूं पाजिटिवली कि माननीय सदस्यों ने जो यह कहा है कि शैड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का आदमी उस कमीशन पर हो, उस पर विचार किया जाएगा । जो कमीशन बनेगा, वह यू०पी०एस०सी० के मोडल पर होगा ।

नियुक्तियों के बारे में श्री इन्द्रजीत गुप्त जी ने कहा और कुछ लोगों के मन में यह आशंका है कि नई नियुक्तियां करने से क्लास 3 और 4 क्लास के लोगों का प्रोमोशन रुक जाएगा । यह चीज नहीं है । इस में केवल यह चीज है कि अभी जो सारा प्रमोशन बेसिस पर हो रहा है, उस में से फिलहाल 25 प्रतिशत जगहों पर ही नये नये लोगों को इनडक्ट किया जाएगा ताकि नया फ्रेश ब्लड भी आ सके जिस से

[श्रीमती सुशीला रोहतगी]

आज कल जो आकांक्षाएं हैं, आज कल जो विचार हैं और आज कल की सामायिक चीजें हैं, वे पूरी हो सकें ।

सभापति महोदय : आप को याद होगा कि बहुत से एड-हाक एपाइन्टमेंट्स हो जाते हैं जिन को बाद में रेगुलेराइज कर दिया जाता है । तो इस कमीशन के आने के बाद ऐसा कोई प्रावधान किया गया है कि इस तरह की जो कुछ दिक्कतें हैं, वे दूर हों ? उनका भी कोई इन्तजाम आप इस में करेंगी ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : एड-हाक के लिए प्रोविजन है ।

सभापति महोदय : पहले एड-हाक एपाइन्टमेंट्स हो जाते है और बाद मे उन को रेगुलेराइज किया जाता है ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मान्यवर, यह जो सारा काम है, जो रेगुलेशन्स बनेंगे, उन के अनुसार होगा और सारे प्रोविजन्स बिल में है । इस के अतिरिक्त मै यह कहना चाहती हूं कि माननीय सदस्यों को कोई शंका नहीं होनी चाहिए क्योंकि जो रेगुलेशन्स बनेंगे, वे गवर्नमेंट की एप्रूवल से बनेंगे ।

श्री पन्नालाल बारुपाल (गंगानगर) : मैं माननीय मंत्री जी में एक प्रश्न पूछना चाहता हूं हालांकि यह विषयान्तर होगा । हमारी प्रधान मंत्री ने 20 सूत्री कार्यक्रम घोषित किया है और उस से यह लिखा है कि कर्जों की माफ़ी होगी, भूमि मजदूर, छोटे किसान और दस्तकारो के कर्जों को वसूलने पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया जाएगा । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकारी कर्जे भी माफ़ होंगे या बनियों के कर्जे ही माफ़ होंगे ।

सभापति महोदय : यह सवाल कहां पैदा होता है । यह सवाल आउट आफ़ आर्डर है और इस का जवाब देने की जरूरत नहीं है ।

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI: The Commission is to make recomendation for appointment in the banks. The Commission will be the only source for selection of candidates for appointment in the banks.

यह जो आप ने प्रश्न किया, इन सब चीजों मे परिवर्तन करने का प्रयास हो रहा है और लोगों की राय से जितनी जल्दी जल्दी ये चीजे हो सकेंगी, उन को किया जाएगा ।

इस सम्बन्ध में मैं यह भी कहना चाहूगी कि आज जो कृषि क्षेत्र मे विकास करने के लिए, एक नया कनसेप्ट बना है और जिस पर वित्त मंत्री जी भी बोले है, यह जो सर्विस सोसाइटीज का नया कनसेप्ट है, केवल धन से वहां पर विकास नही हो सकेगा । इसलिये धन के साथ साथ वहां पर ऐसे आदमियो की नियुक्ति हो जो वहा पर जा कर इन्तजाम कर सकें और लोगों को साथ-साथ अपना कन्सलटेशन भी दे सके । इस तरह से सारी चीजो का सामंजस करने की बात है ।

मेरे ख्याल से इस के बाद कितनी चीजें और कही गई है जैसे कि स्टेगनेशन का प्वाइन्ट था प्रोमोशन अपोरचूनिटीज की जो बात थी या शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में जो बातें उठाई गई थीं, उन पर भी विचार किया जाएगा । एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आनन्दमार्गियों के बारे मे भी उठाया गया है । मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि इस में कोई भी, कभी भी और कहीं का केस चाहे क्यों न हो, अगर किसी आदमी का ग़लत चीज से किसी प्रकार का सम्बन्ध है, उस के टिकने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, पर मेरा निवेदन है कि जिन माननीय सदस्य ने इस चीज को उठाया

है, वह हमें स्पेसीफिक इन्सटांस, कोई भी हो, बगैर विलम्ब के पूरे प्रूफ के साथ दें ताकि हम कोई एकशन ले सकें। यह हमारा कर्तव्य है कि हमारे बीच में इस प्रकार की अगर कोई चीज है, तो उस को हम फौरन वहां से हटायें।

मेरा विश्वास है कि इस व्यवस्था से एक अच्छी परम्परा बनेगी, एक स्वस्थ कन्वेन्शन बनेगा, और बैंकों के राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य सार्थक हो सकेगा। मेरा विश्वास है कि सभी माननीय सदस्य इसको अपना समर्थन देंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : श्री स्टीफ़न ने बहुत ज़ोरों की धमकी दी थी। उस के बारे मे मंत्री महोदय ने कुछ नहीं कहा है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : स्टीफ़न साहब ने कुछ बात कही और उस का जवाब मेरे मित्र, श्री बनर्जी, ने दिया। माननीय सदस्यों ने अलग अलग विचार प्रकट किये हैं। दोनों दृष्टिकोण सामने आ गये हैं। मुझे इस के बारे में कुछ नही कहना है।

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill to provide for the establishment of a Commission for the selection of personnel for appointment to services and posts in certain banking institutions and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

The motion was adopted.

*Clause 2—(*Definitions*)

MR. CHAIRMAN: We now take up Clause by clause consideration. There are amendments to Clause 2; amendments Numbers 3 and 4.

Amendments made:

Page 2, line 15,—

for "constituted under" *substitute* "as defined in" (3)

Page 2,

after line 16, *insert*—

'(i) "regulation" means regulation made under this Act;' (4)

[*Shrimati Sushila Rohatgi*]

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That Clause 2, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted

Clause 2, as amended, was added to the Bill.

Clause 3 was added to the Bill.

Clause 4—(*Appointment and terms of office of Chairman and members*)

MR. CHAIRMAN: There are amendments Nos. 5, 6 and 7 to Clause 4.

Amendments made:

Page 2, line 41,—

for "or any other matter" *substitute* "or in any other matters' (5)

Page 2, line 45,—

for "experience of" *substitute*—"such experience for" (6)

Page 3, line 3,—

after "this section" *insert*—"and of section 5" (7)

[*Shrimati Sushila Rohatgi*]

*In view of Amendment No. 4 to Clause 2 adopted by the House, in clause 2, on page 2, in line 17, "(i)" was substituted by "(j)" and in line 19, "(j)" was substituted as "(k)" as patent errors under the direction of the Speaker.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That Clause 4, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 4, as amended, was added to the Bill.

Clause 5 was added to the Bill.

Clause 6 *Removal and Suspension of Chairman or the members from office in certain circumstances)*

MR. CHAIRMAN: We go to Clause 6. There is amendment by the Minister, No. 8. When you make the Bill, there seems to be more amendments than the Bill itself.

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI: The Bill was introduced last year and now we are discussing it.

MR. CHAIRMAN: From last year you had time to think!

Amendment made:

Page 4, line 13,—

after "functioning as" *insert*— "the Chairman or" (8)

[Shrimati Sushila Rohatgi]

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That Clause 6, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 6, as amended, was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: I think there are no amendments to clause 7. I shall put it to the vote.

The question is:

"That Clause 7 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 7 was added to the Bill.

Clauses 8 and 9 were added to the Bill.

***Clause 10-** *(Competitive examinations for appointment in public sector banks)*

MR. CHAIRMAN: There is one amendment to this clause.

Amendment made:

Page 5,—

for lines 19 to 24, *substitute*—

"Duty of Commission to hold competitive examinations for appointment to posts in public sector banks.

10. (1) It shall be the duty of the Commission to conduct examinations for appointments in each public sector bank to—

(a) posts in the clerical and allied cadres and the Junior officers' cadre, and

(b) such other posts of, or posts in the cadres of, officers as the Central Government may, by notification, specify." (9).

[Shrimati Sushila Rohatgi]

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That Clause 10, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 10, as amended, was added to the Bill.

Clause 11 was added to the Bill.

---

*In view of Amendment No. 9 to Clause 10 adopted by the House, for the words "Competitive examinations for appointment in public sector banks" occurring in the marginal heading to clause 10, the words "Duty of Commission to hold competitive examinations for appointment to posts in public sector banks" were substituted as patent errors under the direction of the Speaker.

Clause 12—(*Duty of public sector banks to communicate to the Commission the number of vacancies*)

MR. CHAIRMAN: There are amendments to clause 12.

Amendment made:

Page 5,—

for lines 34 to 44, *substitute*—

"Duty of public sector banks to communicate to the Commission of number of vacancies.

12 (1) It shall be the duty of very public sector bank to communicate to the Commission—

(a) all the vacancies in the clerical and allied cadres or in such other post or cadre as may be specified by the Central Government under section 10, and

(b) twenty-five per cent of the estimated total number of vacancies in the junior officers' cadre,

which are likely to occur during the unexpired portion of the calendar year in which this Act comes into force and thereafter, as soon as may be, after the commencement of each calendar year:

Provided that, in relation to the junior officers' cadre, the Central Government may, if it is of opinion that it is necessary so to do in the interests of the public sector banks, by notification, raise the percentage of vacancies to be communicated to the Commission to thirty-three and one-third per cent.". (10)

Page, 6,—

Omit lines 1 to 4 (11)

Page 6,—

after line 10, *insert*—

'Explanation.—In this Act, the expression "vacancy" includes a newly created post which has not been filled in'. (12)

[*Shrimati Sushila Rohatgi*]

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That Clause 12, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 12, as amended, was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: There are no amendments to clause 13. I shall put it to vote.

The question is:

"That Clause 13 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 13 was added to the Bill.

Clause 14 was addded to the Bill.

Clause 15— (*Communicated vacancies to be filled only on the recommendation of the Commission*)

MR. CHAIRMAN: There is amendment to this Clause.

Amendment made:

Page 6, line 43,—

for "communicated" *substitute*—

"required to be communicated" (13).

[*Shrimati Sushila Rohatgi*]

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That Clause 15, as amended, stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 15, as amended, was added to the Bill.

---

*In view of Amendment No 10 to clause 12 adopted by the House, for the words "the number of vacancies" occurring in the marginal heading to clause 12, the words "of number of vacancies" were substituted as patent errors under direction of the Speaker.

Clause 16- (*Power of Central Government to entrust other advisory functions to the Commission*)

MR. CHAIRMAN: There is amendment to Clause 16.

Amendment made:

Page 7, line 8,

omit "other" (14)

[*Shrimati Sushila Rohatgi*]

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That Clause 16, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 16, as amended, was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: There are no amendments to clause 17 to 28. I shall put them to the vote.

The question is:

"That Clauses 17 to 28 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 17 to 28 were added to the Bill.

Clause 29— (*Amendment of Act 14 of 1947*)

MR. CHAIRMAN: There is amendment to Clause 29.

Amendment made:

Page 9, line 25,—

for "1974" *substitute* "1975" (15)

[*Shrimati Sushila Rohatgi*]

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That Clause 29, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 29, as amended, was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: There are no amendments to Clause 30 to 33. I shall put them to the vote.

The question is:

"That Clauses 30 to 33 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 30 to 33 were added to the Bill.

Clause 1—(*Short title and commencement*)

MR. CHAIRMAN: There is amendment to clause 1.

Amendment made:

Page 1, line 6,—

for "1974" *substitute* "1975" (2)

(*Shrimati Sushila Rohatagi*)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That Clause 1, as amended, stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

The Enacting Formula

MR. CHAIRMAN: There is amendment to the Enacting Formula.

Amendment made:

Page 1, line 1,—

for "Twenty-fifth" *substitute* "Twenty-sixth" (1)

(*Shrimati Sushila Rohatgi*)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The title was added to the Bill.

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI: Sir, with your permission, I beg to move:

"That the Bill, as amended be passed."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill, as amended be passed."

The motion was adopted.

14.30 hrs.

EMPLOYEES' STATE INSURANCE (AMENDMENT BILL)

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI RAGHUNATHA REDDY): Sir, I beg to move*:

"That the Bill further to amend the Employees' State Insurance Act, 1948, and to incoroporate an explanatory provision connected therewith in Section 405 of the Indian Penal Code, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The Employees' State Insurance Act, 1948, provides, *inter-alia*, for certain benifits to employees in case of sickness, maternity and employment injury and for certain other matters in relation thereto. Medical care under the Act is also being made available progressively to families of insured persons. The Act was last amended in 1966. Since then a number of proposals for further amendment of the Act arising from recommendations of the E.S.I. Scheme Review Committee, 1966 and the Estimates Committee (Fourth Lok Sabha) are under consideration. These proposals will require a comprehensive amendment Bill. Meanwhile, I am placing before you for enactiment a few proposals of an urgent nature.

The Act applies, in the first instance, to non-seasonal factories run with power employing 20 or more persons. The coverage under the Act is at present restricted to those drawing wages not exceeding Rs. 500/- per month. This limit is considered very low in the context of the current wage levels in various industries. The situation has become worse, as fresh increases in wages are being made on account of inflation. As a result, there are instances where most of the labour working in a factory fall outside the scope of the Act and loses the valuable benefits conferred by it. There have, therefore, been persistent requests for enhancement of the wage limit for coverage under the Act. The E.S.I. Scheme Review Committee, 1966, had also recommended the rising of the wage limit for coverage under the Act to Rs. 1000/-. This recommendation has been accepted by the E. S.I. Corporation which is a tripartite body and has at its members, representatives of employers, workers, Central and State Governments, medical profession and Parliament. It is accordingly proposed to increase the wage limit for coverage of employees under the Act from Rs. 500/- to Rs. 1,000/- per month. This will bring the wage limit for coverage at par with the wage limit under Employees' Provident Fund Act, 1952 and the Payment of Gratuity Act, 1972.

The proposed increase in the wage limit would entail revision of the table of contributions and benefits in the first schedule to the Act. We are utilising this rates of contributions and benefits. The wage limit for exemption from employees' contribution is also being raised from below Rs. 1.50 to below Rs. 2/-.

The Employees' State Insurance Act, 1948, provides that the employer shall pay his share of contribution together with the employees' share deducted from their wages. Under Section 85, the employer is liable to penalties of imprisonment up to three months or fine up to Rs. 500/- or both in case of default in payment of contributions. Under the Act the employer is also required to submit certain returns and comply with certain other provisions. The penalties are imprisonment up to three months or fine up to Rs. 500/- or both. The working of the Act has revealed that the penal provision in the Act are not effective in checking defaults. The amount of arrears recoverable from employers has been increasing over the year. The increase in the amount of arrears has been criticised both in Parliament and outside. It is, therefore, proposed to provide for enhanced and more deterrent penalties for default in payment of contributions.

Some of the other amendments proposed in the Bill are:

*Moved with the recommendation of the President.

[Shri Raghunatha Reddy]

(i) Raising the wage limit for creation of posts by the ESIC from Rs. 500 to Rs. 1200;

(ii) To provide that the buyer and transferee of an establishment in respect of which dues payable under the Act are pending shall also be liable to pay all dues; and

(iii) To clarify that any contributions, deducted from the employees' wages by the employer under the Act shall be deemed to be entrusted to the employer within the meaning of sec. 405 of the Indian Penal Code.

It is a matter of satisfaction that as against 1.5 lakh workers, who were intially covered in the two centres in Kanpur and Delhi in 1952 the scheme now covers 49.47 lakhs of employees in 376 centres, with the total number of benificiaries exceeding 190 lakhs including insured persons.

You will also be glad to know that the Corporation has recently decided to extend the scheme to the following new sectors of employments in a phased manner over a period of five years:

(i) Factories using power and employing 10 to 19 workers and non-power using factories employing 20 or more persons;

(ii) Shops, hotels and restaurants, theatres and cinemas, roads motor transport establishments, commercial establishments comprising banks, insurance and newspapers establishments and mines and plantations employing 20 or more persons.

During 1974-75, about 1-1/2 lakhs of workers have been brought under ESI coverage in these new sectors and in 1975-76, it is expected to bring in between 3 to 4 lakh workers. Necessary arrangements for extension of the scheme to some or most of new sectors of employment other than banks, insurance companies, mines and plantations in different areas are being made by the State Governments in consultation with ESIC. In regard to banks, insurance companies, mines and plantations the extension of the scheme will be taken up in later phases.

I now move that the Bill to amend the Employees' State Insurance Act 1948 be taken into consideration. I have no doubt that hon. members would appreciate that the Bill is a most non-controversial Bill and I hope it will be passed in the shortest possible time

MR. CHAIRMAN. Motion moved:

"That the Bill further to amend the Employees' State Insurance Act 1948 and to incorporate and explanatory provision connected therewith in section 405 of the Indian Penal Code, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration".

DR. RANEN SEN (Barrackpore): I welcome this Bill. The working class movement was for the last ten years demanding some such Bill which would actually help the workers to get the benefit of the ESI scheme.

Having said this, I have to say that this amending Bill has not gone far enough to satisfy the working class as a whole, to satisfy their demand for a thorough overhaul of the provisions of the Act. The hon. Minister has said it was last amended in 1966. But after 1966 what has happened. Not only the Estimates Committee but other bodies also made certain suggestions in regard to this particular Act. The suggestions were that suitable amendments have to be introduced. Perspective planning by ESI itself had made certain suggestions nearly two years ago. As far as I remember, it was in the latter part of 1973. But as yet, those suggestions have not been accepted by Government. Those suggestions, some of them at least have not found a place in this amending Bill.

Take for example, one of their suggestions, in regard to Central contribution.. Now there is complete control of the Union Government. I have no objection to this control by the Union Government, but I as a trade unionist know that the Central Government do not make any contribution to the ESI scheme. The perspective planning also suggested that the Central Government should make some contribution. There was the question of hospitals. The number of hospitals and the number of beds have both increased but the number of workers covered under the Act has also increased. Perpsective planning asked for 11 beds for 1000 workers; at the present moment only four beds are available per thousand. Family members of the insured persons are not covered in the scale in which they should be covered; family members also require hospitalisation.

When I speak of the trade union moment, I speak of the trade union moment as a whole irrespective of political affiliations. There is two-days waiting period. Workers have suffered and the trade unions have gone into this question and said that there was no necessity for this. So many representations have also been made to the ESI. But nothing happened. Many other points were suggested by the working class to improve the scheme of working of the Act but Government have not thoroughly gone into them. Still I should say that a very bold step had been taken by the Minister and he deserves congratulations. People who will be getting pay upto Rs. 1.000 will be covered by the ESI Act. This will go a long way to removing the grievances of the workers.

I shall now turn to the provisions of the Bill. Clause 4 seeks to amend section 85 of the Act. The original section says: ".....shall be punished with imprisonment which may extend to 3 months or with fine which may extend to Rs. 500 or with both..." wherever the provision is for imprisonment or fine, invariably the court imposes fine and no punishment in the form of imprisonment is given to the employer or the defaulting person.

MR. CHAIRMAN: Even when it is given, it is till rising of the court.

DR. RANEN SEN: In the Bill it is now provided, "...imprisonment for a term which may extend to six months but it shall not be less than three months..." It is a very good change indeed. In case of failure to pay the employees' contribution which has been deducted by him from the employees' wages, that is the punishment. It is a bold provision; it is timely and proper. Then it goes on to say "...it shall not be less than one month in any other case..." That is also a very good thing. Then it says, "...shall also be liable to a fine which may extend to Rs. 2,000." Another good point is there. But with all this a provision is added to it. In Bengali there is a saying that a whole potful of good milk is spoiled by one drop of Cow's urine.

"Ek ghoti bhalo dudhe ek phonta garur chona parle sab dudh nasta hoi."

I was drawing the attention of the Minister to this provision it shall not be less than one month in any other case and the fine may extend to Rs. 2,000. Section 4—Amendment of section 85—

"and shall also be liable to fine which may extend to two thousand rupees:

Provided that the court may, for any adequate and special reasons to be recorded in the judgement, impose a sentence of imprisonment for a lesser term or of fine only in lieu of imprisonment;"

Sir, why is this provision necessary? Now, it is known that the judiciary is not impartial particularly when the question of employers and employees relations come. This is against the

[Dr. Ranen Sen]

workers. INTUC, Hind Mazdoor Union and everybody opposes this provision. Therefore in adding this provision what happens is that the judge is free to impose any other punishment simply because he records this as a special reason. In that case one has to go to higher court and that means litigation. What is the necessity? Then again in Sub-Section(ii) it is stated as—

> "(ii) where he commits an offence under any of the clauses (b) to (g) (both inclusive) with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both."

Again there is a big lacuna because in the original Act 85 it is stated—

> "(a) fails to pay any contribution which under this Act he is liable to pay, or.. ."

That is dealt with very strongly and very firmly. I agree. But for other points, that is, 85(b) to (g) for violating all these clauses, the punishment is for a term which may extend to six months. That means again "extend to six months or with fine which may extend to one thousand rupees or with both." I say that fine may be imposed which may be Re. 1/-. It depends on the Court. Now, what are the things which have been mellowed down or softened down or wittled down? Now, 85 (b) reads as follows:

> "(b) deduct or attempts to deduct from the wages of an employee the whole or any part of the employer's contribution, or..."

This is condoned more or less. Then 85 (c) reads like this.

> "(c) in contravention of Section 72 reduces the wages or any privileges or benefits admissible to an employee or..."

This is also condoned. Now let me read what is there in Section 72 of the Act. Section 72 reads like this.

> "No employer by reason only of his liability for any contribution payable under this Act shall directly or indirectly reduce the wages of any employee or except as provided by the regulations,...'

That means there is another crime which is condoned in this Act. Similarly there are three or four other things. For example 85(e) reads as follows:

> "(e) fails or refuses to submit any return required by the regulations, or makes a false return, or..."

This is also a crime and this is also condoned. Condoned in what way? Condoned in this manner that for this offence also, punishment may be imprisonment which may extend to six months or with fine which may extend to one thousand rupees or with both. This means that the imprisonment may also be only till the rising of the court or a fine which may be one thousand rupees or Rs. 10/- or even rupee one. Therefore, in clause 4, the earlier portion has been dealt with very firmly but the latter portion has been diluted. The employers will take recourse to this loophole and this will go against the interests of the workers.

A new section 85A is sought to be added. It reads:

> "Whoever, having been convicted by a court of an offence punishable under this Act, commits the same offence shall, for every such subsequent offence be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine which may extend to two thousand rupees or with both."

First time he is punished and again he commits the same offence for a second

time. It means, the fellow is abandoned criminal. For him also it is either TRC or a fine of Rs. 5 or Rs. 10. I do not understand this softness for people who go on committing the same offence. There is a proviso:

> "Provided that where such subsequent offence is for failure by the employer to pay any contribution which under this Act he is liable to pay, he shall for every such subsequent offence, be punishable with imprisonment which may extend to one year but which shall not be less than three months and shall also be liable to fine which may extend to four thousand rupees."

The earlier provision and the proviso are contradictory. I do not understand the legal complexity of it. I hope the Minister will explain it.

A new section 85C is sought to be added, which reads:

> "Where an employer is convicted of an offence for failure to pay any contribution payable under this Act, the court may, in addition to awarding any punishment, by order, in writing, require him within a period specified in the order (which the court may if it thinks fit and on application in that behalf, from time to time, extend) to pay the amount of contribution in respect of which the offence was committed."

Why should the employer go scot-free by paying that particular amount? Why should there not be a fine for this failure?

Therefore, though this amending Bill has dealt with one of the basic things properly, I feel some of these offences should have been dealt with more firmly, without trying to condone them.

The table at the end is an improvement over the previous one. Below Rs. 2, the worker does not have to pay anything; But an employee getting Rs. 2 and above but below Rs. 3 has to pay 40 paise a day. That is to say, if an employee gets Rs. 2 per day, he has to pay 40 paise and ultimately the amount he gets as a worker is only Rs. 1.60. You can understand that this is rather difficult for a worker if this deduction goes on. I do not want to move any amendment. As I have said, this is a good amending Bill in spite of defects, flaws and lacunae. I want to draw the attention of the Minister to the fact that if 40 paise per day is deducted from an employee's salary on account of ESI, how does he maintain his family. Many workers might be getting Rs. 2/- per day and to pay 40 paise per day is very difficult for him.

SHRI RAGHUNATHA REDDY : I think, this amount is not per day but per week.

MR. CHAIRMAN: Is it on basic salary or total.

SHRI RAGHUNATHA REDDY: On total.

DR. RANEN SEN: Then, I stand corrected. I with draw what I have said on this.

Having said this, I again support this Bill and I congratulate the Minister for bringing forward such a bold amending Bill. I hope, it will be accepted by the working class as a whole.

श्री रामसिंह भाई (इंदौर) : चेयरमैन साहब, मैं आप का बड़ा आभारी हूं, मेरी पार्टी के सदस्यों में से प्रथम आपने मुझे बोलने का मौका दिया है । साथ साथ दुखी हृदय से मैं मंत्री महोदय को भी मुबारकबाद देता हूं—कम से कम इतने वर्षों के बाद आपने संशोधन करने की हिम्मत की है ।

[श्री रामसिंह भाई]

श्रीमन्, 1948 में जब यह योजना अमल में आई थी, तब हम और मजदूर बड़ी खुशियां मना रहे थे और यह समझते थे कि सरकार ने हमारी एक बहुत बड़ी जवाबदारी अपने ऊपर ले ली है, क्योंकि दरअसल में यह योजना एक बहुत सुन्दर योजना है, मजदूरों के लिये एक कल्याणकारी योजना है। इससे मजदूरों को कई बैनिफिट्स मिलते हैं। मैं मजदूरों में काम करने वाला एक कार्यकर्ता होने के नाते भलीभांति समझता हू कि यह कितनी सुन्दर योजना है कोई मजदूर लम्बी बीमारी में फंस जाय तो 56 दिन तक की बीमारी की छुट्टी का उस को वेतन मिलता रहेगा, उस के परिवार को मैडिकल ट्रीटमेन्ट मिलती है, वह किसी कारण से अपग हो जाये तो उस को उस का बैनिफिट मिलता है, एक्सीडेन्ट का पैसा मिलता है, इस में बहुत सी अच्छी अच्छी बात है, यदि उन पर अमल कराया जाय या अमल कराया गया होता तो यह एक बडी सुन्दर योजना साबित होती और हमारे श्रम विभाग का नाम हो जाता। लेकिन, श्रीमन्, इस योजना के प्रति श्रम विभाग ने बहुत लापरवाही बरती है—मुझे कहते हुए बड़ा दुख होता है—आज इस योजना की यह हालत है जैसे पाच पाडव के बीच में द्रौपदी की हालत थी। वह यह ही नही समझ पाई कि मेरा पति कौन है।

पाचो पाडव उसे अपनी पत्नी मानते थे और वह पाचो को अपना पति मानती थी इसलिये उस का चीर खीचने वाले बहुत हो गये। यही हालत इस योजना की है। केन्द्र सरकार ने इसकी जवाबदारी ली है और इस योजना के अन्तर्ग 44 पैसे से लेकर 3.75 पैसे प्रति सप्ताह मजदूरो के वेतन में से चदे की कटौती होती है। अभी इन्होंने इस की दर को बढ़ा दिया है, इसलिये यह अमेंडमेंट लाये हैं क्योंकि मजदूरों का कंट्रीब्यूशन जो बढ़ गया है। लेकिन इस योजना की देख भाल कौन करता है? आप ने कोरपोरेशन बनायी, इस कारपोरेशन के अन्तर्गत बैनिफिट काउन्सिल है जो यह देखती है कि क्या क्या दवाये होगी, चंदे का पैसा आप के पास आता है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है और वहां भी श्रम विभाग और हैल्थ डिपार्टमेंट दोनों अलग अलग देखते है। हम शिकायत किस से करें? इस योजना के अन्तर्गत शुरू में बडे बड़े अस्पताल बने। लेकिन आज वहां उनमें झाड़ू लगाने वाला नही है, डाक्टर नही है, लेडी डाक्टर नही है। मजदूरो से कंट्रीब्यूशन आप हर सप्ताह लेते है और वह चन्दा बराबर मालिक काट रहे है, इस के बाद भी जिस दवाखाने मे वह मजदूर जाते है वहा डाक्टर भी नही और दवाइया भी नही। 75 परसेंट इस योजना के अन्तर्गत बीमाशुदा मजदूर प्राइवेट डाक्टरो के पास इलाज के लिये जाते है। और यही कारण है कि बम्बई मे अभी भी पैनल सिस्टम चलता है, मास्स सिस्टम नही है। गुजरात मे अभी दो तीन साल से लागू की है। आप 500 की जगह 1,000 रु० तक मासिक वेतन पाने वाले पर लागू कर रहे है। इसका श्रय आप को नही है, बल्कि प्रधान मत्री जी को है।

15 hrs.

500 रुपये आप ने किस समय रखा था? 1948 मे जब यह योजना अमल मे आयी थी तब बम्बई शहर मे 50 से 58 रु० डी०ए० था। आज 400 रु० मे 435 रु० तक डी० ए० प्रति माह मजदूर को मिलता है। यानी कौस्ट आफ लिविंग इन्डैक्स बढ़ने से मजदूरो को महगाई भत्ता बढ कर मिलता है। इसलिये 400 रु० महंगाई भत्ता बढ़ जाने से उन श्रमिको का वेतन 500 रु० से ऊपर चला गया, इसलिये इस योजना का जो कंट्रीब्यूशन कटता था वह कटना बन्द हो गया और कारखानो में जिनके एक्सीडेंट्स हो गये

हैं, एक्सीडेंट से मर गये हैं उन्हें मुआवजा नहीं मिलेगा ? 1972 से मैं इसके पीछे पड़ा हूं कि 500 से 1,000 रुपये की सीमा की जाय और अभी इसी महीने की 8 तारीख को मैं प्रधान मंत्री जी से मिला और उन से कहा कि 'यह हाल कारखानों में हो रहा है, हमने श्रम मंत्री को बारबार कहा कि इस में संशोधन कीजिये, श्रम सलाहकार समिति ने भी यह कहा कि इस का आर्डिनेंस निकालना चाहिये, लेकिन कुछ नहीं किया गया ।' मैं आभारी हूं प्रधान मंत्री जी का उन्होंने कहा कि आप मुझे अभी लिख कर दीजिये, मैं ने वैसा किया जिस के फलस्वरूप यह बिल, जो नहीं आने वाला था, वह आज यहां आ गया । मैं प्रधान मंत्री जी का आभारी हूं कि जो 20 सूत्री कार्यक्रम उन्होंने देश के सामने रखा है उस के इम्प्लीमेंटेशन की जवाबदारी सब से ज्यादा श्रम विभाग पर आती है ।

आप ने बिल में सजा तो बढ़ा कर रख दी तीन महीने से 6 महीने की, लेकिन 948 से ले कर अभी तक क्या एक भी मिल मालिक जेल में गया है ? आज मैनेजमेंट के पास फंड जमा कराने के लिये काटा गया पैसा पड़ा हुआ है लेकिन जमा नहीं किया गया । मैनेजमेंट तो अपनी सर्विस में हथकड़ी मैनेजर तक रख लेगे हैं जिन का काम ही यह है कि कानून कायदे के मुताबिक जो सजा हो वह जेल में चला जाय । इस से काम नहीं चलेगा । जब तक आप मैनेजिंग डायरेक्टर को जेल नहीं भेजते तब तक इस का कोई असर नहीं होगा ।

सभापति महोदय : आप को डरने का कारण नहीं है इस में भी सजा नहीं होने वाली है ।

श्री राम सिंह भाई : आज, 1,000 रु० आप ने कर दिया । लेकिन जिन पर यह योजना लागू थी और मंहगाई भत्ता बढ़ जाने के कारण 500 रु० से ज्यादा जिनका वेतन हो गया उन को इसके पहले बीच में जो मुआवजा नहीं मिला है, जो श्रमिक ऐक्सीडेंट के कारण मारे गये, जब से उन का कंट्रीब्यूशन कटना बन्द हुआ, तब से क्या आप इस अमेंडमेंट को अमल में लायेंगे ? क्योंकि बीच में जो मजदूर ऐक्सीडेंट से मारे गये हैं उन के परिवार वालों को कुछ नहीं मिला है ।

सजा के बारे में मेरा निवेदन है कि कारावास आदि से हम अच्छी तरह से परिचित हैं, और मिल मालिक भी बहुत अच्छी तरह से परिचित है कि उन का कुछ नहीं होने वाला है । जिन्होंने कंट्रीब्यूशन काटा है उस के बाद भी पूंजीपति की शोषण नीति से मजदूरों को कोई फायदा नहीं मिला है । मैं एक मिल का उदाहरण देता हूं कि 1966 में इस कारखाने ने ई० एस० आई० की 5,07,978 रु० की रकम जमा नहीं कराई । उस का क्या हुआ । उस साल मजदूरों को ट्रीटमेंट नहीं मिला, चंदा देने पर भी इस योजना का कोई फायदा नहीं मिला । इसी कारखाने ने 1967 में 9,20,579 रु० मजदूरों से काटा लेकिन उस को जमा नहीं किया । 1969 में 14,74,585 रु०, 1970 में 19,10,169 रु०, 1971 में 26,57,209 रु० 1972 में 31,55,392 रु० मजदूरों की तनख्वाह से काटे गये लेकिन सरकार के खजाने में जमा नहीं किया गया जिस की वजह से मजदूरों को कोई लाभ नहीं मिला । लेकिन आप चुपचाप बैठे हुए हैं । आप बताये कि हमें इस योजना से क्या फायदा है ? इस से तो अच्छा है कि यह कानून न हो तो मजदूर मालिक से मैदान में निपट लेंगे । ऐसा कानून बना कर मजदूरों को क्यों चकरा रहे हैं । करोड़ों रु० प्रोवीडेंट फंड के इस श्रम विभाग की लापरवाही के कारण स्वाह हो गए । और अगर वह कानून नहीं होता तो या तो हमारा प्रोवीडेंट फंड नहीं कटता, और अगर कटता तो हम जमा करवा लेते । एक ही

[श्री रामसिंह भाई]

कारखाने की बात की है, मैं दूसरे की भी बात बताना चाहता हूं।

एक दूसरा कारखाना है और वह है स्वदेशी काटन मिल, जिस में 1969 में 5,21,24 ,रु० 1970 में 9,44,493, रु० 1971 में 13,69,723, 1972 में 15, 23,181 रु० और 1973 में 15,36,400 रुपये है। मैं आप के सामने एक नहीं ढेर से कारखानों के मामले रख दूं। एक ही कारखाना नहीं है। बम्बई का आलीशान इंडिया यूनाइटेड की कितनी रकम बाकी है जिस में लगभग 12 हजार मजदूर काम करते हैं। (व्यवधान) . . . वह सरकारी हो या प्राइवेट। मजदूरों का पैसा कटता है। आप ने कानून बनाया है, उस का फायदा-मजदूरों को मिलना चाहिए वे चाहे सरकारी हों या गैर-सरकारी। मैं तो कहता हूं कि सरकारी में तो उन के साथ अच्छा व्यवहार और उनका अच्छा प्रोमोशन होना चाहिए और अन्य भी सहूलियतें मिलनी चाहिए। मेरा सिर झुकता हैं मैं प्राइम मिनस्टर से मिला। उन्होंने जब मेरी बात सुनी तो कहा कि आप अभी लिख कर दीजिए और उस के बाद आज यह बिल आ गया। यह लाखों लोगों के जीवन का सवाल है और प्रधान मंत्री जी का हृदय उन के लिए द्रवित है कि उन को फायदा मिलना ही चाहिए। जो गरीब, पिछड़े हुए लोग हैं उन को फायदा क्यों नहीं मिलना चाहिए लेकिन यहां तो साहब यह हाल है कि पूछिये नहीं। श्रीमान्, मेरा यह निवेदन है कि आप की ये सारी बातें है और योजनायें है लेकिन इस पर अमल क्यों नहीं होता है और अमल के लिए आप क्या कर रहे हैं ? मैं श्रम विभाग को जब पत्र लिखता हूं और वह सीरियस पत्र होता है तो उस का या तो जवाब मिलता ही नहीं है और अगर मिलता है तो यह लिखा होता है "विचाराधीन" है, लेकिन मैं लिखता हूं कि प्रोविडेंट फंड के लिए और जवाब मिलता है ग्रेच्युटि के बारे में। ग्रेच्युटि का मामला मैं ने उठाया ही नहीं। मैं ने तो प्रोवीडेंट फंड के लिए पत्र लिखा है और वे जवाब देते हैं कि ग्रेच्युटि के लिए विचार किया जाएगा। ऐसे मेरे पास पत्र हैं। मुझे चिंता होती है और मैं इसलिए बहुत चिंतित हूं क्योंकि मैं चौबीसों घंटे मजदूरों में रहता हूं। उन के बीच में खाता हूं, उन के बीच में रहता हूं और उन की भाषा बोलता हूं और उनका काम करता हूं। इसलिए मुझे दर्द होता है। आप के पास तो वे मजदूर नेता आते हैं जोकि आसमान पर उड़ते है और जिन के पैर जमीन पर टिकते ही नही है। वे मजदूर मुहल्लों में नही जाते हैं और मजदूरों के बीच में नहीं जाते और आज जो आप उद्योग में भागीदारी प्रथा को चलाने की सोच रहे हैं, उस में भी यही होगा कि उनमें से किसी को डायरेक्टर बना दिया और किसी को कुछ बना दिया। किन्तु उस मे मजदूरों को मौका मिलने वाला नही है। आप मजदूरों का डाइरेक्ट सहयोग लीजिए और आप मजदूरों के बीच में जाइये। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बीच की दीवार को आप तोड़ दें और आप के विभाग और मजदूरों के बीच मे कोई फर्क नहीं रहना चाहिए। आप ने अपने एजेंट बीच में जो कायम कर रखे हैं वे ट्रेड यूनियन के लोग हैं। जिस प्रकार पूंजपति पैसे से श्रमिको का शोषण करते है। यह ट्रेड यूनियन के लोग अपनी बुद्धिमानी से मजदूरों का शोषण करते हैं। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आप इस बात को देखिए।

मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप ने आलीशान अस्पताल बनाए है लेकिन उन में डाक्टर नहीं हैं। यह बताइए कि इस से क्या फायदा होगा। आप के पास ऐसी रिपोर्ट है या नहीं कि जहां जो आप ने डाक्टरों की स्ट्रैंथ रखी है वह है, डाक्टर-विशेषज्ञ हैं, एक्सरे की मशीनें हैं, आपरेशन

के पूरे साधन हैं, आपरेशन थेटर है लेकिन मरीज वहां पर पडा हुआ है पर डाक्टर नहीं है। इस का क्या जवाब है ? मेटरनिटी बैनिफिट आप ने इस में कवर किया है लेकिन लेडी डाक्टर है ही नही। क्या मेटरनिटी के लिए मेल डाक्टर चाहिए। नर्सों का पता नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट नही देती और होता क्या है कि मरीज जाता है आप के अस्पताल में लेकिन उसे दाखिल करते है जनरल अस्पताल में। क्यों जी, जनरल हांस्पीटल में मजदूर कोई भी दाखिल हो सकता है लेकिन जो चन्दा देता है, जिस का चन्दा कटता है, उस का और आम आदमी का ट्रीटमेंट क्या एक-सा होगा। श्रीमन् बहुत सी ऐसी बाते है जिन को कहते हुए दु.ख होता है।

तो यह ई० एस० आई० की हालत है और आप के वर्कमैन कम्पेसेशन एक्ट की क्या हालत है। जो हालत ई० एस० आई० की है वही हालत उस की भा है। वर्कमैन कम्पेंसेशन एक्ट में भी 500 रुपये की लिमिट है। 500 रुपये से ज्यादा तनख्वाह वाले पर वह लागू नही होता। प्रधान मंत्री जी के पास जाने पर ई० एस० आई० का यह एमेंडमेंट तो हो गया, किन्तु अन्य के लिए भी क्या उनके पास जाऊ और अगर मैं इसी तरह से जाता रहू और काम कराता रहूं तो फिर श्रम विभाग की क्या जरूरत है, लेबर मिनिस्ट्री की क्या जरूरत है। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके अफसर मजदूरो के बीच में खाई क्यों बने हुए है। श्रम विभाग इसलिए कायम किया गया है कि मजदूरों को तत्काल न्याय मिले लेकिन मुझे यह सब बातें देख कर बहुत दु:ख होता है। प्रोविडेंट फंड की क्या हालत है और ई० एस० आई० की क्या हालत है। वर्कमैन कम्पेंसेशन एक्ट 500 रुपये से ज्यादा वालों पर लागू नही होगा। कितने कारखाने हैं और उनमें कितने एक्सीडेंट होते हैं। इसी तरह से आप देखें कि पेमेन्ट आफ वेजेज एक्ट का क्या हाल है जिसमें 400 रुपये की सीमा है। 400 रुपये तक तनख्वाह पाने वालों पर पेमेन्ट आफ वेजेज एक्ट लागू होगा लेकिन सिर्फ मजदूर को 500 रुपये मिलता है या 400 रुपये से कुछ ज्यादा मिलता है और उस मजदूर का वेतन नहीं दिया गया, तो लेबरकोर्ट में या अन्य कोर्ट में श्रमिक नहीं जा सकते हैं। सब कानून आपके ऐसे ही लूले बने हुए है इंडस्ट्रियल लेबर हाउसिंग का आपका कानून है मकान किस को मिलेगा ? गवर्नमेंट की ओर के जो बना हुआ मकान है वह उसी श्रमिक को मिलेगा जो किसी उद्योग में काम करता हो और जिसका प्रोविडेंट फंड कटता होगा और 500 रुपये से नीचे जिसको वेतन मिलता होगा। उसकी लिमिट भी 500 से अधिक बढ़ाने की बात है। एक मजदूर का चीर किधर किधर खींचा जाता है। तो श्रीमन, यह सर्वसम्मत बिल नहीं है जैसा मंत्री जी ने कहा और यह बहुत ही विवादग्रस्त बिल है। आपको इस पर विचार करना होगा कि ये सारे जो लेबर लाज हैं यह बहुत पुराने जमाने के हैं। आप का वर्कमैन कम्पेसेशन एक्ट कब का है पेमेन्ट आफ वेजेज एक्ट कब का है। 1936 में पेमेन्ट आफ वेजेज एक्ट बना और 1923 में वर्कमैन कम्पेसेशन एक्ट बना मैं समझता हूं कि जो उम्र हमारी है। उससे ज्यादा उम्र के आप के ये कानून हो गये है। आज इस जमाने में जब 20 सूत्री कार्यक्रम हिन्दुस्तान के लोगों के सामने आया है, तो गरीब यह सोच रहा है कि अब हमारे दिन फिरे हैं। तो मैं मानता हूं कि लेबर डिपार्टमेंट में जो बैठे हुए हैं उनका मगज भी फिर जाना चाहिए और उन को उस हालत में नहीं रहना चाहिए जिसमें वे हैं। मेरे और बहुत से साथी बोलने वाले हैं, इसलिए मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता। आप मुझे यह बतलाइए कि वर्कर्स का जो चन्दा कट रहा है, उसका फायदा उसको नहीं मिला है। वह समझता नहीं है क्योंकि वह अज्ञानी है।

[श्री रामसिंह भाई]

लेबर लीडर ऐसे हैं जो उसको बताते नहीं हैं और वे आपके आगे-पीछे चलने वाले है। हम उनके प्रतिनिधि हैं और सही माइने में प्रतिनिधि हैं। हम उन मजदूरों से चन्दा लेकर काम नहीं करते हैं लेकिन अपना जीवन उनको दे रहे हैं और देते रहेंगे। हम आपसे लड़ते रहेंगे उनको न्याय दिलाने की खातिर। इसलिए मैं फिर से निवेदन करना चाहता हू कि हमें कुछ नही चाहिए। हम लोक सभा में रहें या न रहें, फिर भी हम आनन्द मे रहेगे क्योंकि फुटपाथ पर चलने वाला आदमी हमेशा सुखी रहता है। यह मै निवेदन करना चाहता हूं कि आप सोचिये, विचारिये। आप अपने डिपार्टमेंट को खूब मीचिये और दो चार को मीजा मे क्यो नहीं रख देते। म आपसे सच कहता हू कि आज ई० एम० आई० के डाक्टरों का क्या हाल है। वे मजदूरो को झूठे प्रमाणपत्र दे देते हैं बीमारी के। मैं आप को नाम बता सकता हू कि मीजा के अदर जिस व्यक्ति के वारन्ट है, ई० एम० आई० के डाक्टर ने बीमारी का सर्टिफिकेट उसको दे दिया और वह उसको लेकर घूम रहा है। कारखाने के अन्दर किसी आदमी को ससपेंशन का नोटिस देना होता है तो डाक्टर झूठा उसको बीमारी का प्रमाणपत्र दे देता है। अब उस हालत मे उसको नोटिस नहीं दिया जा सकता है, डिसचार्ज, या डिसमिस का उसको नोटिस नही दिया जा सकता, यह आपका कानून है। इस तरह से चोर बदमाश इसका फायदा उठा रहे हैं।

मैं आपको बताऊं कि दवाओं पर आपका खर्च नही हो रहा है। लोगों ने एक रास्ता देख लिया है। आप मुझे बताइए कि कौन बेनिफिट पर आप कितनी रकम देते हैं। इस पर कितनी रकम ई० एम० आई० की चली जाती है। लोग सर्टिफिकेट ले कर जाते है, दस दस और पन्द्रह-पन्द्रह दिन की बीमारी की छुट्टी लेने। इस तरह 56 दिन तक का पैसा ले लेते हैं क्योंकि 56 दिन तक की बीमारी की छुट्टी लेने का अधिकार है। सारा ई० एम० आई० का पैसा इन्हीं बातों पर खर्च हो रहा है। डाक्टरों पर खर्च नहीं हो रहा है, नर्सों कम्पाउण्डरों और दवा पर नही हो रहा है क्योंकि आप उनको उतनी पगार दे नहीं सकते है। वे आपकी योजना में कभी नही आएंगे क्योंकि प्रोइवेट प्रेक्टिस भी वे नही कर सकते हैं। जो दवाइयां वगैरह आती हैं उनको कम्पाउण्डर आदि बाजारों में बेचते हैं। यह छिपी हुई बात नही है। आप मेरे साथ आइये या किसी को मेरे साथ भेजिये मैं दिखा सकता हू आप चन्दा लेते है लेकिन स्टेट गवर्नमेंटस के ऊपर आपने एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ दिया है। स्टेट गवर्नमेंटस ने कुछ श्रम विभाग को सौपा है और कुछ हेल्थ डिपार्टमेंट को। जैसा मैंने कहा द्रौपदी जैसा हाल हो रहा है इस योजना का हाल बेहाल है। इस ओर आप ध्यान दें। पैसे आप लेते, इस वास्ते जवाबदारी भी आपकी है और आप यह भी देखें कि मजदूरों को उससे फायदा पहुंचे। उनको फायदा पहुंचेगा तो वे आपको दुआ देंगे और मेहनत से और ईमानदारी से काम करेंगे। इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हू।

SHRI B. R. SHUKLA (Bahraich): Mr. Chairman, Sir, I welcome this amending Bill. I think, it was long overdue, as I have experience of some cases arising out of this Act in which many mill-owners have been deducting contributions out of the employees' salaries and wages and have not deposited for years in their account. The legal difficulty is that such cases cannot be instituted in court under this Act unless there is a complaint in writing by the Regional Provident Fund Commissioner.

Our society is still dominated by vested interests, mill-owners, mill

directors, who are hand in glove with these big officials. They dine with them; they dance with them and they linger on the filing of the complaint in court. However, after repeated efforts, if any complaint is filed in court, then the penalty provided under Section 85 of the Principal Act is that the offender can be let off with light imprisonment or fine. This amending Bill is very welcome in this respect that it makes awarding of imprisonment of three months as a compulsory punishment and they cannot be let off with fine Under any criminal law where there is any discretion left to a criminal court to let off an offender merely with a fine, that would not deter the big monopolists, big mill-owners and vested class of people from repeating the crime

There is one thing here. In clause 4 of the amending Bill, a provision is sought to be made that where he commits an offence under sub-clause (a), there shall be imprisonment for a term which may extend to six months but it shall not be less than three months in case of failure to pay the employees' contribution which has been deducted by him from the employees' wages. Here, the punishment is six months but the minimum punishment provided is three months.

Another salutory feature which has been sought to be introduced in this amending Bill is provided in clause 9, namely, "a person who fails to deposit the deducted amount in the account of the employees' provident fund shall be deemed to have committed an offence under Section 405 of the Indian Penal Code". That is to say, such an act of deduction but not depositing in the employees' provident fund account would be deemed to be an offence of "misappropriation". Now, there have been certain rulings where such deductions and their utilisation by the employer have been deemed to be an offenee of "misappropriation".

15.23 hrs.

(Shri H. K. L. Bhagat in the Chair.)

But there were other courts which took a different view. Therefore, the insertion of this new clause is a proper step in this direction. While it is going to be an offence under Section 405, it is also an offence under Section 85, that is, for the same act two offences are being made out, one under the Indian Penal Code, where the punishment is much higher, much more severe and the other under this very Act. I want that this depulication of offence should not be there. The offence for misappropriation can be initiated in a court of law even without being a complaint from the specified officer; the court can take cognizance of such offences even on a complaint by a private person; the employee himself can initiate the criminal proceedings, but the rights are circumscribed under Section 85, of this Act. Therefore, the hon. Minister may kindly ponder over this matter and bring an appropriate change that even an offence under Section 85 can be initiated and the court can take cognizance winthout the sanction of the Provident Fund Commissioner, otherwise my submission is that the benefit of Section 85 would not be available to the employee.

So far as Section 405 is concerned, the police would not take cognizance; they will say that this matter is pending before a high officer, why should they go out of their way. Therefore, this duplication is unnecessary; it will create confusion.

It is a welcome amendment that if within the time fixed or within the time extended after the conviction an employer fails to pay the amount, he would be deemed to have committed a further offence for which he shall be liable as provided under Section 85. My submission is, for how many times he would be deemed to have committed further offences. A person has been convicted for failure to pay the amount, and he is again convicted and

[Shri B. R. Shukla]

he again fails, how long we can extend this. After all, the aim and object is that the person should be penalised by awarding the sentence of imprisonment. My submission is that the best thing would be that there should be a provision for payment of interest at a rate which is higher than the bank rate on the arrears of the deducted amount. The employer would not be tempted or inclined to keep the amount because he would have to pay interest on the arrears at an enhanced rate, which would be more than the market rate permissible by the bank.

Further, Sir, the payment of such arrears should be made the first charge on the assets and the resources of the establishment or of the company. That will facilitate the payment. After excluding the dues which are to be paid to Government, such as the Excise duty arrears, sales-tax arrears or other governmental charges the amounts which become due to the employees, should become the first charge and the property of these establishments should be attached. Only then the arrears can be cleared up. Mere passing of the law would not go a long way in helping the wage-earners, the employees. A salutory provision should also be made that prosecution can be initiated without the sanction of the prescribed authority.

With these words, I whole-heartedly support the amending provisions of this Bill.

SHRI C. M. STEPHEN (Muvattupuzha): This Bill with respect to which I would submit I welcome so far as it goes. But I am sorry that it has not gone for enough. This is a half-hearted measure. As I said, half-hearted although it is, it serves a certain purpose in the matter of raising of the wages whereby the employees become entitled to the benefit of the Employees' State Insurance Act and the collection of the money is made more stringent to a certain extent. But I was feeling and I agree completely with Dr. Ranen Sen with respect to the so-called punitive measure, it is all white-washing and a camouflaging affair. Let us have close look at it which Dr. Ranen Sen has very incisively made and I have only a few observations more to make.

The Act as it goes makes an offence under this Act punishable with three month's imprisonment and a fine of Rs. 500—something like that. Now, one particular offence is bifurcated. That is the failure of the payment of the contribution. There, three contingencies are contemplated. (1) The payment of the amounts of the employee's contribution, (2) the payment of the employer's contribution and (3) subsequent offences of the same nature. Now, with respect of to those, they say that if it is payment of a contribution, then punishment is such and such, but, if it is a failure of the payment of the employee's contribution, there is an enhanced punishment fixed with an absolute minimum. This is what they have done. But the whole mischief comes in the proviso which says:

> "Provided that the Court may, for any adequate and special reasons to be recorded in the judgment, impose a sentence of imprisonment for a lesser term or of fine only in lieu of imprisonment."

May I humbly ask: why this absolute minimum become necessary? It was because of the inclination of the courts which we have been sowing successively to take a soft view of the things and allowing persons to get away, may be, till the rising of the court or a small fine of Rs. 10 and the employee going away with all the hardship. Now, the Parliament and the legislative assemblies expected of the courts to take a particular view. As was stated here by another Minister the other day, if a poor labourer

or a hungry man steals a loaf of bread the court, with all fury and righteous indignation, sends him to imprisonments for six months or may be a year or two years. But, if an affluent man, millionaire he may be, robs the worker and does not pay, then they are hesitant to inflict a similar punishment on him. This we saw in the execution of the Provident fund law, in the execution of the economic laws and in the execution of all labour laws we have been seeing this. Therefore, the legislatures thought it appropriate that their hands must be tied and they must be forced to give this much of punishment. Having accepted that, here comes a proviso. Immediately a soft attitude develops with the employer assuming that there is some attenuating circumstances, circumstances whereby this was not paid. Then, this seat of justice must be given a latitude whereby he can say, 'I award him imprisonment till the rising of the court or a fine of Rs. 100.' so that justice may be served. Is it not hypocrisy? Why, for heaven's sake did you bring in this provision with a proviso added? In the Provident Fund Act the proviso is still there. In the Gratuity Act there was this proviso but the members of this House fought and the result was that the proviso was removed and if it is case of non-payment of gratuity, the court has no discretion at all. They will have to send me to jail, and there is no discretion. With respect to insurance with respective to gratuity hard position could be taken. With respect to Provident Fund under Employees State Insurance Scheme why should you give discretion to the court to say "I find him guilty, he has collected money. The employer has not paid and, therefore, the employees has not been getting the benefit of insurance, he has not been getting medical benefit?" After having found all the fact, why should you give discretion to the court to say 'for reasons to be recorded in writing'. If that is done, will all injustice be removed? The court may then get back to the old habit of just patting the man on the back and saying. "All right I forgive you. Be in the imprisonment upto the rising of the court. Myself and you will together rise". I say this is a half hearted hypocritic measure.

Now we come to the other question namely of subsequent offence.

"Provided that where such subsequent offence is for failure by the employer to pay any contribution which under this Act he is liable to pay"

I am not sure whether where he fails to pay my contribution, he is punished. If he fails to pay for another factory. I would like to know whether or not that would be deemed as a subsequent offence. I am not very clear about it. Why this word 'any'—I do not understand. Why could you not quit "any"? If you omit 'any' then it will become mere genral. Then it will read committting subsequent offence.

Then, look to the types of offences—

"(a) fails to pay any contribution which under this Act he is liable to pay, or

(b) deduct or attempts to deduct from the wages of an employee the whole or any part of the employers' contribution".

Now if an employer deducts the entire contribution from the employee then if he pays the whole thing...

SHRI RAGHUNATHA REDDY: What was the previous punishment?

SHRI C. M. STEPHEN: Previous punishment you have raised. What is the benefit of it unless you fix up an absolute minimum? What I am saying is why have this in sub clause (a)? You have now categorised it in (a) to (g). The same punishment was there. Now Mr. Raghunatha Reddy,

(SHRI C. M. STEPHEN)

speaking on behalf of the Ministry is taking a serious view of sub clause (a) even when there was hotch potch as I have shown.

What about clause (b)? I am putting the question to you. An employer collects his own contribution from my wages and pays the whole thing to the other person. No offence committed? The offence is committed. Then the employer is collecting his contribution from my wages and getting out of the hard punishment. Why do you not have a look at it again? Is it not more heinous than the other one?

"(c) In contravention of section 72 reduces the wages or any privileges or benefits admissible to an employee,"

That also you do not consider as a serious crime.

"(d) in contravention of section 73 or any regulation dismisses, discharges, reduces or otherwise punishes an employee, or"

That also you do not consider a serious matter? Why could you not put all this at one place? Therefore if I deduct from the employees wages my contribution and pay the whole contribution....

SHRI RAGHUNATHA REDDY: I shall take your advice and come forward with an amending Bill.

SHRI C. M. STEPHEN: .. and pay the whole contribution, then he is a mild offender. It is not his money. If he does two offences together, he becomes a milder ocender.' If we robs me of salary and pays, it becomes the mildest offence?

MR. CHAIRMAN: Mr. Stephen, the Minister has said that he will take your advice and come forward with an amending bill.

SHRI C. M. STEPHEN: I understand the spirit and tone of it. I do not reply to it.

MR. CHAIRMAN: No, no, you should...

SHRI C. M. STEPHEN: I do not reply to that. Not that I do not know how to reply it but I do not expect that sort of reaction from a person like Mr. Reddy.

So, this is the total picture.

SHRI RAGHUNATHA REDDY: What I said was well-intentioned. I fully realise the significance of your speech. We are keeping it in mind; we will look into the matter.

SHRI C. M. STEPHEN: I accept his assurance. Therefore I am winding up. All I am submitting is only this. The Govrenment as a whole, not merely the Labour Ministry, in the wake of the present emergncy, should look into it and tak a stricter attitude towards certain types of offences, offences against the poor worker and against the economic laws of the country. A stricter attitude has got to be taken and that is to be reflected in the laws which we are enacting. For whatever has been done by this Bill I compliment the Government for it. But my complaint is that it has not gone for enough. I do not agree with Shri Shukla ji on his comments about the amendment of the Penal Code. By reason of this amendment the worker against whom an offence is comitted under this Act can on his own go to some authority in spite of the collusion of a few officers with the employees. To the extent it has gone, I support the Bill, but I repeat what I said in the beginning that it would have been better if it had gone further-enough. But, Sir, I take the assurance of the hon Minister, that in leisure time he will have a deeper look into this mater.

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति महोदय, यह तो विधेयक कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत प्रस्तुत है मैं इस बात का स्वागत करता हूं। मैं केवल एकबात कहना चाहता हूं जिस की तरफ मंत्री जी का ध्यान जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सदस्यों ने बहुत सारी बातों पर रोशनी डाली हैं। मैं केवल अस्पतालों की जो आज दुरव्यवस्था है उस की तरफ आप का ध्यान दिलाऊंगा। आप पैसे तो मजदूरों से भी जमा कर रहे हैं और जो मालिक समय पर नहीं देते या कभी नहीं देते उन को सजा देने की भी व्यवस्था कर रहे हैं। वह तो ठीक कर रहे हैं। इसीलिए कोई भी ट्रेड यूनियन में काम करने वाला कार्यकर्त्ता आप के इस प्रयास की प्रशंसा ही करेगा। लेकिन आप को अर्थात् सरकार को यह भी देखना चाहिए कि ई एस आई कारपोरेशन या मेडिकल बेनिफिट कौंसिल के पास जो इस तरीके से धनराशि जमा होती है उस का सदुपयोग होता है या दुरुपयोग होता है। जो आप की मंशा या उद्देश्य है कि हम मजदूरों की ज्यादा से ज्यादा चिकित्सा करा सकें, उन्हें बीमारियों से बचा सकें, यह उद्देश्य पूरा होता है या नही, इस बात को भ देखना आप का कर्त्तव्य है और शायद सब से बड़ा कर्त्तव्य है। लेकिन इस तरफ मेरे ख्याल से ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा हैं।

अस्पतालों में चले जाइए, डिस्पेंसरियों में चले जाइए, मजदूरों की बात कोई सुनता नहीं। दवाइयों का स्टाक ठीक नही रहता। जिस दवा की आवश्यकता होती है वह दवा मिलती नहीं है। इन दिनों तो दवाओं की सप्लाई पर नियंत्रण भी है कि यह दवा मिलेगी और यह दवा नहीं मिलेगी और यह सर्वत्र है, केवल ई एस आई के ही अस्पतालों में नहीं है। लेकिन आप के अस्पतालों में ज्यादातर पानी दिया जाता है मिक्सचर के नाम पर, उस को गंगाजल कहिए, पानी कहिए, मिक्सचर के नाम पर वही मिलता है। आप के कम्पाउंडर से समझा कि डाक्टर ने दवा दे दी, उस ने उठा कर मिक्सचर दे दिया और ए पी सी का पाउडर जरूर दिया जाता है। कोई भी बीमारी हो ए पी सी का पाउडर दे दिया, आप का काम खत्म हो गया। कभी तो मिक्सचर के नाम पर पानी और कभी ए पी सी का पाउडर यही वहां मिलता है।

इस के अलावा आप जानते हैं आजकल बीमारियां भी बहुत बढ़ रही हैं। आप जितना उपाय करते हैं उतना ही बीमारियां भी अपने बढ़ने का उपाय कर लेती हैं। ऐसी अवस्था में उन को यदि समुचित दवा नहीं दी जायगी और मेरा ख्याल है कि आम तौर से मजदूरों को समुचित दवा नहीं दी जाती तो इस की वजह से वह परेशान हो जाते हैं, उन की बीमारिया अच्छी नहीं होती और बहुत सारे लोग काल कवलित भी हो जाते है, ऐसी ऐसी बीमारियां उन को हो जाती हैं। मेरा निवेदन है मंत्री महोदय से कि जो भी राशि इन कारपोरेशनों के पास जमा है जिस राशि को जमा करने पर सरकार इतना ध्यान दे रही है उस राशि से ज्यादा से ज्यादा दवा दी जाय। अभी आप का पैसा प्रशासन पर ज्यादा खर्च होता है। खर्च होना चाहिए डाक्टरों पर, नर्सेज पर, दवाओं पर, अस्पतालों में जो हैं ज्यादा बढ़ाई जायं, बेड्स ज्यादा बढ़ाए जायं इन पर, लेकिन इस तरफ सानुपातिक रूप से आप देखेंगे कम खर्च होता है और ऐडमिनिस्ट्रेशन पर ज्यादा खर्च होता है। इसलिए ऐडमिनिस्ट्रेशन पर जो खर्च होता हैं उस को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। टाप हेवी ऐडमिनिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। यह चीज सरकार के तमाम विभागों में है जिस से आप का विभाग या ई एस आई का विभाग बचा हुआ नही है इस को रोकने की जरूरत है और ज्यादा से ज्यादा इस में इन को हम चिकित्सा और एक्सपर्ट ट्रीटमेंट मुहैया करे। बहुत से मजदूरों को उस की जरूरत पड़ती है लेकिन क्या आप एक्सपर्ट ट्रीटमेंट दे पाते हैं ? क्या आप ने इस का लेखा जोखा कराने की कोशिश की है कि कितने मजदूरों को एक्सपर्ट ट्रीटमेंट

[श्री रामावतार शास्त्री]

विशेष चिकित्सा या विशेषज्ञ चिकित्सा की जरूरत है ? अगर इस का आप लेखा जोखा लेने की कोशिश करेंगे तो आप को अन्दाज मिलेगा कि अधिकांश मजदूरों को इस तरह की चिकित्सा नहीं मिलती । यदि मजदूरों की हालत देखें तो मालूम होगा कि डाक्टर ने स्लिप दे दी एक्सपर्ट ट्रीटमेंट के लिए, अब वह जनरल अस्पताल में दौड़ा दौड़ी कर रहे हैं । फुटबाल की तरह यहां जाते हैं फिर वहां जाते हैं, फिर यहां आते हैं । उन को ट्रीटमेंट मिलता नहीं है । इस तरफ ध्यान कौन देगा ? ई एस आई को ही ध्यान देना है, सरकार को ध्यान देना है क्यों कि यह काम सर्वोपरि ध्यान देने का है । लेकिन यह बात नही हो रही है ।

राम सिंह भाई ने ठीक कहा है कि डाक्टर ही नहीं हैं तो दवा क्या होगी ? दवा लिखने वाला ही नहीं है । अगर दवा लिखने वाला है तो दवा बांटने वाला नहीं है । और अगर दवा बांटने वाला नहीं है तो घटे दो घंट बैठ कर मजदूर चला गया । दवा बांटने वाला आया तो दवा लेने वाला नहीं है । यह व्यवस्था रहेगी तो जो आप का मंशा है वह बड़ा ही सुन्दर है, सराहनीय है, प्रशंसनीय है, मगर वह किताब में ही रह जायगा । पार्लियामेंट में भी हम लोग बोल देंगे, यहां की रिपोर्ट में भी यह बात छप जायगी । इस समय तो अखबार में भी यह बात नहीं छपेगी क्यों कि आप का सेंशर विराजमान है । हम ने सुना है कि वह सेंशर प्रधान मंत्री के भाषण का भी काट देता है तो हम लोगों के भाषण को कौन छापने वाला है ।

मैं चाहूंगा कि जो हम लोग बोल रहे हैं इस पर आप का ध्यान जाना चाहिए और डाक्टर, विशेष चिकित्सा और अस्पतालों की व्यवस्था होनी चाहिए । राम सिंह भाई ने कहा कि बहुत सी जगह तो एक्सरे की मशीनें हैं, लेकिन हम तो कहते हैं कि बहुत सी जगहों में अस्पतालों का एक्विपमेंट ही नहीं है । एक दो जगह है जहां बड़े बड़े अस्पताल हैं, लेकिन आप की यह कर्मचारी राज्य बीमा योजना देश के कोने कोने में फैली हुई है । इस की व्यवस्था सुदूर क्षेत्रों तक है । मगर सब जगह अस्पतालों मे सब तरह की व्यवस्था नही है । औरतों की चिकित्सा की व्यवस्था तो बहुत कम है । जिस अनुपात में होनी चाहिए उस अनुपात में नहीं है । तो के ल इमीलिए मैं इसपर बोल रहा हूं । वैसे मै इस पर बोलने वाला नहीं था । इस बात की तरफ मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हू कि पैसा जो लिया जायगा, जरूरत पड़ने पर मजदूरों से तो लेते ही हैं, जो मालिक नही दे रहे है उन को सजा देने की व्यवस्था भी कर रहे है, वह सब ठीक है, कीजिए लेकिन उस पैसे का सदुपयोग हो, दुरुपयोग नही हो और जिस के लिए ले रहे है उस को उस का लाभ मिले जो आज नही मिल पा रहा है । इस तरफ मै आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं । मुझे विश्वास है कि आप का ध्यान और ई एस आई का ध्यान जरूर इस तरफ होगा । सभी मजदूर ज्यादा सतुष्ट होंगे । वरना कानून आप केवल बनाते जाएंगे लेकिन उस कानून से उन्हे लाभ नही मिलेगा तो फिर काम नही चलेगा ।

SHRI RAJA KULKARNI (Bombay-North-East): Mr. Chairman, Sir, I wholeheartedly support this amending Bill. There are mainly three points in this amending Bill.

One is, of course, enhancing the wage limit in respect of insured persons from Rs. 500 to Rs. 1,000 per month. As a matter of fact, this has been long pending. The purpose in enhancing this wage limit is, of course partly to bring back—it is almost like catching—some of the insured workers, some workers who were, few years ago, covered under this scheme but subsequently had to go out the scheme because of the increase in their salaries beyond Rs. 500 as a result of increase in dearness allowance

and so on consequent on the increase in the cost of living index. Therefore, in that respect, this enhancement of the limit has the purpose of bringing back those who were out of the scheme. There is also the purpose that by extension of the application of the Act, more people can now be covered from all new industries. Now, more people, under the Shops and Establishments Act and other services, would be covered. Therefore, both ways, this enhancement of the limit would give more coverage and wider coverage. It also entails more responsibilities on the part of the Corporation and I am sure the Labour Ministry will look into the working of the Corporation from that point of view.

Now, when we are trying to bring in more and more workers from different industries, transport undertakings and other services, we should also go into the structure of the Corporation, the working of the Corporation and the benefits given to the employees. We have to see how more efficient service can be rendered. I am sure the Labour Ministry will look into this. As a matter of fact, we were thinking that the Labour Ministry would bring forward a comprehensive legislation on the Employees' State Insurance Corporation for the purpose of re-structuring it and giving more powers to it. But, we are still missing that comprehensive approach of the Labour Ministry when the Corporation is being given more responsibilities. There is a necessity to reorganise the Corporation by treating it as an autonomous Corporation. Now, when we are raising the wage limit bringing in more workers and thus increasing the quantity, we should also look to the quality. Our Labour Minister is conversant with the principle that quantity also changes into quality. Therefore, the present status and the structure of the Corporation must also undergo a change. It must become more autonomous. I hope the Labour Minister will, in the immediate future, come forward with a comprehensive legislation on the new status and functions of the Corporation.

The second point that is covered is in respect of fines and penalties, hard penalties. Much has been said about this and I agree with all that. I do not know with all the harsh penalties now sugested how far they will be effective, how far they will be implemented in reality or how far they would be more relevant. But with all that, I would like to have a clarification from the Labour Minister as to how far the penalty provisions have been implemented in the past. Of course, every effort is to be made for recovery from defaulters.

Take, for example, the crores of rupees which have yet to be recovered, contributions deducted by the employers, workers' contributions as well as the employers' contributions, not deposited, thereby making a default. Years pass away. A lot of proceeding have been there, litigation has been there. How to avoid it? I do not know how much time of the officers of the Corporation is wasted in all these reecovery proceedings. There has to be some kind of an arrangement for the recovery of these contributions. Something has to be done apart from providing for rigorous penalty. Will the rigorous penalty now provided reduce litigation and time spent by the officers of the Corporation in all these legal proceedings? Probably more time of the Corporation is spent on legal proceedings than on the administration of medicines or hospital arrangements. So I would like a proper study made and a report asked for from the Corporation about the time spent on legal proceedings as compared to the time spent on medical treatment itself.

The third point to which I would like to draw the attention is in regard to Sec. 93A—Clause 6 of the Bill. I would like to have a clarification on

[Shri Raja Kulkarni]

this point. Supose there is a big defaulter, the transfer of establishment takes place and no liability comes to the new employer. The proposed sec. 93A reads:

> "Where an employer, in relation to a factory or establishment, transfers that factory or establishment in whole or in part, by sale, gift, lease or licence or in any other manner whatsoever."

What does this expression 'or in any other manner whatsoever' mean? Does it specifically include acquisition proceedings? Last year when Government through the National Textile Corporation took over the sick mills, the original owners of the sick mills were defaulters. Dues were to be paid by them. When the mills were taken over and the Bill came here the Corporation had to lose crores of rupees which were not paid, which were due to be recovered from the old employers. Government refused to take up that liability. When this has happened in the recent past, as early as in 1974, are you including in this expression 'or in any other manner whatsoever' acquisition proceedings. They do not come under 'sale' or 'licence', but do they come under this? I would like to have this clarification.

With these words, I support the Bill.

16 hrs.

SHRI N. K. SANGHI (Jalore): I rise to support this amending Bill. My friends from both sides have already said a lot on the working of the Employees' State Insurance Act. There are two basic points. One is the penalty provision for non-payment of the employees' contribution; that has been made more rigorous. The other thing is that the workers are not enamoured of the services rendered in the hospitals. The special service that we want the workers to get, workers who pay their contributions, is very much neglected.

If we look to the history of the scheme, it was in 1943 that the system was mooted. A special officer was appointed to work out a social health scheme. The State Insurance Bill was brought out in 1946; it took almost three years to do this. This Bill was passed on 2nd April 1948. But then it took again four years to implement it and it was in 1952 that the scheme was implemented in Delhi and Kanpur. I think that we work on making changes is going on at a snail's pace when it is a question of making desirable changes in the scheme. The Estimates Committee Report, 123rd of 1969-70 and the Action Taken Report, 133rd report of 1970-71, are the basic pointers in this direction. The recommendation of the Estimates Committee was that employees drawing a salary of Rs. 1000 should be brought into the orbit of the scheme; it was made in 1969-70. In 1975 we are implementing that recommendation. At this rate I do not know how we could go ahead with the provision of basic health service to the vast multitudes of our people.

Another basic recommendation of the Estimates Committee was about the merger of the State Insurance scheme with the Employees' Provident Fund. The hon. Minister of Labour a few years ago said that a whole scheme had been finalised and would be brought soon before the House. Even five years after the statement by the hon. Minister, no scheme for the merger of the State Insurance scheme with the provident fund scheme has been brought in. Now, why do they want a merger of the two schemes? Because we find so much time being wasted on paper work and complying with formalities with the result that the benefit that should really go to the workers did not reach them in the desired measure. Even

industrial undertakings had to do so much of paper work and that was why the Estimates Committee recommended that there should be a merger so that the paper work would be reduced. Unfortunately that has not been done. We want to know the reason why. In the Action-taken report, it was stated that the Government had appointed a special officer to work out an integrated scheme. That was in 1970-71. We are now in 1975. What has hapened to the integrated scheme? I also feel that the scheme should be integrated because the old scheme is archaic, outmoded and time-consuming involving a lot of paper work. In 1948 we provided that the employees should be issued a card and the contribution of the employees should be affixed in revenue stamps. A lot of expenditure is involved in printing them and then pasting them. If improvements are made in the scheme, the work of the treasury also will be reduced.

When a person joins an industrial undertaking, for the first few weeks he does not get any benefit. We are in space age and things are moving fast. Why should not a person get the benefit from the very first day he joins an industrial undertaking?

The whole working system should be re-oriented to avoid labour on paper work. A lot of paper work will be eleminated and recovery payments, etc. will be simplified. Other benefits would also come out from remodelling of the working of the State Employees' Insurance Scheme. In Rajasthan, today, we have a beautiful E.S.I. hospital construction in Jaipur. A very good surgeon who had been transferred to this hospital said that he was unable to work in that hospital because there was no anaesthetist. He said unless an Anaesthetist was posted there he could not do any surgery work. After his transfer to that hospital he worked there for a few months without any operations being done. Later he got himself transferred to some other hospital as he could not do surgery there. Similarly in Jodhpur we have seen the E.S.I. building where a medical hospital is housed. Here for any special treatment these employees have to go to the main State Hospital. After they are treated there, since medicines are not available in this hospital they have again to go to E.S.I. dispensary to get their medicines. This E.S.I. dispensary is a couple of miles away. These are the practical difficulties faced by the sick people and somebody should look into these matters.

Sir, you have also brought a modification of employees' contribution for a wage earner getting below Rs. 2. But the recommendations of the Estimates Committee in 1969-70 was to exempt the wage earner below Rs. 3. A lot of water has flowed down the Ganges. At this late stage, why should the Government not have decided to exempt the wage earner below Rs. 3 from making his contribution. The present day value of the earnings has come down due to inflation, etc. and the value of Rs. 3 is already very low. There has recently been another problem. Casual workers are employed by industrial establishments for annual white-washing and repairs of their buildings. The E.S.I. Department wanted the contributions from these casual workers also. The case was filed in the High Court of Rajasthan and the High Court has given a decision that such workers do not come under the ambit of the E.S.I. law and no contribution should be demanded. In spite of this, the Director in Rajasthan has been issuing notices for payment of similar contributions from the factories and industrial undertakings for payment made to the casual workers. But it was told that an appeal has been filed with the double bench. But once a decision has been taken; it should stay till it is reversed and the Department should not have proceeded in creating harassment and difficulties in this matter. Such administrative

[Shri N. K. Sanghi]

problems should be tackled by the Government to avoid genuine difficulties of the undertakings.

I think the Government would consider these redical changes to simplify the procedures so that the working would become easy and also implement proper medical care scheme to these workers. This would go a long way in improving the faith of the workers in this system. Thank you.

डा० कैलास (बम्बई-दक्षिण) : माननीय सभापति जी, मैं एम्पलाइज स्टेट इंश्योरेंस अमेण्डमेंट बिल, 1975 का स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ हूं। एमरजेन्सी में शायद केन्द्रीय सरकार ही नहीं, राज्य सरकारों के भी सभी विभाग अपने आप को टटोल रहे हैं, बड़ी बुद्धिमानी और तत्परता से कार्य करने लगे हैं। लेकिन श्रम विभाग तो शायद सोया हुआ तो था और अब तो और ज्यादा गहरी नींद में सो रहा है। मैं इस लिये यह कह रहा हूं कि यह बिल इतना सुन्दर है, लेकिन इस की सुन्दरता को बिगाड़ने का काम हमारे वे नान-कमिटड आफिसर्ज कर रहे हैं जो इस लेबर डिपार्टमेन्ट में बैठे हैं। चाहिए तो यह था कि इस डिपार्टमेन्ट में कमिटेड आफिसर्ज को लिया जाता जो मजदूरों के लिये रो सकते हैं, जो आसू बहा सकते हैं, उन्हीं को यहां लिया जाना चाहिये था, लेकिन वे कुछ शायद दूसरी ओर सोचने लग जाते हैं।

सभापति जी, आप ने मजदूरों के नेताओं को बोलने का मौका दिया .....

MR. CHAIRMAN: Mr. Kailas, I am sorry your name appears earlier in the list. I apologise to you. Now, you may continue.

डा० कैलाश : हो सकता है कि संघी जी मालिक हों, मैं नहीं जानता लेकिन अगर इस बिल की आत्मा को देखें तो उसका सम्बन्ध मजदूरों के स्वास्थ्य से आता है। मैं भी एक डाक्टर हूं और मैं ने एक नहीं बीसों ई० एस० आई० के अस्पतालों को देखा है। बम्बई से मैं आता हूं, राम सिंह भाई जी कहते हैं कि बम्बई में अभी भी पैनल सिस्टम चला हुआ है। मनुष्य को गाली देने से नहीं सुधार सकते बल्कि प्रेम से सुधार सकते है। वहां का डाक्टर गलती करता होगा, तो क्या सर्विस में जो डाक्टर है वह दूध के धुले हुए हैं ? पैनल सिस्टम की बात तो इस बिल मे है भी नहीं।

माननीय श्रम मंत्री जी बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं लेकिन समझ मे नहीं आता कि जिन अफसरो के चक्कर मे आ कर यह प्रोविजो लगाये है। आप ने 500 से 1,000 रु० किया यह ठीक है, लेकिन मै तो चाहूंगा कि 1,500 रु० हमें करने चाहिये। क्यो कि वह जमाना हम देखने जा रहे है जब इस देश का हर व्यक्ति मेडिकली इन्श्योर्ड होगा और डाक्टर कमिटेड हो जायेगे।

आप ने 6 महीने से 1 साल की सजा की मियाद बढ़ायी है। कोर्ट को हम क्यों दोष दें, वहां पर भी कमिटेड मैजिस्ट्रेट होने चाहिये। जिन मालिकों ने लाखों रुपया इकट्ठा कर लिया वर्कर्स से और कारपोरेशन मे जमा नही कराया तो कोर्ट उन को छोड़ देती है उन मालिको का तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन दंड मिला मजदूर को जिन्हें मेडिकल बेनिफिट नही मिलता। अगर मालिक पैसे जमा नही करता है तो कोर्ट उस से निपटेगा, लेकिन जिस ने पैसा दिया है उस का इलाज अस्पताल से होना चाहिये इस पर आप ने कलम नही रखी है। यह बिल में रखना आपके हाथ में हैं।

पिछले चार साल के बाद आप प्लान्टेशन और माइन वर्कर्स को इस में ले आये इस के लिये बधाई है। हम कह रहे थे कि थ्येटर के कर्मचारियों को और ट्रांसपोर्ट के एम्पलाईज

को भी शामिल किया, इस नाते 3, 4 लाख वर्कर्स और इस स्कीम में शामिल हो गया। अगर इस प्रोवीज़ों को नहीं रखते तो यह बिल बहुत ही बढ़िया हो जाता। माननीय राम सिंह भाई, स्टीफ़न साहब और डा० रानेन सेन साहब ने एक अच्छी कलम को नहीं देखा और वह यह कि अगर किसी ने एक बार, दोबारा फाल्ट किया तो 100 रु० रोज जुर्माना मालिक पर होगा। इस को भी तो उन्हें देखना चाहिये। क्यों नहीं इस के लिये श्रम मंत्री को बधाई देते ? कोर्ट ने कुछ भी फैसला दिया हो लेकिन फ़ैसले के बाद अगर ऐक्सटेंडेड पीरियड को वह तोड़ता है तो 100 रु० रोज का दंड देना होगा। इस से वह डरेंगे। ठीक है आप हैबिचुअल औफ़ेंडर्स को बढ़ा कर सजा दें, लेकिन मुझे औफ़डर वे लोग लगते हैं जिन को मालूम है तथा जो जानते हैं कि फला आदमी औफ़ेंडर है फिर भी उन से रुपया जमा नहीं कराते ऐसे लोगों को ठीक प्रकार से कोर्ट में नहीं ले जाते हैं। इसलिये जो वहां पर इंस्पेक्टर वगैरह काम कर रहे हैं उन को अगर श्रम मंत्री जी समझा दें, उन को अगर सम्भाल लें तो अच्छा रहेगा।

ऐक्स-रे मशीन है, डाक्टर भी है, लेकिन प्लेट्स नहीं मिल रही हैं। श्रम मंत्री को तार देते हैं, स्टेट हैल्थ मिनिस्टर को तार देते हैं लेकिन कोई साहब नहीं आता। जब अधिकारियों से कहते है तो वह कहते हैं कि हम क्या करें, इम्पोर्ट नहीं आया है। रोज यही होता हैं। महात्मा गांधी अस्पताल जो बम्बई का है मजदूरों के लिये, उस में रोज की यही कहानी है। मजदूरों का नम्बर करीब 1 करोड़ के बढ़ गया है, तीन चार लाख और भी बढ़ाये जाने वाले हैं। लेकिन अगर आप ने उन डाक्टरों को जिन को फुल टाइम पर रखा है, उन्हें उतनी तनख्वाह नहीं देते जितनी कि और डाक्टरों को जो हैल्थ डिपार्टमेंट में काम कर रहे है तो आप को कभी भी अच्छे डाक्टर नहीं मिलेंगे। आप अच्छे डाक्टर, नर्सेज और वार्ड बाय नहीं रख सकेंगे। मंत्रालय इस स्कीम को तो चलाये लेकिन अस्पताल का ऐडमिनिस्ट्रेशन हैल्थ डिपार्टमेंट की तरफ़ अगर चला जायगा तो हम आशा करते हैं कि स्थिति में सुधार होगा और हैल्थ डिपार्टमेंट में जो विशेषज्ञ बैठे हैं वह डाक्टरों नर्सेज से ठीक प्रकार से काम ले सकेंगे

मैं ने नहीं देखा कि हमारे मंत्री जी किसी ई० एस० आई० अस्पताल में गये हों। अगर गये होते तो मेरे पास सूचना जरूर आती और मैं उस को बताता कि कैसे स्थिति में सुधार किया जाता है। इस इमरजेंसी में आप ऐसे लोगों पर एम० आई० एस० ए० लगा दीजिये या प्रीमैच्योर रिटायर कीजिये जो आप को गलत रास्ता बता देते हैं या काम नहीं करते फ़ील्ड पर जो बैठे हैं, जो मालिक और मजदूर के बीच में बैठे हैं वह गलत काम कर रहे हैं। उन में से एक दो बड़े लोगों को आप पकड़ लीजिये या उनकी छुट्टी कर दी दीजिये तो लेबर डिपार्टमेंट ठीक प्रकार से कार्य करने लगेगा। और आप का नाम भी हो जायगा। अगर हैल्थ और लेबर डिपार्टमेंट्स में अस्पताल के ऐडमिनिस्ट्रेशन के लिये कोआर्डिनेशन हो जाय तो भी सब ठीक हो जायगा।

ई० एस० आई० अस्पताल ज्यादा बनाते तो अच्छा होता। लेकिन जब नहीं बना पाये तो इन प्राइवेट ट्रस्ट के अस्पतालों में आप ने जो बैड्स रखे हैं उस के लिये 15 रु० पर बैड आप दे रहे हैं यह आज कल के जमाने में कम है। 15 रु० प्रति बैड आप ने बहुत पहले सोचा होगा। आज एक बैड का खर्चा 20 से 25 रु० आता है। आप के पास पैसा है, जब मजदूरों के लिये फायदे का काम करने जा रहे हैं तो आप को चाहिये कि जिस ट्रस्ट के अस्पतालों में ई० एस० आई० के बैड रखे हैं और चाहते हैं कि मजदूरों को पूरा लाभ मिले तो प्रति बैड जो खर्च आता है वह आप को देना चाहिये।

[डा० कैलास]

इन शब्दों के साथ मैं श्रम मंत्री जी को, और खास तौर से प्रधान मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि विभाग में जो स्लैकनैस आ गई है उस के लिये इस इमरजेंसी दौरान जिम्मेदार लोगों को अगर सजा देंगे तो अच्छी तरह से यह योजना सेवा कर सकेगी ।

श्री अमर नाथ विद्यालंकर (चंडीगढ़) : सभापति महोदय, इस बिल के सम्बन्ध में मेरे साथी बहुत कुछ कह चुके हैं, और मैं अधिकतर बातों का समर्थन करता हूं । यह बिल जैसा मेरे साथियों ने कहा बहुत देर के इंतजार के बाद आया । मैं न सिर्फ इस बिल से बल्कि राम सिंह भाई जी से भी सहमत हूं कि जो भी मजदूरी के सम्बन्ध में कानून हैं, अब समय आ गया है कि उन पर फिर से एक दफा विचार किया जाये क्योंकि इस बात की सख्त जरुरत है कि मौजूदा वातावरण के मुताबिक उन को बनाया जाये ।

यह बड़े दुःख की बात है कि हमारे देश की प्रधान मंत्री ने देश का वातावरण तब्दील किया है और उन्होंने सरकार की तरफ से इस बात का एक फैसला किया है कि हम कुछ अपने देश में करेंगे । दरअसल हम देश की गरीबी हटाना चाहते हैं । गरीबी धन से हटती है । धन ज्यादा हो तो जदेश गरीब नहीं रहेगा और धन का उत्पादन मजदूर करता है लेकिन हमारे देश में अब तक हालत यह रही है कि मजदूर जो धन कमाता है और देश को धनी बना सकता है, वह जितनी सख्त मेहनत करता है, उतना ही उस को कम मिलता है और जो कम मेहनत करता है, उस को बहुत ज्यादा मिलता है । सामाजिक हैसियत के लिहाज से भी मजदूर कितना ज्यादा मेहनत करता है, समाज के अन्दर उस का हैसियत उतनी ही कम है । अब तक यह चीज होती रही है लेकिन मैं समझता हूं कि जब इस देश का वातावरण परिवर्तित हुआ है, तो यह चीज भी बदलनी चाहिए और मजदूर को न सिर्फ इस देश के धन का ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए बल्कि उस की समाज के अन्दर हैसियत भी ऊंची होनी चाहिए, उस का स्टेटस बढ़ना चाहिए, लेकिन अब तक हमारे देश में चाहे प्रान्तीय सरकारें हों और चाहे वह केन्द्रीय सरकार हो उन के जो मजदूर विभाग हैं, उन के अन्दर अभी तक इस भावना का प्रादुर्भाव नहीं हुआ है । वह भावना अभी तक उन में नहीं है और उन की भावना उसी तरह से मशीनरी को चलाने की है जैसे और डिपार्टमेंटस चलते हैं । वे इस भावना से काम नहीं करते हैं कि यह विभाग जो है, इस के द्वारा मजदूरों की स्थिति को ऊंचा करना है और हम लोग मजदूरों को जो कुछ राहत मौजूदा कानूनों से पहुंचाना चाहते हैं, वह उन को मिलनी चाहिए लेकिन हमें यह शिकायत रहती है और खास तौर से वे लोग जो मजदूरों में काम करते रहते हैं, उन को हमेशा यह शिकायत रहती है कि और किसी चीज, का इम्पलीमेंटेशन चाहे हो या न हो लेकिन मजदूरों के कानूनों का इम्मलीमेंटेशन पूरी तरह से नही होता है । मजदूर लड़ झगड़ कर आज चाहे जो कुछ ले ले लेकिन जहां तक कानूनों का ताल्लुक है, दो, दो और तीन तीन साल तक उन के मामले लटके रहते हैं और उन को मुआविजा मिलना चाहिए उस के लिए अदालतों के अन्दर मामले चलते रहते हैं और उन को मुआविजा नहीं मिलता है और जैसा कि इस बिल से मालूम होता और जिस के लिये आपने सही तौर पर कदम उठाया है कि जो कुछ रुपया उन से वसूल होता है, वह मालिक अपने पास रख लेते हैं और उन को देते नहीं है, इन सब चीजों को आप को समाप्त करना चाहिए और इस लिए मैं इस बिल का स्वागत करुंगा । आज जो वातावरण बदला है उस के अनुसार हम अपने मजदूर विभाग का वातावरण भी बदलें और आगे बढ़ें और इस चीज की निशानी यही है और उन का टैस्ट मैं यही समझता हूं कि हरेक मजदूर देश का यह महसूस करे कि अब मेरे लिए कुछ होने जा रहा है और मुझे सही तौर पर राहत मिलने वाली है और मेरे साथ जो अब तक व्यवहार होता था, वह

बदलने वाला है। अगर यह विश्वास हम मजदूरों के दिल में पैदा कर सकेंगे, तो मैं समझता हूं कि यह एक सुनहरी किरण होगी जिस का देश के आम नागरिक भी स्वागत करेंगे। इस बिल में जो विशेष रुप से प्रयत्न है कि जो कुछ भी रुपया मिलेगा और जो खास तौर से मिल-मालिकों के बगल से निकलेगा, उस का वे जमा करें। जहां तक इस बात का ताल्लुक है, मैं इस का स्वागत करता हूं लेकिन यह सन्देह जरुर है और दूसरे साथियों ने भी यह सन्देह प्रकट किया है कि जहां तक अदालतों का ताल्लुक है, अभी तक उन्होंने अपनी भावना नही बदली है और मैं यह चाहता हूं कि मजदूरों के कानूनों को लागू करने के लिए एक नये किस्म की अदालतें होनी चाहिए और वे नये किस्म की अदालतें एसी होनी चाहिए जिन के अन्दर मजदूर वर्ग के लोग बैठे। उन के अन्दर बहुत लम्बे चौड़े कानून की ऐसी जरूरत नही है कि वह वकालत पढ़ा हुआ हो। मजदूर अपने हितों को और जो कुछ उस को मिला है या जो कुछ कानून उस को देता है, उसको अच्छी तरह से समझता है,। इसलिए इस तरह की मिली-जुली अदालतें हों और उन के अन्दर मजदूरों के झगड़ों के फैसले हों जैसे कि अगर किसी ने रुपया चुराया हैं, तो यह एक फैक्ट की बात होगी और इस सूरत में उस फैक्ट को जानने के बाद, उस का निर्णय हो। अब इस चीज को मजदूर ही कच्छी तरह से समझ सकता है। और दूसरे लोग, जिन का मजदूरों से वास्ता नहीं है, किस तरह से ऐसी बात का निर्णय करेंगे। व कहेंगे कि हां, यह ठीक है पर यह मालिक कैसे वाला है और अगर इस को जेल में भज दिया जाएगा तो मिल बन्द हो जाएगा और फिर कैसे काम चलेगा। इस तरह से ये अदालतें इस तरह की बातें सोचती हैं और एक लीनियन्ट व्यू लेती हैं। इस तरह से जो समाजिक बुराइयां हैं उन के सम्बन्ध में ये अदालतें लीनियन्ट व्यू लेती हैं और ये अदालतें कम इस तरह के कानूनों को अच्छी तरह से नहीं चला सकतीं। इसलिए मैं चाहूंगा कि हम पुनरावृत्ति करें और हमें इस बात पर सोचना चाहिए कि मजदूरों के तमाम कानूनों को लागू करने के लिए किस प्रकार की अदालत हों और उन में किस प्रकार के कमिटिड व्यक्ति हों।

एक दिक्कत यह है कि मजदूरों के जो कानून हैं, उन के लिए केन्द्रीय सरकार के मंत्री कहते हैं कि हम इस में क्या कर सकते हैं क्योंकि यह तो प्रान्तीय सरकारों से सम्बन्धित हैं और प्रांतीय सरकारें ढील दिखाती हैं। हमारे विधान में दोनों सरकारों को अधिकार दिया हुआ है और मजदूरों का जो मामला है वह एक तरह से कानकेन्ट लिस्ट में भी आता है। तो इस विषय में मैं समझता हूं कि हम को झिझक नहीं करनी चाहिए और प्रान्तीय सरकारों और केन्द्रीय सरकार, इन दोनों के अन्दर एक क्षमता होनी चाहिए और उन की अप्रोच एक ही होनी चाहिए। इस विषय में अगर प्रान्तीय सरकारें ढील करें तो केन्द्रीय सरकार को उन को मजबर करना चाहिए और इस के लिए कोई रास्ता निकालना चाहिए और विधान के अन्दर इस के लिए अगर कोई परिवर्तन भी करना पड़े, तो करना चाहिए जिस से कि केन्द्रीय सरकार उस मामले को उठा सके जिसमें कि प्रान्तीय सरकार आगे नहीं बढ़ना चाहती। तो ये तमाम चीजें हैं, जिन को मैं चाहता हूं कि सरकार को करना चाहिए। यह जो बिल आया है, इस का मैं स्वागत करता हूं और पूरा समर्थन करता हूं लेकिन मैं यह समझता हूं कि अभी हमें एक बहुत लम्बी राह तय करनी है। जैसा कि राम सिंह भाई जी ने और दूसरे लोगों ने कहा है कि ई०एस०आई० के जो अस्पताल है, उन की हालात बहुत बुरी है। आज जो मजदूर है वह उन अस्पतालों में जाना नही चाहता? वह मिल-मालिकों से कहता है कि आप हमें वहां मत भेजिये और अपने ही हमारी दवादारु का इन्तजाम कर दीजिए। हम पैसा देते रहेंगे और आप चाहे अपना पैसा डालें या न डालें। वह ई०एस०आई० अस्पतालों में जाता नहीं है क्योंकि वहां उस को कोई पूछता नहीं है। जो आम अस्पतालों की हालत है वह हालत ई०एस०आई० अस्पतालों की हो गई है। यह हमारे लिए लज्जा की बात है मजदूर उस के लिए पैसा देता है लेकिन उस का ईलाज ठीक से नहीं होता। इसलिए गवर्नमेंट

[श्री अमरनाथ विद्यालंकार]

इस चीज की देखे और वहां की जो हालत है, उस को सुधारे और वहां जो डाक्टर हों कमिटेड डाक्टर हों। मैं उस दिन की प्रतिक्षा में हू जबाक न सिर्फ उन मजदूरों को, जो कि कन्ट्रीब्यूट करते हैं, बल्कि हरेक मजदूर को जो मेहनत करता है, सुविधाएं मिलें और वे अपना ईलाज ठीक तरह से करा सकें। हम जिस समाजवाद की स्थापना करना चाहते हैं उस समाजवाद के अन्दर हरेक नागरिक को, ईलाज, जो कि एक मिनिमम चीज है, की सुविधाएं प्राप्त हों और जब वह ईलाज के लिए जाए तो उसका उसी तरह से ईलाज मिले जिस तरह से किसी दूसरे बड़े व्यक्ति को मिलता है। इसलिए मैं बिल का समर्थन करता हूं और इस बात के लिए मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता लेकिन मैं उन से यह प्रार्थना करना चाहता हू कि वे एक बहुत प्रगतिशील व्यक्ति है और बड़े कमिटड व्यक्ति है। मैं समझता हूं कि उनके होते हुए जितने भी मजदूरों के कानून है उन की पुनारावत्ति होगी और उन तमाम कानुनो को वे इक्ट्ठा यहां संसद के सामने लाएंगे और वह उन को पास करेंगे और फिर उन कानूनों का ठीक तरह से इम्पलीमेंटेशन हो जिस से हरेक मजदूर और एक टोकरी ढोने वाला मजदूर भी यह महसूस करे कि अब जो देश का शासन चलाया जाएगा, वह मेरे लिए चलाया जाएगा और वह मेरे हित में चलेगा और मुझे जो कुछ भी काम करना है, वह देश के हित मे करना है।

इन शब्दों के साथ में इस बिल का स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं।

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI RAGHUNATHA REDDY): Sir, I am extremely thankful to the hon. Members, who had given a very warm welcome to the provisions of the Bill, specially the one raising the limit from Rs. 500 to Rs. 1,000.

Some criticisms have been made with regard to some of the provisions and also the working of the hospitals. Shri Ram Singh Bhai elaborately dealt with how some of the hospitals are working, the need to improve them and the way in which they should be improved. I am fully aware of the fact that some hospitals in some States are not in a very happy position and that they are not working properly. But it does not mean that all the hospitals under the ESI Corporation in all the States are not working well. Some of the hospitals are doing very well. I have no hesitation to say that they are doing much better than the hospitals that are being run by the State Governments; specially in Tamil Nadu, Mysore, Kerala and Maharashtra some of these hospitals are doing very well though, unfortunately in some States some hospitals are not working well. In this regard you may kindly appreciate that the entire management of these hospitals, the administration of these hospitals, the posting of doctors, is completely in the hands of the State Governments and within the jurisdiction of the State Governments. I do not want to take cover under the plea that it is only because it is under the State Governments that it is happening. The State Governments are taking more and more interest in this matter.

During the Labour Ministers' Conference we had pointedly discussed this question as to how these various hospitals should be improved and what steps should be immediately taken. As a matter of fact, in the nature of programmatic action it has been decided that the Labour Ministers should particularly take interest in this matter and see to it that the working of these hospitals improve. You will kindly realise that the hospital administration should be under the Health Minister and not under the Labour Minister even with regard to the ESI Corporation. That is why there are some technical difficulties involved.

The next day when the ESI meeting was called, again this question was discussed about the improvement of the

hospitals, the working of the hospitals, the way in which the steps should be taken by the ESI Corporation itself and what the regional committee should do. These questions were discussed for nearly three or four hours and it has been decided that the Regional Board should meet within a period of 20 days and should go into the working of the hospitals within the particular region of the State and see in what manner they should be improved and should take the necessary steps for the purpose of improving the working of the hospitals and send reports. I do not for a moment say that everything is all right. I can only hope that wherever steps are necessary they are being taken.

Another point that was made was that ESI hospitals do not attract better talent. Shri Sanghi particularly mentioned that special equipments, anesthetics etc. and specialists are not available in these hospitals. Bearing this in mind, we are thinking of having a central hospital for a particular area where we can have specialists, technical experts and also research facilities so that, apart from giving specialised treatment, those hospitals may be able to contribute to the general health of the area i nterms of research.

Then, certain very pertinent questions about law have been raised. It is only when I heard the speech of Dr. Ranen Sen that I realised that he knows so much of law because he analysed the various provisions of the law with absolute clarity and understanding. Of course, my good friends, Shri Stephen and others have also made certain points with regard to the interpretation of section 85 and the way in which it should have been done. I am not for a moment saying this section could not have been improved; it could well have been improved. For the time being, when this Bill was being drafted, we thought that perhaps this may be sufficient. After these provisions are made applicable and they work for some time, if we find that revision is needed, there will be no hesitation in doing that.

Dr. Ranen Sen and Shri Stephen had pointed out with regard to section 85(a) that we have taken it out and we have provided a different type of punishment. Under the existing section 85, it is only three months. We have almost doubled the punishment from three months to six months. Even with regard to (a), compulsory punishment has been provided with regard to subsequent offence.

Then a pertinent question has been raised by Dr. Ranen Sen and Shri Stephen why it is not included for the purpose of providing punishment for subsequent offence by way of minimum compulsory punishment. At this stage I can tell you that the same type of provision has been made with regard to the Gratuity Act and we wanted some uniformity of legislation in regard to social security matters

The second consideration was this which, being a very distinguished lawyer, he will understand well. Whenever we provide for compulsory minmium punishment in any legislation, if the court on consideration of the materials before it feels that it does not have enough evidence to award the minimum punishment in the circumstances of the case, it would rather prefer to acquit the accused than give the minimum punishment to the accused. You may kindly recall that under the Indian Penal Code, for instance, for dacoity with deadly weapons or arms the minimum punishment is seven years of imprisonment. A technical offence can be proved as an offence which comes within the definition of dacoity with arms. In such cases, the courts when they are compelled to give seven years compulsory imprisonment have rather acquitted the accused than having a feeling that conviction of the person for seven years imprisonment is not called for. That is the reason why it has been thought to be reasonable.

[Shri Raghunatha Reddy]

It may be warranted or not warranted. There may be two opinions on it. But this is the consideration we had in our mind. If this consideration is found to be unwarranted, certainly, I will not hesitate to come forward with an amending Bill in order to rectify some of the things which have been mentioned by my friends here.

Another question that has been raised is this. The hon. Member, Mr. Stephen, who is also a very distinguished lawyer referred to Section 85A where it is stated:

> "Provided that where such subsequent offence is for failure by the employer to pay any contribution which under this Act he is liable to pay, he shall for every such subsequent offence, be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year but which shall not be less than three months and shall also be liable to fine which may extend to four thousand rupees."

What we have mentioned is, "any contribution". For the purpose of interpreting this proviso, "any contribution" must be understood in the context of the objective as such. The objective as such here concerns with "any contribution". Therefore, it must be in relation to a particular contribution relating to which an offence has been committed. If this violation is repeated, then it becomes a subsequent offence and that is the way in which the concept of "subsequent offence" will have to be understood. I do not think there is any ambiguity there.

Another point that has been raised by my hon. friend, Shri Raja Kulkarni, about Section 93A is as to what is the meaning of "in any other manner whatsoever". The transfer of any factory can take place from one employer to some other person in several ways, like, by sale, gift, lease or licence or in any other manner. The transfer of property can take place from "A" to "B". As far as acquisition of property is concerned, acquisition by the Government is done by a statute and, whether this provision will be applicable or not, it will depend upon the nature of the statute which is passed for the purpose of acquisition. As to what would be the effect of that statute on the provision of the law, then only one can express an opinion, not now. Therefore, I would not like to go into that question.

Another aspect that has been raised is about the provision of amendment of Section 405 in order to take away any ambiguity that may be in the mind of the court that in such a case of keeping money of the employee by the employer, whether it would amount to entrustment or not within the meaning of Section 405. I would like to draw the attention of the House to Section 85 of the principal Act. Here, *mens rea* is not involved. If an offence can be proved that the employer has kept the money of the employee—whether it is done with good or bad heart, we are not concerned with it—if once technically an offence can be proved, the punishment follows. No *mens rea* is called for. The punishment follows. As far as the criminal breach of trust is concerned, where the guilty mind is there, the entrustment must be proved. For that purpose, Section 405 has been amended to remove any kind of ambiguity that might exist in the interpretation of the law or in the minds of Judges. That is the purpose. This has been provided for the purpose of awarding punishment for a criminal act. For a criminal breach of trust, under Section 405, the punishment can follow if the offence can be proved.

The punishment provided in the Bill are reasonably deterrent. If

these are not found to be enough, Section 405 can be made use of for further punishment in case of a criminal breach of trust. In these circumstances, I hope, the hon. Members will appreciate, after allowing these provisions of the amending Bill to work for some time, if a revision is called for, certainly, I will not hesitate to come forward with another amending Bill and get it passed.

With these words, I commend the Bill for the acceptance of the House.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill further to amend the Employees' State Insurance Act, 1948 and to incorporate an explanatory provision connected therewith in section 405 of the Indian Penal Code, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: There are no amendments to clauses 2 to 9.

The question is:

"That clauses 2 to 9 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 to 9 were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That Clause 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

SHRI RAGHUNATHA REDDY: I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

16.42 hrs.

TELEGRAPH WIRES (UNLAWFUL POSSESSION) AMENDMENT BILL

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (DR. SHANKER DAYAL SHARMA): I beg to move:

"That the Bill further to amend the Telegraph Wires (Unlawful Possession) Act, 1950 as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

Sir, the losses on account of theft of copper wire from the telegraph alignments have been steadily on the increase. This Telegraph Wires (Unlawful Possession) Act, 1950 regulates the possession of the telegraph wires and provides for punishment for unlawful possession. Amendments to certain sections of the Act are considered necessary in order to curb more effectively the theft of telegraph copper wire in the country. As we all know, these thefts not only result in loss to the department, but also result in dislocation of communication. Consequently, it is thought that we must make the provisions more stringent.

The Telegraph Wires (Unlawful Possession) Act was originally passed in 1950 with the main object of simplifying the procedure for prosecution and conviction of persons who committed theft of telegraph copper wires. In the light of the working of the Act, this Act was amended in 1962. In 1962, it was provided that there would be a minimum punishment for the second and subsequent offences by the same set of persons or by the same person. Again, it was found that these amendments could not achieve the desired object. It is now proposed to amend it and make it more rigorous. However, when we are amending it, it has been proposed that the definition of telegraph copper wire is also amended to bring it in consonance with the decimal system which we have adopted. Consequently, it is proposed to amend Section 2(B) to define telegraph wires in a

[Dr. Shanker Dayal Sharma]

manner that has been approved by the Indian Standards Institution. The P. & T. Department has been using three types of gauge. They were originally defined in the light of weight—150, 200 and 300. On the adoption of the metric system of units as a national policy to replace the earlier system which was known as F.P.S. system, a new specification for copper wire has been adopted. It has been drawn upon with the approval of the Indian Standards Institution wherein new gauges of wire for telegraphic and telephone purposes have been drawn up in terms of their girth —diametres. The new guages, though they are closely approximate to the gauges of wires which are now in use, there are some slight changes and consequently, we have tried to define them in such a manner that both the wires under the old standard and the new standard come in the range of prohibition.

Similarly, we have amended Section 5 of the Act which was amended in 1962 and which provided for a deterrent punishment in the case of subsequent offences. Now, it is proposed that in the case of the first offender also there must be minimum punishment and if the court departs from it, it should put it in writing or give the reasons therefor.

So far as these changes are concerned, they were called for because the Public Accounts Committee of this House itself has been talking about the gravity of the offence. Then again the whole matter was considered in the conference of the Inspectors General of Police in July 1964. They also suggested that the first offence should be made punishable. Of course, I may take the House into confidence. It is not that the Department has not been trying. We have been trying, but, sometime, it so happened that we got the Bill passed in the Rajya Sabha in 1966 but because of the dissolution of the House in 1967, it could not be passed. We again got it passed in the Rajya Sabha in 1968 and then again, the 1971 elections came and the Bill could not go through. Now, we got it passed again for the third time by the Rajya Sabha on 25th November 1974. Somehow it could not come to the Lok Sabha till to-day. So, to-day we have brought it. I just made this clear because we have not been sleeping over it. We have been trying but circumstances beyond our control did not permit us to get it through both the Houses.

We have made certain consequential changes. One of them is that the original Act provided that the court will take cognizance only when an officer specially authorised for the purposes makes a complaint. Now we have provided in the place of the long list of those persons who can complain, simply that a public servant within the meaning of Section 21 of the Indian Penal Code will have the right to move the court. Another thing we have done is that the original Act did not provide for search and seizure by the Police We have provided for it and we have also provided for confiscation of unlawfully possessed telegraph wire which had not been provided earlier. At the same time we have provided for the confiscation of any vehicle or any mode of conveyance used for transporting these wires from one place to another. These are the attempts which have been made so far as this Bill is concerned which is in consonance with the wishes of the House. It is a completely non-controversial Bill and I hope that the House will pass it unanimously.

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That the Bill further to amend the Telegraph Wires (Unlawful Possession) Act, 1950 as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

श्री बाज सिंह भोरा (भटिंडा) : सभापति महोदय, यह बिल जैसा मंत्री महोदय ने अभी बताया बहुत सिम्पल है। छोटा सा भी और सिर्फ दो तीन अमेंडमेंट्स इस में हैं।

अमेंडमेंट्स तो छोटे छोटे हैं मगर तीन चार साल हुए 1971 में जब यह हाउस आया तो इतनी देर गवर्नमेंट क्या करती रही यह हमें पता नहीं । इतना छोटा बिल इतने दिनों तक नहीं आ सका इस का क्या कारण है ? ये क्या करते रहे ? क्यों नहीं यह बिल पास हो सका ? अभी भी यह 25 नवम्बर 1974 का उधर से पास किया हुआ है, कितने दिन हो गए ? एक साल होने को हो चला । इस बीच में बजट सेशन निकल गया लगभग तीन महीने का, क्यों नही यह उस में आ सका ? अब इतनी देर के बाद इसे ला रहे है, चलिये यह भी मैं अच्छा समझता हूं ।

पहले 1950 मे यह बिल बना था । उस के बाद अमेंड हुआ । उस समय बहुत दलीलें दी गई कि अब चोरियां खत्म हो जायेगी । लेकिन पास होने के बाद चोरियों की संख्या बढ़ कर 6171 हो गई । 1968 में अमेंड हुआ उस समय भी यह कहा गया कि अब बिलकुल चोरियां नही होगी, मगर उस के बाद चोरियों की संख्या बढ़ कर 10469 हो गई । यह बिल अमेंड होता रहा, दलीलें दी जाती रही और चोरियां बढ़ती रही । अब हमारा ऐसा ख्याल है कि इस समय लाखों में ये चोरियां चली गई होंगी । मैं यह समझता हूं कि कापर वायर इस में ज्यादा होता है जिस की चोरी होती है । अब इन्होंने इसे काफी स्ट्रिंजेट बनाने की कोशिश की है ।

चोरियां रोकने के सिलसिले में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के दरमियान जो लायजन है वह ज्यादा अच्छा होना चाहिए । उस में क्या होता है कि स्टेट की पुलिस होती है, उस के सामने चोरी होती है, वह कहते हैं कि यह तो सेंटर का माल है, इस तरह कर वह आराम से चले जाते हैं । दूसरे, आपके जो मुलाजिम हैं उन का लोगों के साथ रवैया अच्छा नहीं है । हम हर रोज देखते हैं आप का जो टेलीफोन का सिस्टम है उस की तारें तो अकसर खराब ही रहती हैं । आप कोई भी टेलीफोन बुक करा लीजिए, आधे घंटे के बाद पूछिए कि क्या हुआ तो वह कहेंगे कि लाइन खराब है । मुझे तो इस का तजुर्बा है, कभी भटिंडा या मलेरकोटला का टेलीफोन बुक करवा लेता हूं तो तीन तीन चार चार घंटे बैठा रहता हूं, लाइन खराब ही रहती है और टेलीफोन मिलता नहीं है । पता नहीं वहां की लाइन सचमुच खराब रहती है या क्या होता है ? इस के बाद अगर हम कोई कम्प्लेंट किसी की करें तो जो आप के आफिसर हैं एक दफा तो जवाब देंगे, ऐकनालेजमेंट आ जायगा, उस के बाद पूछते रहिए क्या हुआ, कुछ पता नहीं चलेगा । एक बार हमारा टेलीफोन खराब हो गया, मैं ने आपरेटर से पूछा कि मेरा टेलीफोन खराब क्यों है तो वह कहता है कि केवल आप का ही खराब नही है, औरों के भी बहुतों के खराब हैं । मैं ने पूछा कब तक ठीक होगा, उसने कहा कि जब औरों के भी ठीक होंगे तो आप का भी ठीक हो जायगा । मैं ने लेटर लिख कर भेजा डी ई टी फिरोजपुर को, लेकिन आज तक पता नही चला कि उस पर क्या हुआ ? आप के आफिसर कोई परवाह ही नही करते हैं । वह कहते हैं इन के लेटर तो आते जाते रहते हैं । पब्लिक के साथ अगर आप का अच्छा रवैया हो तो पब्लिक भी आप की इन चोरियों को बचाने में सहायक होगी । और अगर पब्लिक के साथ रवैया अच्छा नहीं होगा तो चोरियों को बचाने के लिए लोग आगे नही आएंगे । इसलिए उन के साथ आप के विभाग का रवैया अच्छा हो यह बहुत जरूरी है । एमर्जेंसी में यह आप का विभाग बहुत जरूरी है । किसी भी तरह की सैबोटेज इस में नहीं हो सकती है । इसलिए आपको इस में और भी मुस्तैदी बरतने की जरूरत है । आप यह देखिए कि यह जो चोरियां हो रही हैं इन को रोकने के लिए पब्लिक को आपरेशन

[श्री मान सिंह भंडारी]

सब से ज्यादा जरूरी है। क्यों कि तार तो बाहर होते हैं, पुलिस कहां तक उस को देखेगी। अगर लोगों के दिमाग में इतनी बात आ गई कि यह तो तारों की चोरी हो रही है यह हमारी चोरी हो रही है तो लोग जा कर उसी वक्त पकड़ेंगे चोरों को। फिर वे तार ले जाते हैं रेहड़े पर या बैलों पर ये क्योंकि ये तार काफी वजन में भारी होते हैं। तो जहां जहां यह जाता है वहां उन को भी पकड़ने की जरूरत है।

आज आप के विभाग का जो रवैया है, मैं तो हैरान हूं कि मेम्बर पार्लियामेंट के साथ इन का रवैया ऐसा है, मैंने कई साल पहले एक डी ई टी जो शेड्यूल्ड कास्ट का था उसके बारे में लिखा था। उसे जलन्धर से जबलपुर तबदील कर दिया था, मैंने शेर सिंह उस समय मिनिस्टर थे उन से कहा कि यह कैसे कर दिया उस पर और कुछ तो हुआ नहीं, उस को चार्जशीट दे दिया कि आप ने मेम्बर पार्लियामेंट से क्यों लिखवाया ? हमारे पास तो कोई कम्प्लेंट आती है तो हम जरूर आप को लिखेंगे लेकिन शेड्यूल्ड कास्ट का होने की वजह से उस को चाजशीट कर दिया कि आप ने मेम्बर पार्लियामेंट से क्यों अप्रोच कराई ? मैं तो उस को जानता नहीं, मेरे किसी रिश्तेदार ने बताया। तो यह जो रवैया आप के विभाग का है उस को आप बदलिए।

दूसरी बात-आप नये नये एक्सचेंज खोलते हैं, लेकिन उस में कोई सामान नहीं होता। हम लेटर लिखते हैं तो जवाब आ जाता हैकि एक्सचेंज मंजूर हो गया लेकिन सामान कहां है ? अभी हमारे यहां सरदूलगढ़ जिला भटिंडा में आपने एक्सचेंज मंजूर किया था, वहां सामान नहीं पहुचा, अमरगढ़ जिला संगरूर में एक्सचेंज मंजूर किया वहां भी उस का सामान नहीं। मेरी समझ में नहीं आता यह चोरियां तो तारों की होती है, सामान तो चोरी नहीं होते, फिर सामान वहां क्यों नहीं होता ? इस में सिर्फ आप के विभाग का दोष है। अपने विभाग को आप ठीक करेंगे तो ये चोरियां वगैरह भी ठीक हो जाएंगी और ये शिकायतें नहीं रहेंगी। दूसरी बात मैं यह कहूगा कि जब तक स्टेट मशीनरी और सेंट्रल मशीनरी का लायजन अच्छा नहीं होगा, स्टेट वाले जिम्मेदारी नहीं लेते तब तक ये चोरियां रुकने वाली नहीं हैं। जो सजा आप ने रखी है वह तो ठीक है। लेकिन सजा तो उस वक्त देंगे जब चोर पकड़ा जाय। लेकिन पकड़ा ही नहीं जायगा तो सजा किस को देंगे ? इसलिए चोर को पकड़ने की व्यवस्था पहले कीजिए।

वैसे मैं समझता हूं कि यह बिल अच्छा है और इन शब्दों के साथ मैं इस का समर्थन करता हूं। जो सुझाव मैंने दिए हैं आशा है आप उन पर ध्यान देंगे।

SHRI VAYALAR RAVI (Chirayinkil): Mr. Chairman, as the hon. Minister has stated, while introducing this Bill, it is a small piece of legislation and there is nothing to be argued. I congratulate the Minister for his efforts to prevent the thefts which cause damage to the department as well as loss to the consumers of this essential service. I agree with the views of the hon. Minister that this ought to be dealt with severely. We should not allow these kinds of thefts in the department to occur from time to time. It is very unfortunate that some of the people who are associated with the department are also responsible for these kinds of activities. More of thefts are done not by the people from outside but by the people within. Such dishonest people may be everywhere; but some of them might have introduced into the department also.

16.59 hrs.

[SHRI BHAGWAT JHA AZAD in the Chair]

What happens is this. Usually the department's practice is this. They resort to some departmental action. Departmental action may end with dismissal. But that will not be enough. That is not sufficient punishment. That is why Government has brought this new amendment. I agree that there should be more stringent punishment.

Then I come to the question of seizure of copper wire and other material which might be found in the possession of any person. I would like to have clarification from hon. Minister on one point here, on which I have some doubts. I would like to know that when Government searches any place and finds any quantity of copper wire unlawfully kept there, they should have powers to seize the whole thing and arrest the people who are responsible for holding the wire.

I should like to know whether it is the man who is keeping these things or the whole chain of gangsters should be arrested. Somebody may find a loophole and say that he cannot be arrested as he does not know anything about it. Even though the police might have tried their level best to rope in the real culprits, they will escape on a simple plea that they do not know anything. Usually, it is the department which handless this thing. So, I appeal to the Minister that the loophole in the Act should not be misused. Even the diameter of a wire is small and if it is a piece of wire, and found in possession of a man he can be charged guilty. This kind of misuse ought to be avoided.

17 hrs.

I think this is a very good measures. I am glad that the Government has taken note of this. The magnitudue of theft is very high that sometimes the whole length of the telephone wire from one post to the other is taken away by the professional thieves. So, it is necessary that constant vigilence should be kept by the department as well as the other agencies that are available with Government. Only then this can be prevented.

I now come to the functioning of the department. This requires to be toned up. Government have divided the department into two—one is the Post and the other is the Tele-communication. I thought that it was a welcome change. Rather from the experience in my State—State of Kerala—I am sorry to say that this has made the services rendered very poor and has made them inefficient. This was very efficient for the last four or five years when it was under the P.M.G. in my State. After this bifurcation of the department into two, the Post and Tele-communication, it has become more inefficient to-day than what it used to be before. This is one part. I do not know whether the services are efficient or not in other parts of the country. So far as Delhi is concerned, it is very bad. This has been bifurcated into two departments with a view to helping some senior officers to get more and more posts. Nothing more it served. This does not help at all. I want the Minister to consider this thing. I am little more concerned about some of the most vital sectors being more inefficient. There are certain people in the telecommunication establishment indulging in anti-national activity. In Kerala Circle there are certain elements like that. I want the Minister to take note of this. We cannot allow such anti-national activity. I do not want to go into the instances that have happened. I am sorry that in my State there are people who are using this telephone system for their own nefarious propaganda and rumours about which I do not want to go into details. I do not want to name them. I can only tell the Minister personally about that. Sir, everything depends upon the General Manager. The efficient functioning of the department or circle depends upon the

[Shri Vayalar Ravi]

calibre or efficiency of the General Manager. If the General Manager is inefficient, weak or corrupt, the whole thing will go to dogs. Unfortunately, that is the state of affairs in Kerala Circle to-day. It all depends upon the efficiency of the General Manager. I hope the Minister will look into the matter and see that he restores the earlier efficiency. The efficient system as it existed earlier ought to be restored by him. I hope he will also agree with me that we cannot afford to have security risk in the P & T Department. I hope he will act with stern hands. It is my request. I do not want to go into details of it.

Lastly, I fully agree with what the friends on the other side said about efficiency. Sir, here, I would also like to mention one other severe problem in regard to Kerala. There is no equipment supply. I raised a question here as to why they are purchasing from outside. Because of this question, the whole purchase has been stopped. People are coming to me and telling about this. We could at least make open market purchases and keep the system going. The whole purpose of the question in the Parliament was to draw the attention of the Government to the irregular supply of material. There is not only irregular supply but there is also no supply at certain times. This will harm the interests of the consumers of Kerala. I agree that Kerala is at the far end of the South. But, that is not the reason for the Department in Delhi to delay the whole supply of material to Kerala and make the consumers suffer a lot. Because of my innocent question, the purchase has been stopped and the people are suffering. I appeal to the hon. Minister to examine this matter and see how much material has been supplied to Kerala, what is the demand from Kerala and how far they are able to supply. He should examine this matter and see that the department makes a regular supply of equipment, even of small wires, to Kerala. This is a small thing which should be looked into.

Lastly, I have a request to make to the hon. Minister. Myself, Mr. C. K. Chandrappan and Mr. K. Balakrishnan, all three of us, come from the same place, Shertalai. In fact, we are neighbours. We have represented to the hon. Minister not only to Dr. Sharma, but to Mr. Bahugna, the then Minister, as well. This is a very small request, namely, that there should be an automatic exchange at Shertalai. We have been making this demand for the last four-five years and we have been getting a reply that the machine supply is less. I agree, it may be less. But, this facility should be provided. I hope my friend Mr. Chandrappan will agree with me. I appeal to the Minister that he should consider this small request of the three Members of Parliament.

Sir, I would also like to refer to the attitude of the General Manager in Delhi. Sir, Dr. Sharma is the Minister and I can talk to him. I can contract him through his P.A. But, if you want to complain to the General Manager, you are not able to contact him. You cannot talk to him. The girl in the Telephone Exchange will answer and you cannot talk to him. There are some visiting hours; between 3 P.M. and 4 P.M., you can go and see him. I do not know why the facilities which are not available to the Minister are being given to the General Manager. I had no occasion to see his ugly face so far. But, this kind of arrogant attitude by officers should be looked into. He is the General Manager. He must be available to the public. He should be accessible to the public because people may wish to make complaints in regard to the working of the Telephones Department. Even, you, Mr. Chairman, are not able to contact him in the house. This is a very shocking thing that in Delhi, this is happening.

that the General Manager is not available. May be, thinking that many MPs and others will call him, he wants to avoid them. I do not know.

I hope the Minister will consider my requests in regard to the regular supply of material to Kerala, setting up of an automatic telephone exchange at Sheertalai and a general toning up of the whole system in Kerala. With these words, I support the Bill.

SHRI K. MAYATHEVAR (Dindigul): Mr. Chairman, Sir, I welcome and support this Bill. The offence set out in this enactment is a very serious and grave offence. In other words, it can be called an anti-national offence. Therefore, we must deal with this offence very severly and sternly. That is why, we welcome this Bill with all happiness and pleasure.

Sir, after the emergency has been proclaimed by the President and after the announcement by the Prime Minister of the twenty point economic programme, almost all the States are using MISA. In Tamil Nadu especially, MISA has been used against prohibition offenders. We welcome this because these are anti-national and anti-social offences. Whatever may be the Government, we welcome the action taken by them for reforming the society and to help the poor masses.

Either this way or that, it is welcome. Prohibition offenders are arrested under MISA in Tamil Nadu. Then old offenders who are committing thefts of railway property, rails and so on, are also rounded up in Madras under this. I request the hon. Minister and the Central Government to give instructions to all State Governments to use MISA against offenders under this offence also since it is an anti-national and a very serious offence which cannot be excused very easily, legally speeking, socially speaking or even morally speaking.

Regarding amendments introduced in the main Act, you have given a minimum punishment of one year or a fine of Rs. 1,000 for the first offender. I am a practising criminal lawyer in the Madras High Court. I have dealt with so many identical criminal cases. You have given the option to the magistrate or judicial officer, whoever may be the person presiding over the court. You have given him absolute discretion to award a fine of Rs. 1000 or imprisonment for one year. As the hon. Minister previously mentioned before this House, regarding dacoity and robbery the relevant sections are 392, 395 and 397 IPC, and the minimum sentence is imprisonment for 7 years. But here the minimum sentence proposed is one year or Rs. 1,000. I recommend to the hon. Minister to raise this to Rs. 2000 and two years. Both should be given concurrently to the convicted. You have given discretion to the magistrate to award one year and/or Rs. 1,000. That being so, the magistrate will always prefer to be lenient because the advocates will be pleading before the court 'My lord, since he is a first offender, you leniently deal with him'. Therefore, the magistrates on the recommendation, pleading and arguments of advocates in various High Courts throughout India, not only in Tamil Nadu, are inclined to impose a fine, not award imprisonment. Therefore, I would request the hon. Minister to be more deterrent since this is an anti-national offence and both should be awarded: sentence of two years imprisonment and fine of Rs. 2,000, not one year or Rs. 1000 as you have provided under cl. 3.

Regarding habitual offenders or second or subsequent offenders, this is their business and profession. These fellows should be dealt with very severely. You have laid down in the pertinent section of the Act five years imprisonment and Rs. 3,000. That

[Shri K. Mayathevar]

should be the minimum, not the maximum, or second and habitual offenders. But nothing is found in this Bill regarding the quantum of punishment to be awarded to the second and habitual offenders. I recommend very strongly that the punishment to them should be as I have suggested. These follows are monied fellows. Their hirelings and agents commit these offences. The money goes to some monopolist or capitalist group. But some poor people are engaged regularly in this business.

Regarding rail thefts in Madras, MISA has been used against offenders committing theft of railway property. There is one man. I can give his name itself. He is one of the leading thieves of railway property in Madras. Any railway property not found in railway junctions may be found in his place or shop. That fellow has not yet been arrested. His name is Madar. The hon. Minister or the Department can take note of this. He is a leading fellow there. He is a multi-millionaire. He is not touched. Ordinary fellows are arrested. Let them be arrested. But persons who are liable to be arrested under these offence may also be arrested. Therefore, the minimum punishment under this Bill should be two years and Rs. 2000 and the maximum should be five years and Rs. 3000. This is a preventive measure; this is not consequential to the office. You should make it more stringent and deterrent to reform habitual offenders and thieves. It should be made a cognisable offence. Only then they could be arrested without a warrant issued by the judiciary or the court that have jurisdiction to try the case. Finally the offence should also be made non-bailable. Robbery, dacoity, etc. under section 307, 302 I.P.C. are non-bailable. Minor offences are bailable offences. This should not be treated as minor or ordinary officence; it should be treated as a serious offence and anti-national offence. It should be non-bailable. Only then the big persons would be afraid of committing or repeating this offence. It will automatically reform the habitual offenders.

Mr. Ravi made certain points. If some wire was found in the possession of somebody who was responsible for that? I am clarifying that point. Under the Railway Property unlawful possession Act a person who is in possession of the rail way property should explain how he came into the possession; otherwise he is liable to punishment. There should be an identical provision in this matter also; then only the case against the offenders could easily be proved. The then should not only rest with the police; it should be shifted partly to the offenders. Then only it will be reformative and deterrent. I request the hon. Minister to raise the minimum sentence for the first offence, from one to two years and the fine from Rs. 1000 to Rs. 2000. I request the hon. Minister to consider my other suggestions also. With those suggestions I welcome the Bill.

श्री शिवनाथ सिंह (झुंझनु) : सभापति जी, टेलीग्राफ वायर बिल का यह संशोधन एक बहुत मामूली संशोधन है, लेकिन यह एक स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि तारों की चोरी इस देश में बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ी है और जैसा मंत्री जी ने कहा है, इस के कम्यूनिकेशन में बहुत दिक्कत होती है । इस लिये इस कानून को सख्त से सख्त बनाया जाना बहुत जरूरी है । मैं इस अवसर पर दो-तीन बातों की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान खींचना चाहता हूं ।

आप के आफिसर्ज ने इस बिल को इस लिए बनाया कि देश में तारों की चोरी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इस लिये सख्ती से काम लिया जाना चाहिए । लेकिन वे एक आस्पेक्ट

बिलकुल भूल गये । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान क्लाज 3 की तरफ आकर्षित करूंगा—क्लाज 3 में, जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि फर्स्ट आफेण्डर को एक साल से कम की सजा नहीं होगी और एक हजार रुपये से कम जुर्माना नहीं होगा । दोनों में से कोई भी हो सकता है या दोनों साथ साथ भी हो सकते हैं । अब मैं ध्यान दिलाऊंगा क्लाज 4 के सब क्लाज 6 (बी) की तरफ । यहां आपने रखा है कि यदि कोई मवेशी की मदद से, मवेशी पर लादकर या दूसरे कन्वेएन्स से तार ले जाता है तो चाहे चोर पकड़ा जाय या नहीं, लेकिन जो कन्वेएन्स उस को ले जाने के लिये काम में लाई गई है उस को फोरफीट कर लें । और फोरफीट करने के बाद जिस व्यक्ति का वह कनवेयेंस है वह चाहे तो बाजारू कीमत कोर्ट में जमा करे, या वह जब्त हो गई । आज आप देखते हैं कि चोरी करने वाला बहुत सावधानी से चोरी करता है । हम देहात में रहते हैं स्टेशनों से उतर कर घोड़ा तांगे में बैठ गये या ऊंट गाड़ी ले ली । आज एक घोड़ा तांगा की कीमत 2, 3 हजार से कम नहीं होती । चोर सामान रख कर कहीं चला गया और तार तांगे वाले के तांगे में मिल गया तो उस की पूरी सम्पत्ति आप ने जब्त कर ली । चोर को 1,000 रु० से अधिक जुर्माना नहीं होगा, लेकिन जिस की गाड़ी है उसमें चोरी का सामान मिल गया तो उस को तीन, चार हजार रु० नुकसान हो गया, और अगर बस में ले गया तो 30, 40 हजार रु० की कनवेयेंस कनफिसकेट हो गई । यह ठीक नहीं है । मैं निवेदन करूंगा कि वह लौटाना नहीं चाहिये, लेकिन इस क्लाज में जो आप ने रखा है उस की जिम्मेदारी सब डाल दी उस पर जिस की गाड़ी है । आप ने कहा है :

.. unless the owner of the conveyance or animal proves that it was so used without the knowledge or connivance of the owner himself, his agent, if any....."

यहां तक तो ठीक है कि उस की कनाइवेंस नहीं होनी चाहिये । वह कह दे कि मेरी कनाइवेंस नहीं है तो ठीक है । लेकिन आगे आप कहते हैं :

"....and the person in charge of the conveyance or animal and that each of them had taken all reasonable precautions against such use:"

इस की पाबन्दी कर दी कि किसी के घोड़ा तांगे में यदि बैठोगे तो आप का वह सब सामान खुलवा कर देखे कि कहीं उस में कोई चोरी का सामान तो नहीं है । बस में बैठोगे तो हर मुसाफिर का सामान वह पहले खोल कर देखेगा । क्योंकि उस के बिना "रीजनेबिल प्रीकौशन" हुआ ही नहीं । कहीं गठरी में उस ने बांध दिया, या बोरी में डाल दिया या बक्से में डाल दिया और उस ने रीजनेबिल प्रीकौशन नहीं लिया तो उस की कनवेंयेंस और बस सब जब्त हो गई । मैं मंत्री जी से कहूंगा कि आप ने इतना कठोर पीनल ला बना दिया है कि जिस से चोर तो बच जायगा लेकिन जो ईमानदारी से अपना भाड़ा कमाने का धंधा करता है वह बेचारा फंस जायगा । इसलिए आप अपने अधिकारियों का थोड़ा ध्यान दिलाइये कि देहात में जहां इस तरह के कनवेयेंस काम में आते हैं वहां जरा सावधानी बरतें । अन्यथा डर के मारे भाड़ा कमाने वाले पहले सब का बिस्तर खुलवा कर देखेंगे अन्यथा रीजनेबिल प्रीकौशन नहीं माना जायगा । मंत्री महोदय सोच सकते हैं कि इस से कितनी दिक्कत लोगों को होगी ।

मेरा निवेदन है कि आखिर के यह शब्द आप हटा दें "....and the person in charge of the conveyance or animal and that each of them had taken all reasonable precautions against such use;"

[श्री शिवनाथ सिंह]

इस को यदि आप हटा देंगे तो पहले वाला यदि कनाइवेंस से होगा तो सजा पायेगा। और अगर नहीं होगा तो सजा नहीं पायेगा।

सभापति महोदय : आप का मतलब यह है कि चोरी का सामान ले जाते हुए भी अगर पकड़ा जाय तो उस को छोड़ दिया जाय ?

श्री शिवनाथ सिंह : जी नहीं, अगर जानकारी में चोरी का सामान ले जा रहा है तो उस को जरूर पकड़ा जाना चाहिये। लेकिन बिना जानकारी के अगर कोई ले जाय तो उस को सजा नहीं मिलनी चाहिये।

श्री राम हेडाऊ (रामटेक) : सभापति जी, राष्ट्रीय सम्पत्ति की चोरी को रोकने के लिये एक अच्छा बिल सदन के सामने आया है। यह जो चोरियां होती है, चोरी करने वाले के पीछे दूसरी शक्तियां काम करती हैं। चोरी के तार को गलाने वाला या तार को दूसरी चीजों में परिवर्तित करने वाली फैक्ट्री का जो मालिक होता है, यही चोरों को उकसाने वाला होता है। जहां तांबा और पीतल के बर्तन बनाने का धंधा चलता है इस देश में बड़े पैमाने पर, मैं भंडारा जिले में रहता हूं और मैंने वहां देखा है कि वहां जो तांबा और पीतल के कारखानेदार हैं जिन को कोटा मिलता है सरकार की ओर से, जिन का धंधा है उन को भी कोटा मिलता है और जिन का कारखाना केवल कागज पर है, उन को भी कोटा मिलता है, उतने से उन का समाधान नहीं होता। बड़े लोगों को पैसा कमाने की जो हवस होती है वह काफी होती है, तो वहां मैं ने ऐसे कई कारखानेदार देखे जो इन तारों की चोरी करवाते हैं। एक गिरोह होता है जिस के जरिये तार की चोरी करवाते हैं और उस तार को अपने कारखाने की भट्टियों में गला कर उस के बरतन बनाते हैं। वास्तव में इस का कोई रेकार्ड नहीं रहता। यदि रास्ते में माल लाते लाते चोर पकड़ा गया तो सजा हो जाती है, पर यदि कारखाने के अन्दर तार का बंडल चला गया तो मालिक बच जाता है, उस को कोई हाथ नहीं लगा सकता क्यों कि वह यही कहेगा कि यह कोटे का सामान है। यह घटना भंडारा जिले में हुई थी। वहां नगर कांग्रेस कमेटी के प्रेसीडेंट हैं, मैं नाम लेने की हिम्मत कर रहा हूं, क्योंकि बात सही है, यदि सरकार का सी० बी० आई० विभाग इस की जानकारी ले तो यह सब मामला आज फिर से सामने आ सकता है। तो इन महाशय ने कुछ लाख रु० का तांबा चुरवाया और वह गलाया। यह केस पकड़ा गया और पकड़ने के बाद उस जिले के जो मंत्री थे, उस मंत्री के जरिये इस केस को दबाया गया। ऐसी यदि बात चलती रही, मालिक ही चोरी करने लगे और वही उस को दबाने लग गये तो बड़े आदमी को कभी भी सजा नहीं दी जा सकती। सदा छोटे आदमी ही पीसे जाते हैं और जो असली गुनहगार होता है वह छूट जाता है। जो बेचारा पेट के लिये थोड़ा सा गुनाह कर बैठता है वह पिस जाता है, और जो वास्तव में चोरी करवाता है वह बच जाता है। इस चोरी में कांग्रेस (आर) के उस आदमी का कुछ नहीं बिगड़ा। उस कारखाने का नाम निर्वाण मैटल वर्क्स है। उन को बचाया गया। इसलिये आप चोरी करवाने वाले को भी ध्यान में रखिये, और जो कोटा दिया जाता है तांबा, पीतल और दस्ते का, कितना माल कारखाने में गलाया गया, कितना माल कारखाने से बना कर बेचा गया, इस का भी कुछ जोड़ मिलना चाहिये। नहीं तो होता यह है कि कोटा मिल रहा है 10 टन का, माल बन रहा है 20 टन का और हिसाब लिखा जा रहा है 10 टन का। इस प्रकार जो गड़-बड़ी चल रही है इस को रोकना चाहिये।

साथ ही पुलिस विभाग पर इस की बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन पुलिस वालों का भी विचित्र पेशा है कि जब ऐसे बड़े लोगों की चोरी पकड़ी जाती है उस वक्त पुलिस पर

ऊपर से प्रैशर आता है कि नहीं नहीं उस को छोड़ दिया जाय । इस प्रकार बड़े लोग जो चोरी करवाते हैं वह बच जाते हैं । यह बात नहीं होनी चाहिये और इसके लिये इस बिल में यदि प्राविधान हो सके कि चोरी करने वाले से चोरी करवाने वाले को एम० आई० एस० ए० में बन्द करना चाहिये और नान-बेलेबिल आफेंस के अन्दर उस को बन्द कर देना चाहिये, तब जा कर चोरियां कम हो सकेंगी ।

रेल के सामान की चोरी, तारों की चोरी करने वालों का भी गिरोह है जिसका सरकार को पता लगाना चाहिये कि इस के पीछे कौन सी शक्ति काम कर रही है । इस बात की व्यवस्था होनी चाहिये, और ऐसे गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिये ।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

श्री डी० एन० तिवारी (गोपालगंज) : सभापति जी, यह अमेंडिंग बिल बहुत ही साधारण और अविवादग्रस्त है । लेकिन मिनिस्टर साहब ने कहा कि पहले भी एक, दो बार इस विधेयक में संशोधन लाये गये थे और उन संशोधनों के बाद चोरियां बढ़ती गईं । जैसे कहावत है कि मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की । विधेयक में अमेंडमेंट इन्होंने किया, कुछ सैक्शन्स को सख्त किया, लेकिन चोरियों की संख्या घटी नहीं, बल्कि बढ़ गई । हमको डर है कि कहीं इस संशोधन के बाद चोरियां दुगुनी, तिगुनी न बढ़ जायें । मैं जानना चाहूंगा कि पहिले अमेंडमेंट के अनुसार कितने प्रौसीक्यूशन्स हुए, 6, 7, 8, 10 हजार चोरियों में से कितने प्रौसीक्यूशन्स हुए और कितने लोगों को सजा मिली ?

इन्फ़ार्मेशन मिल जाती है कि चोरी हो गई और उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है और न कभी इस एक्ट को काम में लाने की कोशिश की जाती है । मिनिस्टर साहब इस अवसर पर कुछ और भी एमेंडमेंट एक दो धाराओं का कर रहे हैं । जैसे उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाया, वैसे ही मेम्बरान, विभाग की कार्यवाही से लोगों को क्या क्या शिकायतें हैं, इस अवसर का लाभ उठा कर, उनके सम्बध में और आपके विभाग का वर्किंग कैसे चल रहा है, उसके बारे में कहना चाहते हैं । आप वायर की चोरी के लिये सख्त सजा के लिए यह बिल लाए हैं । मैं आपके टेलीग्राफ़ और टेलीफ़ोन डिपार्टमेंट में किस तरह से कार्य हो रहा है, उस के सम्बध में एक दो उदाहरण सदन के सामने रखना चाहता हूं ।

अभी तीन महीने पहले मैंने पार्लियामेंट हाउस से एक तार भेजा था रांची को यहां से अपने जाने के एक हफ़्ता पहले लेकिन वह तार एक हफ़्ता में नहीं पहुंचा और एक हफ़्ता तो क्या आज तक नहीं पहुंचा है । क्या हो गया उस को पता नहीं । उसकी रसीद भी मुझसे कहीं मिसप्लेस हो गई । इसलिए मैं उसकी कम्पलेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं यह बता दूं कि हम तार जो भेजते हैं हम समझते हैं कि वह ठीक समय पर पहुंच जाएगा लेकिन वह पहुंचता ही नहीं । यह टेलीग्राफ़ डिपार्टमेंट की वर्किंग है । ऐसे एक नहीं कितने ही केसेज हुए हैं । मैंने यह सुना है कि जब बहुत ज्यादा तार हो जाते हैं तो वे चिट्ठी के जरिये भेजे जाते हैं लेकिन वह चिट्ठी के जरिये भी नहीं गया । चिट्ठी भेजते तो 10, 15, या 20 दिन में पहुंच जाती लेकिन वह तार पहुंचा ही नहीं है ।

अब मैं टेलीफ़ोन के बारे में बताना चाहता हूं । जो मुफ़स्सिल टाउन्स हैं उन में 10, 10 और 15, 15 दिन टेलीफ़ोन खराब रहते हैं । जब मांगो तो टेलीफ़ोन खराब है, जब ट्रंक कीजिये तो टेलीफ़ोन लाइन खराब है । दिल्ली में 199 पर लगाइए, तो कोई

[श्री डी० एन० तिवारी]

उठाती ही नहीं है । अगर उनसे हेल्प लेने के लिए उसको मिलाते हैं तो टेलीफ़ोन उठाया ही नहीं जाता । क्या हेल्प लें उन से । हम पांच मिनट, सात मिनट तक डायल घुमाते रहते हैं और जब टेलीफ़ोन एंगेज मिलता है, तो समझते हैं कि 199 की हेल्प लेलें लेकिन लगाते हैं तो कोई जवाब ही नहीं देता, 5, 7 और 10 मिनट तक कोई जवाब नहीं देता । क्या करें ? जब 198 को कम्पलेंट करते हैं तो वे कहते हैं कि फ़लानी जगह कम्पलेंट कीजिए । वहां कम्पलेंट करते हैं तो वहां भी बराबर एंगेज मिलता है और कभी कुछ होता ही नहीं । पहले 197 बहुत प्रोम्पटली जवाब देता था लेकिन उसमें भी अब सुस्ती आ गई है । इस इमर्जेंसी के जमाने में कुछ काम तेज़ होना चाहिए लेकिन ये पीछे जा रहे हैं । आज से दस वर्ष पहले पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ़ आफिस का नाम था कि इसका वर्किंग बड़ा एफ़ीशियेंट है और वहां घूस वगैरह नहीं चलती है लेकिन अब तो सारे दोष उसमें आ गये हैं जो कि दूसरे डिपार्टमेंटों में हैं । उसमें घूसखोरी भी है और वर्किंग भी इनएफ़िशियेन्ट है । चिट्ठियां 15, 15 दिन बाद डिलीवर होती हैं । अब तो एक्सप्रैस डिलीवरी की बात हट गई, पहले एक्सप्रैस डिलिवरी भी 5, 7 दिन तक डिलीवर नहीं होती थी, देहातो में नहीं बल्कि टाउन्स में जहां कि दिन में दो तीन डिलीवरियां होती हैं । हाउस ने कभी आपको ज्यादा पावर्स देने में ग्रज नहीं किया । आप चाहे जितनी पावर्स ले लीजिए लेकिन कार्य तो सुचारू रूप से होना चाहिए । काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए जितनी पावर्स आप चाहेंगे, वे पावर्स हाउस आपको दे देगा लेकिन आप सुधार कीजिए अपने डिपार्टमेंट में । क्या सुधार आपके डिपार्टमेंट में हुआ है । अगर वह ब्यौरा आप नहीं दे सकते हैं तो फ़िर और अधिक पावर्स लेने की क्या ज़रूरत है । अगर पहले एक्ट के अनुसार आप कार्यवाही नहीं कर सके, तो नई पावर्स ले कर कागज में बन्द रखें, इससे क्या फ़ायदा होगा । मैं चाहूंगा कि मंत्री जी डिपार्टमेंट की वर्किंग की तरफ़ ध्यान दें और जो एक सुस्ती उसमें आ गई है, उस को दूर करें ।

श्री कमला मित्र "मधुकर" (केसरिया): सभापति महोदय, मैं अपने साथी भौरा जी के बाद चाहता था कि न बोलू, लेकिन बोलना इसलिए जरूरी हो गया है कि आप जो कानून में संशोधन लाए हैं, उसमें यह मंशा जाहिर की है कि इसके जरिये कड़ी सज़ा दी जाएगी ताकि टेलीफोनों के जो तांबे के तारों की चोर होती है वह न हो । इस मंशा से मैं सहमत हूं लेकिन कानून में आपने जो सज़ा दी है उसमें कैद भी और फाइन भी रखा है । इसमें आपने जो Or रखा है, उससे कानून सही तरह से इम्पलीमेंट नहीं होगा । इसलिए मैं चाहता हूं कि आप कड़ी सज़ा दीजिए और इसमें जो Or शब्द है, इसको हटा देना चाहिए और इसमें संशोधन लाकर इसको कर लीजिए लेकिन मैं जानता हूं कि आप ऐसा नहीं करेंगे ।

साथ ही मैं दूसरी यह कहना चाहता हूं कि इस बिल में पब्लिक आपरेशन की बात कुछ नहीं है । मुझे अपने जिले का अनुभव है । हमारे जिला चम्पारन में मोतिहारी के टेलीफोन के एस० डी० ओ की चोरी को हमने पकड़ा और हमने उसके लिए गृह मंत्री जी को तार द्वारा लिखा कि उस के खिलाफ़ कार्यवाही की जाए । उसकी बदली गुजरात में हुई और फिर एक माननीय सदस्य के यहां उसकी पहुंच हुई और नतीजा यह हुआ कि अब उस भ्रष्ट अफ़सर को प्रोमोशन मिल रही है और उसको सज़ा देने में कठिनाई हो रही है । मैं इस बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जब हम लोग सहयोग कर रहे हैं कि लोगों की चोरी पकड़ी जाए और जो लोग ऐसा काम करते हैं उन को

सज़ा दिलवाना चाहते हैं लेकिन बजाए सज़ा देने के उसको छोड़ दिया जाता है, तो फिर सुधार कैसे हो पाएगा ।

मैं आपको अपने यहां का एक और अनुभव बताता हूं । हमारी कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने रेलवे की चोरी करने वाला जो गैंग है उस गैंग को पकड़ा । उसको पकड़ने के बाद वहां जो एस० पी है उस ने उसी पकड़ने वाले को चार्जशीट किया और गैंग को छोड़ दिया । अगर अधिकारियों की ऐसी स्थिति बनी रहेगी, तो कैसे काम चलेगा । आप सोच रहे हैं कि नौकरशाही पर लगाम लगे । लगाम आप जरूर लगायें लेकिन इस बात में पब्लिक कोआपरेशन की बहुत जरूरत है लेकिन इस बिल में मैं पब्लिक कोआपरेशन की बात कुछ नहीं पाता हूं । मान लीजिए कि सरकारी सम्पत्ति की चोरी हो जाती है, तो उसमें पब्लिक कोआपरेशन लेना चाहिए । आजकल तांबा बड़ा महंगा हो गया है, इसलिए तांबे के तारों की बड़ी चोरी होती है और बड़े पैमाने पर यह होती है । चोरी करने के लिए गैंग बने हुए हैं, जिनसे आफ़िसर मिले रहते हैं, और आपके व्यवसायी लोग मिले रहते हैं । उन की कनाइवेंस होती है और चोरी हो जाती है लेकिन कनाइवेंस करने वालों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। कनाइवेंस करने वालों में आपके अफ़सर हों या टेलीफोन डिपार्टमेंट के कर्मचारी हों या व्यवसायी लोग हों, तो उनके खिलाफ़ भी एक्शन लेना चाहिए । हेडाऊ जी ने भी यह सवाल उठाया था और मैं भी निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप कानून बनाते हैं तो उस को खुल कर बनाइये और कोशिश यह कीजिए कि कोई लूपहोल न रहे । लूपहोल होने से कुछ लोग बच जाते हैं। कुछ मित्रों ने कहा कि पता नहीं इस कानून के बनने के बाद चोरी और न बढ़ जाए । मैं उतना निराशावादी नहीं हूं और मैं विश्वास करता हूं कि सुधार होगा । मैं मंत्री महोदय से जरूर कहूंगा कि वे इस बात की कोशिश कम से कम जरूर करें कि पब्लिक कोआपरेशन लिया जाए । पंचायतों के स्तर पर और ब्लाक स्तर पर वे सहयोग लेने की कोशिश करें । पंचायतों के जो मुखिया होते हैं उन का सहयोग लिया जाए । वे आपको बता सकेंगे कि अमुक व्यक्ति ने चोरी की है और अगर वे आपको प्रमाण दे सकें तो उनको रिवार्ड मिलना चाहिए और यह नहीं होना चाहिए कि बजाए रिवार्ड देने के उसको सज़ा मिल जाए ।

इसलिए मेरा कहना यह है कि एक तो इसमें सज़ा में जो Or लिखा है, उसको हटा दिया जाए । दूसरी बात यह है कि पब्लिक कोआपरेशन लिया जाए और तीसरी बात यह है कि नौकरशाही में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसको रोकने के लिए आप कदम उठाएं । मैं समझता हूं कि मंत्री जी इसके लिए जरूर कदम उठाएंगे ।

अन्तिम बात यह कहना चाहता हूं कि जो लोग चोरों को पकड़ने में आपको सहयोग देते हैं उनको आप रिवार्ड दीजिए । इस तरह से उनको एक तरह से इंसेंटिव मिलेगा । आपने फेमिली प्लानिंग करने वाले लोगों को रिवार्ड दिया है, उसी तरह से यहां पर आप रिवार्ड देने की व्यवस्था करें ।

संक्षेप में मेरे कहने का मतलब यह है कि कानून में कोई लूपहोल नहीं रहना चाहिए और साथ ही साथ पब्लिक कोआपरेशन लेना चाहिए और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिएं । इसको हमारे लोगों ने और आपके लोगों ने भी कहा है और इस तरह से अपोजीशन में और आप में इस मामले में कोई फर्क नहीं रहा है । मैं चाहूंगा कि सुधार होना चाहिए और मैं सुधार की आशा भी करता हूं ।

SHRI GIRIDHAR GOMANGO (Koraput): Mr. Chairman, I support the Telephone Wires (Unlawful Possession) Amendment Bill. I feel that the unlawful possession of wires can be checked if the administrative machinery in the department is an efficient one. In Orissa there are numbers of such cases. It would be better if the department could call a meeting of the MPs of that State and request them to give suggestions as to how to check the unlawful possession of wires by thieves.

Advisory Boards are constituted by the Department in all the States. So far as Orissa is concerned, that board seldom meets. The Ministry of Communications made a survey and identified the backward areas and districts, so far as telephone facilities are concerned. So far as the development of telephone facility is concerned, you will find that State-wise Orissa is the lowest. Even in that backward State the districts of Koraput, Keonjhar and Phulbani are more backward than the other districts. This has been identified by the Ministry.

The money which has been provided by the Centre to the State is for the development of the whole State. But it is a fact that this money is utilised only for the development of the developed districts and not for the provision of facilities in the backward districts. When some sympathetic officers were posted by the department in Orissa, there was some development in these areas. But now all these schemes are pending. We, MPs. from the backward districts of the State, are not getting an opportunity to give our suggestions to the department and that is why we are not getting our due.

The administrative machinery should be improved. Now that the telephones have been separated from the postal service, it will be easier for the administration to run the services. They should ear-marked money for the districts which are backward in communication facilities. The Centre should give direction not only to Orissa but to all States to pay special attention to the backward areas and ear-marked money for the development of those areas.

The proposal for direct telephone facility from the district headquarters to the State capital has not yet been completed. When it is completed, there should be provision of communication facility from the sub-divisional headquarters and even panchayats to the headquarters.

I had applied for telephone facilities for me in my village about two years back. That facility has not yet been given to me. I hope it will be done soon.

I conclude my speech with great hope in the Minister of Communications.

SHRI DHAMANKAR (Bhiwandi): I rise to support this Bill.

The original Act was passed in 1950. It is 25 years now, but the offences are increasing every year because firstly the Act and its amendments are not sufficiently deterrent, secondly shortage of copper in the country is increasing and thirdly the technique of cutting wires and disposing of them has also been greatly improved. We cannot also ignore the fact that it is because of collusion or connivance of the staff or linemen that these thefts are committed.

When the wires are cut from an area, the telephone and telegraph services do not work. The telephones are usually idle. I have experience of this. The Tehsildar complaints that the telephone is not working for 8

to 10 months in the year. And sometimes when the wire is cut, the telegraph line is also not working and so, there is no communication between the tehsil and the district headquarters. When this is happening in Government offices, what to talk of the poor citizens who send telegrams? Urgent telegrams to places within 50 miles reach after three days. Telegrams sent from Delhi on Government account to Thana or Bombay reach after two or three days, and when we make a complaint, they say they would enquire.

These wire thefts can be minimised by making the law deterrent. Instead of imprisonment or fine, it should be imprisonment and fine. Along with that, public co-operation should also be taken. Wires run through thick jungles. If the duty of guarding them is entrusted to the members of the gram panchayat and some reward is given to them to check these thefts, I think it will give an impetus to the villagers. They will feel this is their property and that they have to report to Government. These wires are Central Government's property, and normally State Governments do not bother much about them, but if the villagers and gram panchayats are involved and special mention is made of their help, the problem will be solved.

श्री नागेश्वर द्विवेदी (मछलीशहर) : इस विधेयक का मैं समर्थन करता हूं । इस विकास के युग में देश के सुदूर क्षेत्रों के लोगों को सुविधा पहुंचाने के लिए तारों का आप बड़ा विस्तार करने जा रहे हैं । इससे लोग सुगमतापूर्वक अपने कामों को कर सकेंगे । लेकिन जिस तरह से इस में चोरियां बढ़ी हैं उससे इस काम में बाधा भी पहुंची है और उसका बहुत बुरा प्रभाव भी पड़ रहा है । इस कारण से लोगों को वास्तव में जो लाभ मिलना चाहिये उससे वे वंचित हैं । इस वास्ते ऐसी कार्रवाइयों को रोकने के लिए जितने कठोर दंड की व्यवस्था की जाए, उसका हम सब लोग हार्दिक समर्थन ही करेंगे ।

इस में चोरों का ही हाथ नहीं होता है । चोरियां करवाई भी जाती हैं । हमें जानकारी मिली है कि कुछ इस तरह के लोग हैं, बरतन बनाने वाले हैं या कल कारखानों वाले हैं जोकि इस तरह की चोरियां करवा करके अपने कल कारखाने चलाते हैं । इस तरह से जो लोग गैंग बना करके काम करवाते हैं उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाए, उनको इस तरह की कार्रवाइयां करने से कैसे रोका जाए, मैं आशा करता हूं कि सरकार का ध्यान इस ओर भी जाएगा और इसके सम्बन्ध में भी वह कोई उचित व्यवस्था करेगी ।

तारों की चोरियों के कारण तारों में खराबी तो पैदा हो ही जाती है लेकिन आए दिन इस तरह की शिकायतें भी मिलती हैं कि कर्मचारियों का भी इस में हाथ होता है और वे भी इसके दोषी होते हैं । वे अपने काम के प्रति लापरवाह हो गए हैं । जहां तारें कटी नहीं भी रहती हैं वहां भी आम तौर से लाइनें खराब रहती हैं और इस कारण लोगों को लाइन लेने में बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ता है और वे टेलीफोन भी नहीं कर पाते हैं और उनके आवश्यक जो कार्य हैं उन में बाधा उत्पन्न होती है ।

जहां तक विभागीय लापरवाही का प्रश्न है, उस पर मंत्री महोदय को खासतौर से ध्यान देना चाहिये । आज हमारे यहां आपातकालीन स्थिति है और इस सम्बन्ध में उसका लाभ अवश्य उठाना चाहिये । और विभागों में बड़ी सतर्कता आई है । मैं आशा करता हूं कि इस विभाग में भी इसका लाभ उठाया जायेगा ।

[श्री नागेश्वर द्विवेदी]

मैं अपनी कुछ कठिनाइयां मंत्री महोदय के सामने रखना चाहता हूं । जौनपुर जिले में सुजानगंज टेलीफोन का एक एक्सचेंज खोलने के लिये उत्तर प्रदेश के मंडल ने चार-पांच साल पहले तय किया था, लेकिन सिर्फ सामान न होने के बहाने से आज तक उसकी स्थापना नहीं हो सकी है । वहां के रहने वाले बहुत से लोग टेलीफोन लगवाना चाहते हैं, लेकिन अभी तक उनको यह सुविधा नहीं मिल सकी है ।

मैं अपनी एक निजी कठिनाई बताना चाहता हूं । चार-पांच साल से मैं अपनी कांस्टीटुएन्सी में टेलीफोन लगवाने के लिये प्रयत्नशील हूं । जिस जगह के लिये मैंने लिखा, वहां से टेलीफोन की लाइन गई है । खम्भा कुछ गज की दूरी पर होगा । पहले तो यह गलत रिपोर्ट दी गई कि दूरी बहुत है, संसद सदस्य के लिये जो सुविधा है, उसमें टेलीफोन नही दिया जा सकता है । लेकिन कई बार लिखापढ़ी करने के बाद जब कायदे के अन्दर आया, तो कहा गया कि लाइन लगाने के लिये रुपया चाहिये । इस बहाने से तीन-चार साल में अभी तक हमारा टेलीफोन नहीं लग सका है, ताकि हम वहां बैठकर अपने क्षेत्र के छोटे-मोटे कार्यों को कर सकें । विभाग द्वारा इस तरह लापरवाही से काम होता है । जहां तार चोरी करने वालों के लिये कठोर दण्ड की व्यवस्था की जाये, वहां मंत्री महोदय अपने विभाग में भी सतर्कता और सावधानी लाने का प्रयास करें ।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री पन्नालाल बारूपाल (गंगानगर) : सभापति महोदय, संचार मंत्री ने जो विधेयक पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । तार की चोरी के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने बहुत कुछ कहा है । मैं कुछ समस्याओं की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

मैं 24 साल से संसद् सदस्य हूं । मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में राजगढ़, सादूलपुर, भादरा, नोहर, हनुमानगढ़, संगरिया, सादूलशहर, श्रीकर्णपुर रायसिंह नगर, अनूपगढ़ और सूरतगढ़ आदि ऐसे स्थान हैं, जहां पर सारे के सारे डाकघर निजी भवनों में हैं और अब तक उनका किराया कम-से-कम चौगुना दिया जा चुका है । लेकिन संचार मंत्रालय आज तक कोई नया डाकघर नही खोल सका है । श्री राज बहादुर के समय गंगानगर मे एक नई बिल्डिंग बनी थी । उसकी बहुत दुर्दशा है, उसकी मरम्मत का कोई इंतजाम नही है, वहां कोई फर्नीचर नही है, घड़ियां ठीक काम नही करती हैं और बैठने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है । इस तरफ ध्यान देना चाहिये ।

मैं श्री तिवारी की इस बात से सहमत हूं कि डाक तार विभाग मे एक गिरोह ऐसा है जिस के आदमी हर त्यौहार पर इनाम मांगने के लिये आ जाते हैं । जो आदमी कभी तार बांटने नहीं आते, जिन की कभी शक्ल नहीं देखी, वे होली, दिवाली, और विजयादशमी आदि हर त्यौहार पर बधाई देने के लिये आ जाते हैं । तार कोई बांटता है और बधाई देने के लिये दूसरे आ जाते हैं ।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र गंगानगर में ट्रंक काल 5, 5 और 6, 6 दिन नही मिलते हैं । इसकी व्यवस्था ठीक करनी चाहिये । हम देखते हैं कि हमारे ट्रंक काल तो नहीं मिलते हैं, लेकिन जिन बिजनेसमैनों से मासिक बंधा हुआ है, उनको ट्रंक काल्स जल्दी मिल जाते हैं । इस गिरोह का भी पता लगाना चाहिये । उनको सस्पैंड करके उनको सजा देनी चाहिये ।

पोस्ट आफिसेज में सेविंग बैंक और रेडियो लाइसेंस आदि का काम बहुत बढ़ गया है, लेकिन स्टाफ न होने के कारण वे बेचारे काम नहीं कर पाते हैं। उनकी डिफिकल्टी की तरफ भी ध्यान देना चाहिये।

संचार मंत्री बड़े कुशल प्रशासक, कर्तव्यनिष्ठ और कुशाग्र बुद्धि के विद्वान हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि जब से वे मिनिस्टर बने हैं, तब से हमारे पत्रों का जवाब तुरन्त मिल जाता है। इसलिये मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि उनकी ओर से पत्रों का जवाब नहीं मिलता है।

मैं आशा करता हूं कि इस विभाग के कार्य में सुधार होगा।

गंगानगर में पोस्ट आफिस के कर्मचारियों के लिये आवास की समस्या है। यह स्थिति हर जगह है। इनके रहने के लिये क्वार्टरों की व्यवस्था करनी चाहिये। बेचारे डाकिये ठीक तरह से काम करते हैं, लेकिन उनको ज्यादा सुविधा नहीं मिलती है। मेरा तजुर्बा है कि वे समय पर डाक पहुंचाते हैं, लेकिन पता नहीं कि उनको वर्दी समय पर मिलती है या नहीं। मंत्री महोदय, इन बातों की तरफ ध्यान देने की कृपा करें।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा): सभापति महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि सब माननीय सदस्यों ने इस बिल की मंशा का समर्थन किया है। उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए हैं।

श्री बोरा ने कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट्स का को-आपरेशन लेना चाहिए। यह पूरा बिल और तारों की चोरी को रोकने की व्यवस्था सब राज्य सरकारों पर निर्भर रहती है। हमारे पास कोई अलग से एन्फोर्समेंट स्टाफ नहीं है। हमको राज्यों से ही सम्पर्क रखना होता है और इस तरफ पूरा ध्यान दिया जा रहा है। मैंने भी मंत्री बनने के बाद कई राज्यों के मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखे हैं। इससे पहले कैबिनेट सैक्रेटरी ने राज्यों के होम सैक्ट्रीज को भी पत्र लिखे थे। मैंने शुरू में ही एक बात खास तौर से कही थी कि हम यह बिल भी इंस्पैक्टर जनरल्स की मीटिंग द्वारा दिए गए सुझाव के मुताबिक ही लाये हैं। दिक्कत यह है कि हमारी लाइन 9 हजार किलोमीटर है और उस सब के लिए हर जगह इंतजाम करना कठिन होता है। इसलिए सोचा गया कि कुछ इस तरह के प्रावधान किए जायें कि हम उसकी चोरी को रोक सकें।

श्री राम हेडाउ ने कहा कि लोग तार को अपने कारखाने में ले गए और फिर उसका पता नहीं लगा। उसी के लिए हमने इस विधेयक में एक धारा रखी है जिसमें सर्च, सीजर और कोंफिस्केशन का प्रावधान है। इसलिए जहां तक तार के कारखाने के अन्दर जाने का सवाल है, वहां पर भी उसको देखा जा सकता है और पकड़ा जा सकता है। जहां तक तारों का सवाल है हमने जो डैफीनिशन दी है उसके मुताबिक जो तार उस साइज के होंगे, वे हमारे टेलीफ़ोन या टेलीग्राफ़ वायर माने जायेंगे।

यह भी कहा गया है कि इस सम्बन्ध में लोगों को हैरासमैंट नहीं होना चाहिए। मूल एक्ट में दस पौंड से ज्यादा तार निकलने पर ही इस कार्यवाही की व्यवस्था की गई है। इसलिए जिसके पास थोड़ा तार है, उसके केस में हम पता लगायेंगे। अगर कोई एक इंच तार भी काटे, तो उसको तो सजा मिलेगी ही, लेकिन हमारा यह प्रावधान उनके लिए है, जिनके पास इकट्ठा तार मिलेगा और उनको हम सजा दे सकेंगे।

[श्री शंकर दयाल शर्मा]

हमने सिर्फ यही व्यवस्था नहीं की है कि जिसके पास तार हो, बल्कि इस सम्बन्ध में जो कन्वेयन्स या व्हीकल इस्तेमाल हो, उनके सम्बन्ध में भी कार्यवाही की जायेगी। जैसा कि आम तौर पर होता है, ओनस उन पर रहता है, जिम्मेदारी उनकी है कि वे सिद्ध करें कि उन्होंने गुड फेथ में ऐसा किया है गुड फेथ के बारे में इंडियन पीनल कोड में साफ़ कहा गया है

Nothing is said or done in good faith, if it is done without due care and caution.

इसलिए अगर कोई पूरा ध्यान न दे, तो वह जिम्मेदार हो जाता है। कहा गया है कि पूरी कार, पूरा ट्रक ले ली जायेगी। हमने इस बारे में यह प्रावधान किया है :—

"... to pay in lieu of the confiscation of the conveyance or the animal a fine not exceeding the market price of the conveyance or the animal on the date of the seizure thereof or the value of the telegraph wires in relation to which the contravention has been made, whichever it less."

इससे साफ़ है कि कन्वेयन्स के दाम या तार के दाम, जो उनमें से कम होगा, उतना ही उसको फ़ाइन के रूप में देना होगा। अगर तार की कीमत 100 रुपया है तो 100 रुपया, अगर दस हजार है तो दस हजार रुपया, और अगर पचास हजार या एक लाख रुपए के तार गिरे हैं, तब हम सिर्फ ट्रक लेंगे। जब बहुत बड़ी मात्रा में तार जाते हैं; तो उसको देखना चाहिए। हम यह मानकर चलेंगे कि अगर कोई ट्रक वाला तार ले जाता है, तो वह जानता है। उस पर जिम्मेदारी होगी कि वह सिद्ध करे कि वह इसमें शामिल नहीं है और उसने पूरी एहतियात बरती थी। इसलिए इसमें परेशानी होने की बात नहीं है।

18 hrs.

यह सुझाव दिया गया है कि कैद और जुर्माना दोनों रखे जायें—"एंड" होना चाहिए, "और" नहीं होना चाहिए। मेरे मन में यही बात आती है कि यह होना चाहिए। लेकिन हमें भाई जीज० के सुझाव पर गौर करना है। जैसा कि एक दूसरे बिल के सिलसिले में कहा गया है, अदालतों का यह मामला रहता है कि जब सजा देना जरूरी हो, तब वे अक्सर छोड़ देते हैं। इस केस में हमने यह किया है कि इतना कम से-कम होगा, और अगर इससे कम करे, तो उनको उसकी वजह बतानी होगी। उस में सब से बड़ी रोक यह रहती है कि वजह बताने के बाद अगर उन्होंने कोई लापरवाही की है, तो सुपीरियर कोर्ट उनको तम्बीह कर के रिमार्क कर देती है।

जहां तक इस संबंध में सहयोग का प्रश्न है, उसमें कोई दो रायें नहीं है कि इस चोरी को पकड़ने के लिए सहयोग की अत्यन्त आवश्यकता है और हम इसमें बराबर लोगों का सहयोग चाहेंगे। हमको राज्य शासनों का सहयोग चाहिए, क्योंकि हमारे पास कोई मशीनरी नहीं है, जिससे हम उन लोगों को पकड़ सकें। इसके साथ-साथ हमको जनता का भी सहयोग चाहिए। सब का सहयोग मिलने पर ही यह काम हो सकेगा।

जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, हम इस बात में फ़र्क नहीं करते कि कौनसा व्यक्ति किस पार्टी का है। जो जुर्म करें, उसको सजा मिलेगी ही। अदालत किसी को छोड़ दे या उस के बारे में सबूत न मिले, तो हमारा विभाग उसमें ज्यादा नहीं कर सकता है। जहां तक हमारा ताल्लुक है, चोरी होने पर हम उसकी शिकायत दर्ज करते हैं। लेकिन

राज्य शासन उस को देखता है। इसमें कोई अन्तर करने का सवाल ही नहीं है। अगर आप मुझे इजाजत दें, तो मैं उस व्यक्ति को कांग्रेस-जन नहीं मानूंगा, जो चोरी करता हो, किसी की भी चोरी करता हो, व्यक्तिगत चोरी करता हो या शासकीय धन की चोरी करता हो, उसके लिए कड़ी सजा होनी चाहिए।

यह कहा गया है कि जब से टैलकाम और पोस्टल का बंटवारा हुआ है, तब से कम्प्लेंटेस बढ़ने के बजाय कम हो गई है। इसमें पूरा साल भर नहीं हुआ है। इसको करने में हमारा लक्ष्य यही था कि इसके फलस्वरूप कुछ चुस्ती आयेगी और कुछ काम अच्छा हो सकेगा। हम इसको निश्चित रूप से देख रहे हैं।

जहां तक केरल का सम्बन्ध है, श्री रवि की बात से ऐसा लगा कि शायद उनको ख्याल है कि केरल की तरफ़ कुछ दुर्लक्ष्य किया जा रहा है। इस समय जो आंकड़ मुझे मिल सके है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं। उनसे पता चलेगा कि केरल की तरफ़ दुर्लक्ष्य करने का सवाल नही है, बल्कि केरल को टेली-कम्युनिकेशन्ज में दूसरे राज्यों से कही ज्यादा मिला हुआ है। एक हजार की आबादी पर केरल में 2.98 टैलीफ़ोन हैं, जब कि राजस्थान मे 1.99, उड़ीसा में .96........

सभापति महोदय : मंत्री महोदय अभी कितना समय और लेंगे ?

डा० शंकर दयाल शर्मा : 5, 7 मिनट।

MR. CHAIRMAN: I suppose the House will sit a few minutes more and dispose of this business:

SOME HON. MEMBERS: Yes.

डा० शंकर दयाल शर्मा : ... आन्ध्र में एक हजार की आबादी पर 2.18, कर्नाटक में 2.76 और मध्य प्रदेश में 1.28 टैलीफोन हैं।

यही नहीं कि मैंने सिर्फ आबादी के हिसाब से कह दिया है; 100 स्क्वैयर माइल पर केरल में 164 टैलीफ़ोन हैं, जब कि मध्य प्रदेश में 12, राजस्थान में 14, उड़ीसा में 14, आन्ध्र प्रदेश में 34 और कर्नाटक में 42 हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश की स्थिति इससे कोई खास अच्छी नहीं है। वहां 14 और 20 के बीच में होंगे।

जहां तक इस बात का प्रश्न है कि एक पी० सी० ओ० से कितना एरिया सर्व होता है, केरल में 240 स्क्वैयर माइल पर एक पी० सी० ओ० है, जब कि मध्य प्रदेश में 2192 किलोमीटर में, राजस्थान में 769 किलोमीटर में, आन्ध्र में 490 किलोमीटर में और कर्नाटक में 282 किलोमीटर में एक पी० सी० ओ० है। टेलीफोन एक्सचेंज के सम्बन्ध में भी यही हालत है।

श्री रवि को मालूम है कि ट्रंक आटोमैटिक एक्सचेंज गत एक वर्ष में सिर्फ एक जगह लगी हैं, और वह जगह केरल में है। पहले शिकायत की गई थी कि केरल से बात नही हो पाती है। अब केरल के लिए एस० टी० डी० हो गया है। रात के वक्त एस० डी० डी० से सीधे सीधे बात कर सकते हैं। टेलीफोन आपरेटर, जिन से श्री रवि आज-कल कुछ नाराज हैं, बीच में नहीं आते हैं।

जो शिकायतें हैं, उन में से बहुत सी सही हैं, यह मुझे मालूम है। इसमें कोई दो रायें नहीं हैं कि टेली-कम्युनिकेशन्स की प्रगति के लिए, ... के लिए, ... करना है। ... में भी कोई दो रायें नहीं है कि हमारे ... पहले

[डा० शंकर दयाल शर्मा]

थे। उन में थोड़ा सुधार पहले आया था। लेकिन इमर्जेन्सी आने के बाद उन के कामों में काफी सुधार आया है, क्योंकि वे स्वयं मानते हैं कि जो कुछ हुआ है, वह उनके हित में है, इसलिए वे स्वयं ज्यादा मेहनत से काम कर रहे हैं, और उसके नतीजे भी सामने आये हैं। दिल्ली में ही ट्रंक-काल के मेच्युर होने की परसेंटेज 20 से ज्यादा बढ़ गई है।

हमारे यहां बहुत से तार डाक से जाया करते थे। उसके कारणों के बारे में हम ने कर्मचारियों और उन की यूनियनों से चर्चायें कीं, और उसके बाद हम ने रास्ता निकाला। पता चला कि सी० टी० ओ० से बहुत ज्यादा तार जाते थे। उस का कारण यह पता लगा कि अक्सर शाम के समय गवर्नमेंट के सब विभागों और बैंकों के तार वहां पहुंच जाते थे—सब 5 बजे के बाद पहुंचते थे। नतीजा यह होता था कि वे सब के सब बुक हो जाते थे, क्योंकि उन को प्राथमिकता मिलती है। हमने सब को लिखा है कि इस से कोई फायदा नहीं है, वे हमारी क्विक मेल सर्विस का उपयोग करें, जिससे उन का भी पैसा बचेगा और टेलीग्राफ से दूसरे लोगों को फायदा हो सकेगा। और दूसरे इससे कोई लाभ इसलिए नहीं होता कि रात को तार पहुंचा अर्जेन्ट और इम्मीडिएट उससे कोई फायदा नहीं हुआ। आप या तो यह कीजिए या जैसा हम ने आप को टेलीप्रिन्टर दे रखा है उस के जरिए से इन चीजों को पहुंचा दीजिए। उस का भी कुछ असर हुआ। फिर जो छुट्टी लेने के कुछ तरीके थे गलत सर्टिफिकेट दे कर उस पर भी हम ने और हैल्थ मिनिस्ट्री ने रोक लगाई। नतीजा यह हुआ कि अब जो तार डाक से जाते थे उनकी संख्या में अनहमैरिजिनेबल कमी आई है। बहुत ज्यादा कम हो गए हैं। मैं समझता हूं

कि अगर उस को परसेंटेज में लिया जाय तो पहले के मुकाबिले में शायद 80 फीसदी तक सुधार हो चुका है। एग्जैक्ट फिगर तो मैं नहीं दे सकता हूं, लेकिन जो रिपोर्टस मैंने बराबर बीकली ली हैं उन में बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। तो एमर्जेंसी के बाद चीजों को सुधारने की बात हुई है।

एक बात और कही गई कि पिछड़े इलाकों का ख्याल रखा जाए। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ एक मुसीबत है कि हमारा कामर्शियल डिपार्टमेंट माना गया है। इस में हमारा जो भी विकास है वह हम अपनी आमदनी के अंदर ही कर सकते हैं। पंच वर्षीय योजना में हमारे लिए कोई अलग से रुपया नहीं मिलता है। जितनी हम आमदनी करेंगे उसी में से जितना हम खर्च करेंगे वह करना पड़ेगा। सिर्फ इसमें एक फारेन एक्सचेंज का जो कन्टेन्ट है वह हम को जनरल बजट से मिलेगा। हम को इस के अलावा जनरल पूल में भी कुछ कान्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। इस कारण से स्वभाविक है कि हमें उन स्थानों को प्राथमिकता देनी होती है जहां पर कि रिटर्न होता है। आप लोग नाराज होते होंगे, हमारे यहां पत्र आते हैं और मेरा प्रयास होता है कि हर पत्र का उत्तर मैं दूं। अगर मालूमात के आने में देर होती है तो यह बात दूसरी है। लेकिन मुझको जैसे ही पत्र मिलता है मैं उस को एकनालेज करता हूं और प्रयास करता हूं, बराबर मैं ने आफिसर लगाए हैं इस बात के लिए कि वह इस का पीछा करें कि पार्लियामेंट के मेम्बर के जो पत्र आए हैं उनके उत्तर गए या नहीं गए। देर हुई तो क्यों हुई? अगर ज्यादा देर हुई तो उस आफिसर को तम्बीह दी जाय।

यह कहा गया है कि किसी मेम्बर पार्लियामेंट ने किसी की सिफारिश की और उसकी वह से किस व्यक्ति को वंचित करने का

प्रयास किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि अगर ऐसा है तो हम बराबर उसको रोकेंगे क्योंकि मैंने यह कभी नहीं माना कि पार्लियामेंट के मेम्बर्स, जो लोगों के जेनुइन दिक्कतें है वह हमारे सामने न लायें। हम उसका स्वागत करते है। ऐसी बात तो बिल्कुल होने वाली नहीं है। जो भी आप सुझाव देते है अलग अलग जगहों के उनको हम देखते है। आपके जो पत्र आते है उनमें अक्सर हमें लिखना पड़ता है कि यह अनरेम्युनरेटिव है। और अनरेम्युनरेटिव होने पर हमारी कठिनाई है क्योंकि अगर हम यह करते रहें तो हम आगे बढ़ा नहीं सकते। वैसे अगर हमको रुपया मिले तो हम इस को भीट कर सकते है।

टेलीफोन की डिमांड्स बढ़ती जा रही है। अभी मैं गया था तो बम्बई में मुझे बताया गया कि अकेले बम्बई में 1 लाख 86 हजार की टेलीफोन की वैटिंग लिस्ट है। दिल्ली में शायद 1 लाख 8 हजार की है। हम इन चीजों को सुधारने का काम कर रहे है।

जहां तक इक्विपमेंट की बात है हम इक्विपमेंट के प्रोडक्शन को बढ़ाने का प्रयास कर रहे है। हम यह भी प्रयास कर रहे है कि जो हमारे प्रोडक्शन यूनिटस है उनमें स्पेयर्स का एक बड़ा परसेंटेज निश्चित रूप से बने ताकि वह वहां दिया जा सके। जहां तक कि स्पेयर्स पार्ट्स का सवाल है, चीजों का सवाल है, केरल तो दूसरे राज्यों के मुकाबले थोड़ा बेटर पोजीशन में है क्योंकि हमारा आई० टी० आई० का जो मेन कारखाना है वह केरल में है और दूसरे केरल को यह भी शिकायत नहीं हो सकती, एक दूसरा कारखाना पालघाट में है। पालघाट में एलैक्ट्रोनिक पी० ए० बी० एक्स० है। तो हम पूरा पूरा प्रयास कर रहे है कि ये चीजें हों।

दिल्ली की बात एक कह कर मैं खत्म करूंगा। यहां पर हमने टीम्स बनाई है। यह हम सब जगह करने वाले हैं। यहां हमने एक्सपर्टस की टीम्स बनाई हैं जो हर ऐक्सचेंज में जायेंगी, देखेंगी कमियों को और जो भी वहां कमी होगी, उसको केवल बताएंगी ही नहीं उन चीजों को ठीक करने का प्रयास भी करेंगी। छ टीमें यहां बनाई गई हैं। तीन टीमें एक्सचेंज को देखने के लिए, तीन ट्रांसमिशन को देखने के लिये और एक जो हमारा बिल्डिंग है उसको देखने के लिये होगी। उनका हमने एक टाइम शेड्यूल बनाया है। उस टाइम शेड्यूल के बाद वह आयेंगे। आशा है कि उसके नतीजे में थोड़ी एम्प्रूवमेंट जरूर आयेगी। कुछ वर्कर्स का कोआपरेशन मिलने की वजह से और कुछ इन प्रयासों से हम कुछ ज्यादा अच्छा काम कर सकेंगे। हम आपके सझावों का हमेशा स्वागत करते है। जो भी पार्लियामेंट के मेम्बर चर्चा करना चाहे राज्य की या दूसरी किसी जगह की, हम उनके साथ चर्चा करते है। वह अपनी कठिनाइयां बताते है। लेकिन जब भी चर्चा या जो भी सुझाव होते है चाहे वे किसी भी दल के हों, हम उनको अपने वश भर ठीक करने का प्रयास करते हैं। यही आप आश्वासन चाहे तो मैं दे सकता हूं और यही मैं कह सकता हूं क्योंकि बात इतनी लम्बी है कि सब जगह इसकी परेशानी है।

एक बात और कह कर खत्म करूंगा। यही नहीं, जो भी विकसित देश है उनकी हालात के बारे में मैं एक बात सिर्फ बता दूं कि अभी योरोपा एक निकला है, उसमें एक मजाक आया था, पूरा एक आर्टिकल था टेलीकम्युनिकेशन और पोस्टल सर्विसेज के ऊपर, उसमें लिखा था कि फ्रांस में एक कहावत है, वहां यह कहा जाता है कि आधे फ्रांस के लोग तो उनके यहां टेलीफोन लग जाय इसका इंतजार कर रहे हैं और बाकी आधे लोग डायल टोन का इंतजार कर रहे हैं। यानी हम बुरे है, हमको ठीक होना चाहिये...

सभापति महोदय : कृपया उसका अनुसरण यहां न हो ।

डा० शंकर दयाल शर्मा : यह मैं उनको बुरा बताने के लिये नहीं कह रहा हूं । मैं यह भी जानता हूं, और मैं यह बता दूं कि फ्रांस की टेलीकम्युनिकेशन सर्विस हमसे बेटर है । मैं यह नहीं कहता कि हम उन से अच्छे हैं । लेकिन यह मैंने इसलिए बताया कि यह कठिनाई रहती है । हम अपना प्रयास कर रहे हैं । और आपका सहयोग मिलेगा तो आशा करते हैं कि चीज सुधरेंगी और टेलीफोन वायर की थेफ्ट भी कम होगी । जितनी दिलचस्पी आपने इसमें दिखाई है उसके लिये मैं आप सबका आभारी हूं ।

सभापति महोदय : प्रश्न है--

"कि तारयंत्र तार (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में विचार किया जाए "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

..The motion was adopted.

सभापति महोदय : अब हम खण्डश. विचार आरम्भ करेंगे ।

खण्ड 2 पर कोई संशोधन नहीं है ।

"प्रश्न है कि खण्ड 2 विधेयक का अंग माना जाए" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

..The motion was adopted.

Clause 2, was added to the Bill.

Clause 3— (*Amendment of section 5.*

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

Page 1, line 17,—

for "five" *substitute* "three" (3)

Page 1, line 17,—

for "or with fine or with both," *substitute* "and fine" (4)

Page 2, line 2,—

for "one year" *substitute*—"six months" (5)

सभापति महोदय, टेलीग्राफ तार की चोरी को मैं महापाप मानता हूं भारत की परम्परागत भाषा के अनुसार । इसका समर्थन कोई नहीं कर सकता और उसके लिये कठोर से कठोर सजा की व्यवस्था होनी चाहिये । मैं बराबर इस हक में रहा हूं कि सजा कड़ी से कड़ी दी जाय । उसके बावजूद मैंने संशोधन पेश किया है कि सजा में कमी की जाय । उसे मैंने पांच साल से तीन साल करने की कोशिश की है । मैं इसे छोड़ सकता हूं अगर आप "या" को खत्म करने को तैयार हों । यानी आप पांच साल सजा दे रहे है, पांच साल सजा देंगे या जुर्माना करेंगे तो दस रुपया भी जुर्माना हो सकता है या ज्यादा से ज्यादा आप एक हजार जुर्माना करेंगे, यह व्यवस्था आपने की है । फाइव इयर्स और विद फाइन यह रख रहे हैं । फाइन को आपने उसमें व्याख्या भी नहीं की है कि क्या होगा । तो मैं इस ख्याल का हूं कि अब वह समय आ गया है कि आप केवल सजा की बात ही कीजिये और जुर्माना की बात कीजिये तो 'या' नहीं कह करके सजा और जुर्माना दोनों की बात कीजिये । यानी पांच साल की सजा भी हो और जुर्माना भी हो । लेकिन आप इसको मान नहीं रहे हैं । इसीलिये मैंने कहा कि तीन साल और जुर्माना जरूर कीजिये । लेकिन मैं तीन साल को छोड़ने के लिये तैयार हूं । केवल आप 'या' को खत्म करके और कहिये । इतना ही मेरा संशोधन है । और यह आप से बराबर कीजिये आप ।

इसके सिलसिले में कहा इस तरह की व्यवस्था आपको जरूर करनी चाहिये कि चोरी करने में जो सहायक होते हैं, पुलिस के लोग चोरी करवाते है, आपके विभाग के लोग चोरी करवाते है, उनको भी जरूर कुछ सजा की व्यवस्था होनी चाहिये । इस बात की व्यवस्था मैंने इस बिल में कहीं नहीं देखी । इसलिये मेरा यह बड़ा सिम्पल संशोधन है । इसको मंत्री महोदय मान लें । एक संशोधन मैं वापिस लेने को तैयार हूं संशोधन नं० 3, यानी पांच के बदले तीन करने का, लेकिन 'या' को आप खत्म कर दीजिये, आप "और" कहिये यानी सजा और जुर्माना, मैं उसके लिये तैयार हूं । नहीं तो, मै अपने संशोधन पर वोटिंग चाहूंगा । संशोधन नं० 4 को मैं चाहूंगा कि आप मान लीजिये । 3 पर मै अड़ने को तैयार नहीं हूं क्योंकि मैं कठोर सजा का पक्षपाती हूं । लेकिन 4 तो मानिये ।

डा० शंकर दयाल शर्मा : सभापति महोदय, शास्त्री जी ने बड़े जोर से तर्क दिया । एक तरफ पांच को तीन करने की बात, यानी सजा कम करने की बात थी और एक तरफ सख्त करने की बात थी । लेकिन यहां पर बात यह है कि यह प्रावधान तो पुराने हैं, चले आ रहे हैं, बराबर और हमने इसमें कोई खास तब्दीली नहीं की है । हमने तब्दीली तो सिर्फ यह की है कि पहले आफ़ेंस पर हमने प्रावधान किया है कि एक साल या 1 हजार जुर्माना । अगर इससे कम करेंगे तो उन्हें इसको लिखित में देना होगा । यानी उनको अपने आर्डर में इसको बताना होगा कि क्यों कम दे रहे हैं । तो मेरी यह प्रार्थना है कि जो चीज मेन ऐक्ट में अब तक चली आ रही है उसमें हम कम करने की या दूसरी बात अभी न करें । अभी जो आई० जी पुलिस वगैरह ने हमको बताया है उसको हमने किया है ।

एक बात और है कि जो चोरी में सहायता करे . . . .

श्री रामावतार शास्त्री : पांच साल के बारे में भी दिया है संशोधन । वह अलग है । एक साल वाला अलग है ।

डा० शंकर दयाल शर्मा : शास्त्री जी, 'ऐंड' और 'आर' दोनों चले आ रहे हैं । 'ऐंड' भी वह दे सकते हैं, 'आर' भी दे सकते हैं ।

अबेटर का, सहायक का जहां तक प्रश्न है वह तो क्रिमिनल ला का उसूल है । उसके मुताबिक जो भी अबेटर है उसको सजा मिलती है । इसका अलग से प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है । वह तो इसमें है ही । मैं आशा करता हूं, शास्त्री जी, इस बात को देख कर कि हमें इस काम को आगे बढ़ाना है, इस को ज्यादा प्रेस नहीं करेंगे ।

इस मौके पर हमारे जो भण्डारा के एम० पी० श्री हेड़ाऊ हैं, उन्होंने जो कहा है उसके सम्बन्ध में मैं उनको बता दूं, मैंने पहले भी साफ़ कर दिया था कि हमारे तार कहीं निकले हैं, तो इसको जरूर देखेंगे, लेकिन रिपोर्ट करने के बाद कार्यवाही प्रदेश शासन करता है । इसके आगे हमारा काम नहीं है । जो लोग ज्यादा इस तरह की कार्यवाही करते है, उनके खिलाफ मीसा का प्रयोग हो, तो हम इस का स्वागत करेंगे ।

श्री राम हेडाऊं (रामटक) : शासन ने उस केस को दबा दिया है । इस केस की एनक्वायरी करवा ली जाय तो मामला सामने आ जाएगा ।

सभापति महोदय : शास्त्री जी, क्या आप अपनी तीनों अमेंडमेंट्स वापिस लेना चाहते हैं ?

श्री रामावतार शास्त्री : मैं अमेंडमेंट संख्या 4 को प्रैस करूंगा, लेकिन अमेंडमेंट संख्या 3 और 5 को वापस लेना चाहता हूं ।

Amendments Nos. 3 and 5 were, by leave, withdrawn

सभापति महोदय : अमेंडमेंट सं० 4—प्रश्न है —

Page 1, line 17,—

for "or with fine, or with both," substitute—
"and fine," (4)

संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived

सभापति महोदय : प्रश्न है—

"खण्ड 3 विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

Clause 3 was added to the Bill.

सभापति महोदय : खण्ड 4, 5 तथा 6 पर कोई संशोधन नहीं है ।

प्रश्न है—

"खण्ड 4, 5 तथा 6 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted

Clauses 4, 5 and 6 were added to the Bill

Clause 1—(*Short title*)

सभापति महोदय : खण्ड 1—इस पर मंत्री जी का संशोधन सं० 2 है । क्या आप इसे प्रस्तावित करना चाहते हैं ?

डा० शंकर दयाल शर्मा : मैं प्रस्ताव करता हूं—

Page 1, line 4,—

for "1974" *substitute* "1975" (2)

यह बिल्कुल कासीक्वैंशल संशोधन है, अतः इन्हें स्वीकार किया जाये ।

Page 1, line 4,—

for "1974" *substitute* "1975" (2)

संशोधन स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

सभापति महोदय : प्रश्न है—

"खण्ड सं० 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

Enacting Formula

सभापति महोदय : "इनैक्टिंग फ़ार्मुला (अधिनियमन सूत्र) पर मंत्री महोदय का संशोधन संख्या 1 है ।

क्या आप इसे प्रस्तावित करना चाहते हैं ?

डा० शंकर दयाल शर्मा : मैं प्रस्ताव करता हूं—

Page 1, line 1,—

for "Twenty-fifth" *substitute* "Twenty-sixth" (1)

सभापति महोदय : प्रश्न है—

Page 1, line 1,—

for "Twenty fifth" *substitute* "twenty sixth" (1)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

सभापति महोदय : प्रश्न है—

"अधिनियम के सूत्र (इनेक्टिंग फारमूला) संशोधित रूप मे, स्वीकार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

सभापति महोदय : प्रश्न है—

"नाम (लांग टाइटल) विधेयक का अंग बनं ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

The Title was added to the Bill.

डा० शंकर दयाल शर्मा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस बिल को संशोधित रूप मे पास किया जाए ।

सभापति महोदय : प्रश्न है —

"यह विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : सदन कल 11 बजे तक के लिये स्थगित किया जाता है ।

18.25 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, July 31, 1975/Sravana 9, 1897 (Saka).

GMGIPND—M—1185 L S—978